JANUARY 2024

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Warli Paintings

Hit & Run

Nuclear Installations

K Shaped Economy

Eurasian Otter

Einstein Probe

& More

हिंदी

TOPPER'S RECOMMENDED

BEST CHOICE

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

Extended Portal access upto 2026 Prelims

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Current Affairs Daily Practice Test (Prelims & Mains)

Super 100 (Mentored by Mohan Sir & Toppers)

Daily Comprehensive Classes

Personality Test Modules.

(For Freshers)

Prelims Revision Handouts & VAN

Group Discussions & Doubt Clearing Platform

Personalised Mentorship and Feedback

Analyse Learn Perform (ALP)

& Much more......

GURUKUL FOUNDATION 2025

Above & Beyond Regular Coaching

ADMISSION OPEN

Bengaluru · Online

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

विषय-सूची

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (ई-एससीआर) परियोजना
- हिट-एंड-रन के विरुद्ध नया कानून
- हाटी समुदाय
- साइबर किडनैपिंग
- शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)
- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)
- राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची
- डाकघर अधिनियम, 2023
- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023
- पीएम गतिशक्ति
- इ-डेट आयोग (Idate Commission)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)
- परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर द्विपक्षीय समझौता
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
- मालदीव
- ग्लोबल गुड के लिए गठबंधन: लैंगिक समानता और समानता
- भारत और फ्रांस

अर्थव्यवस्था

- लघु वित्त बैंक (SFB)
- आयकर रिटर्न
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)
- ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना (ZED)
- प्रवर्तन निदेशालय
- नम्मा यात्री
- विश्व आर्थिक मंच (WEF)
- तेल की कीमतें
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
- बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवोल्यूशन)
- के-शेप्ड इकोनामिक रिकवरी
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)

भूगोल

- अदन की खाड़ी
- सोमालिया
- कोरापुट काला जीरा चावल
- सिमिलिपाल काई चटनी
- लांजिया सौरा पेंटिंग
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान
- नयागढ़ कांतिमुंडि बैंगन
- ढेंकनाल माजी

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- यूरेशियन ऊदबिलाव
- लाओखोवा और बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य
- बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (बीआरटी) टाइगर रिजर्व
- कॉनजॉइन्ड सिल्वरलाइन
- अफ्रीका चीता
- सेन्ना स्पेक्टाबिलिस
- अफ़ीम
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- ई – कचरा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन
- R21 वैक्सीन
- **आइंस्टीन प्रोब**
- एक्सोप्लैनेट WASP-121
- नासा की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला
- चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर (SLIM)
- सॉवरेन AI

हेल्थ

- वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस
- केटामाइन

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- वारली पेंटिंग
- दिव्य कला शक्ति
- श्रीमुखलिंगम मंदिर
- बोब्बिली वीणा
- कपडगंडा शॉल
- जगन्नाथ मंदिर
- महायोगी वेमना
- अमृत उद्यान
- कौशल भवन
- हज़रत निज़ामुद्दीन औलियादरगाह

डिफेन्स एंड सिक्योरिटी

- CV-22B ऑस्प्रे विमान
- डेजर्ट साइक्लोन 2024
- INS चेन्नई
- सेना दिवस
- अभ्यास डेजर्ट नाइट
- INS सुमित्रा

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ, संगठन

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
- नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम
- सागर परिक्रमा
- स्मार्ट 2.0
- "पृथ्वीविज्ञान"
- **स्वदेश दर्शन 2.0 योजना**
- अनुभव पुरस्कार योजना 2024
- अटल बिहारी बाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया
- अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS)
- प्रसादम
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- पीएम-ईबस सेवा योजना
- स्टार्टअप रैंकिंग 2022
- आयुष दीक्षा
- आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब – भीष्म
- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
- 'वैभव' फेलोशिप
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-2022
- पीएम यशस्वी योजना

स्पोर्ट्स

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023

विविध

- विश्व ब्रेल दिवस
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस

MAINS

PAPER 1

- महिला नेतृत्व में विकास
- सशस्त्र बलों में महिलाएं
- मंदिर वास्तुकला की नागर शैली
- शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन (एबीसीपी)

PAPER 2

- शैक्षिक केन्द्रों में आत्महत्या के मामले
- राजद्रोह (SEDITION)
- भारत में लेखापरीक्षा की भूमिका
- एक राष्ट्र-एक चुनाव (ओएनओई)
- भारत-केन्या संबंध
- भारत-बांग्लादेश संबंध
- भारत-रूस संबंध

PAPER 3

- टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली
- कैंसर का पता लगाने और उपचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका
- प्रोजेक्ट टाइगर
- उद्योग-अकादमिक सहयोग
- भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
- चंद्रयान-3

Practice Questions

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (ई-एससीआर) परियोजना

संदर्भ: हाल ही में, CJI ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की।

इस परियोजना के बारे में:-

- यह एक पहल है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उसी तरह प्रदान करेगी जैसा कि आधिकारिक कानून रिपोर्ट - 'सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स' में बताया गया है।
- **उद्देश्य:** न्याय के सभी हितधारकों, मुख्य रूप से वादियों और बार के सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, न्यायिक अकादमियों आदि के लाभ के लिए सकारात्मक बदलाव लाना।
- ई-एससीआर परियोजना पीएफ प्रारूप में उपलब्ध सत्यापन योग्य प्रामाणिक सॉफ्ट प्रतियों का इस्तेमाल करके एससीआरएस की प्रतिकृति सॉफ्ट प्रतियां प्रदर्शित करेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक सर्च इंजन विकसित किया है, जो ई-एससीआर के डेटाबेस में इलास्टिक सर्चटेक्निक्स का इस्तेमाल करता है।
- इससे सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
- ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के मोबाइल ऐप और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

अवश्य पढ़ें: प्रत्यायोजित विधान

SOURCE: THE ECONOMIC TIMES

हिट-एंड-रन के विरुद्ध नया कानून

संदर्भ: हाल ही में, सरकार द्वारा हिट एंड रन के खिलाफ नए कानून को स्थगित रखने के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त कर दी गई।

पृष्ठभूमि:-

- सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की जगह नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लाने के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों के संघों ने तीन दिवसीय हड़ताल वापस ले ली है।

हिट-एंड-रन के विरुद्ध नये कानून के बारे में:-

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का नया कानून धारा 106(2) के तहत आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) का स्थान लेता है।
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- इसके तहत, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनता है और फिर पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना निकल जाता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- बीएनएस ने "लापरवाही से मौत का कारण" के तहत दो अलग-अलग श्रेणियां स्थापित की हैं।
- पहली श्रेणी: किसी भी जल्दबाज़ी या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण मृत्यु का कारण बने ऐसे पते जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आते।
    - अपराधियों को पांच साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- दूसरी श्रेणी: तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत होने से संबंधित है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है।
    - अपराधियों को 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- इसके विरुद्ध तर्क: परिवहन ऑपरेटरों का तर्क है कि कानून ड्राइवरों को गलत तरीके से दंडित कर सकता है और उन्हें भीड़ की हिंसा का शिकार बना सकता है, खासकर जब घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो।

MUST READ: Road to Safety

SOURCE: BUSINESS STANDARD

हाटी समुदाय

संदर्भ: हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अंततः हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की।

पृष्ठभूमि:-

- हिमाचल प्रदेश में निर्णय के कार्यान्वयन में देरी हुई क्योंकि राज्य सरकार ने 4 अगस्त, 2023 को विधि विभाग से परामर्श के बाद राजपत्र में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना के कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। ।

हट्टी समुदाय के बारे में:-

- यह एक एकजुट समुदाय है जिसका नाम कस्बों में 'हाट' कहे जाने वाले छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस, ऊन आदि बेचने की उनकी परंपरा से मिला है।
- ये कठोर जाति व्यवस्था का पालन करते हैं।
- भट्ट और खश उच्च जातियाँ हैं, और बधोई उनसे नीचे हैं, और उन्होंने अंतरजातीय विवाह को हतोत्साहित किया।
- हट्टियों को खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित किया जाता है, जो हरियाणा की खापों की तरह सामुदायिक मामलों का फैसला करती है।
- पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुम्बली की शक्ति को चुनौती नहीं दी गई है।
- औपचारिक अवसरों पर हट्टी पुरुषों के पास पारंपरिक रूप से एक विशिष्ट सफेद टोपी होती है।

अवश्य पढ़ें: जनजातियों को एसटी सूची में शामिल करना

SOURCE:THE TIMES OF INDIA

साइबर किडनैपिंग

संदर्भ: हाल ही में एक चीनी छात्र जो 'साइबर किडनैपिंग' का शिकार हुआ था, यूटा के ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पाया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- 17 वर्षीय काई ज़ुआंग के 28 दिसंबर को लापता होने की सूचना मिली थी। जब तक पुलिस ने उसका पता लगाया, चीन में उसके माता-पिता फिरौती में 80,000 डॉलर दे चुके थे।

साइबर किडनैपिंग के बारे में:-

- साइबर किडनैपिंग एक ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जहाँ 'अपहरणकर्त्ता' अपने शिकार को छिपने के लिये मना लेते हैं और फिर फिरौती के लिये अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं।
- पीड़ित को ऐसी तस्वीरें भेजने के लिए भी कहा जाता है जिससे ऐसा लगे कि उन्हें बंदी बनाया जा रहा है और उन्हें बंधा हुआ या मुंह बांधा हुआ दिखाया गया है।
- 'अपहरणकर्त्ता', हालाँकि शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित की ऑनलाइन निगरानी करते हैं।
- पारंपरिक अपहरणों के विपरीत आभासी अपहरणकर्ताओं ने वास्तव में पीड़ित का अपहरण नहीं किया रहता है।
- रोकथाम:-ऑनलाइन शेयरिंग सीमित करना, कॉलर सतर्कता, आपातकालीन संपर्क, कानून प्रवर्तन भागीदारी।

अवश्य पढ़ें:साइबर हमले

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)

संदर्भ: हाल ही में, दिसंबर 2023 महीने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर 17वीं रिपोर्ट जारी की गई थी।

पृष्ठभूमि:-

- दिसंबर 2023 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 58,016 पीजी मामले प्राप्त हुए।

इसके बारे में:-

- यह एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24x7 उपलब्ध है।

- यह एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय [MeitY]) द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (DPG) और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत विभाग DARPG द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह Google Play स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकने वाले एक स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और UMANG के साथ एकीकृत एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी नागरिकों के लिए सुलभ है।
- आईटीआईएस नागरिकों को शिकायत अधिकारी के समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर अपील की सुविधा भी प्रदान करता है।
- अपील की स्थिति को याचिकाकर्ता शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ भी ट्रैक कर सकता है।
- वे मुद्दे जिन्हें निवारण के लिए नहीं उठाया जाता है: आरटीआई मामले, अदालत से संबंधित / विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले आदि।

अवश्य पढ़ें: एआई संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन

SOURCE: PIB

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

संदर्भ: हाल ही में, गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- उद्धृत कारणों में से एक यह है कि संस्थान ने "वर्तमान मामलों के कार्यक्रमों" पर रिपोर्ट प्रकाशित की, जो अधिनियम का उल्लंघन है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के बारे में:-

- गृह मंत्रालय (एमएचए) भारत में एफसीआरए को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
- इसे वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
- कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण तथा जांच देने के लिए एफसीआरए को 2010 और 2020 में संशोधित किया गया था।

विदेशी योगदान की परिभाषा:-

- यह 'विदेशी योगदान' शब्द को परिभाषित करता है जिसमें मुद्रा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहारों के अलावा अन्य वस्तुएं और विदेशी स्रोतों से प्राप्त प्रतिभूतियां शामिल हैं।
- जबकि विदेशी आतिथ्य किसी विदेशी स्रोत से विदेशी यात्रा, बोर्डिंग, आवास, परिवहन या चिकित्सा उपचार लागत प्रदान करने के किसी भी प्रस्ताव को संदर्भित करता है।

एफसीआरए पंजीकरण:-

- जो एनजीओ विदेशी फंड प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- एफसीआरए पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हैं।
- एनजीओ द्वारा आवेदन के बाद, गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से आवेदक के पूर्ववृत्त की जांच करता है और तदनुसार आवेदन पर कार्रवाई करता है।

एफसीआरए अपवाद और निषेध:-

- निषिद्ध श्रेणियाँ: चुनाव के दौरान उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों, राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों के लिए विदेशी डोनेशन की अनुमति नहीं है।
- पात्रता मानदंड: आवेदकों को काल्पनिक नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण गतिविधियों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य उत्पन्न करने में शामिल नहीं होना चाहिए, या राजद्रोह के प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए।

महत्व:-

- एफसीआरए भारत में विदेशी डोनेशन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- यह वैध उद्देश्यों के लिए विदेशी धन के उपयोग को सुनिश्चित करता है।

MUST READ:FCRA Changes: Ease of Monitoring vs Crippling Curbs
SOURCE:THE HINDU

राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची

संदर्भ: हाल ही में, आईसीएमआर ने पहली बार वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची को संशोधित करना शुरू किया।
पृष्ठभूमि:-

- सूची में न्यूनतम नैदानिक परीक्षण शामिल हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर उपलब्ध होने चाहिए; साथ ही आईसीएमआर ने हितधारकों से फरवरी के अंत तक परीक्षणों को जोड़ने, हटाने पर सुझाव देने को कहा।

राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (एनईडीएल) के बारे में:-

- यह एक सूची है जो गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक नैदानिक परीक्षणों के प्रकार तय करने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मई 2018 में आवश्यक निदान सूची (ईडीएल) का पहला संस्करण जारी किया। यह भले ही WHO का EDL NEDL के विकास के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, भारत की निदान सूची को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं के परिदृश्य के अनुसार अनुकूलित और तैयार किया गया है।
- भारत में, डायग्नोस्टिक्स को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियामक प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।
- डायग्नोस्टिक्स (चिकित्सा उपकरण और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के तहत दवा नियमों के आधार पर एक नियामक संरचना का पालन करते हैं।
- आईसीएमआर ने डायग्नोस्टिक्स की उपलब्धता को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अनिवार्य घटक बनाने के लिए वर्ष 2019 में पहला एनईडीएल जारी किया।
- एनईडीएल को स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों - ग्राम स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए विकसित किया गया है।

महत्व:-

- इस एनईडीएल का लक्ष्य मौजूदा नियामक प्रणाली की उस कमी को पाटना है जो सभी चिकित्सा उपकरणों और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों (आईवीडी) को कवर नहीं करती है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एनआईबी)
SOURCE:THE HINDU

डाकघर अधिनियम, 2023

संदर्भ: डाकघर अधिनियम, 2023 हाल ही में अधिनियमित किया गया था।
पृष्ठभूमि:-

- 24 दिसंबर, 2023 को, भारत के राष्ट्रपति ने डाकघर विधेयक, 2023 को मंजूरी दी, इसके लिए जब भी केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की जाएगी, यह औपनिवेशिक युग के भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह लेगा।

डाकघर अधिनियम, 2023 के बारे में:-

- अधिनियमित: दिसंबर 2023
- उद्देश्य:-
  - डाक विभाग की दक्षता को आधुनिक बनाना और बढ़ाना तथा डाकघरों की उभरती भूमिका को संबोधित करना, उन्हें सेवा-वितरण संस्थानों में बदलना और बैंकिंग सुविधाओं को शामिल करने के लिए उनके कार्यों का विस्तार करना।
  - डाक सेवाओं के महानिदेशक के अधिकार को मेल सेवाओं से परे विस्तारित करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेता है।
- इसमें सरकार को पत्र संप्रेषित करने का विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा।

- डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा।
    - उसके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियाँ होंगी।
- भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के माध्यम से निर्धारित किसी भी दायित्व को छोड़कर, कोई दायित्व नहीं उठाएगा।

महत्वपूर्ण मुद्दे:-

- विधेयक इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसारित लेखों को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तियों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- अवरोधन के आधार में 'आपातकाल' शामिल है, जो संविधान के तहत उचित प्रतिबंधों से परे हो सकता है।
- विधेयक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिए दायित्व से छूट देता है।
- विधेयक किसी भी अपराध और दंड को निर्दिष्ट नहीं करता है।

जरूर पढ़ें: छोटी बचत योजनाएं

SOURCE:THE HINDU

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023

संदर्भ: हाल ही में, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जारी किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- 24 राष्ट्रीय, 20 क्षेत्रीय और 54 राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा।

स्वच्छ सर्वेक्षण2023 के बारे में:-

- स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा शहर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत 13 पुरस्कार विजेताओं को सम्मान मिला।
- पोर्ट सिटी सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया, जिसने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था।
- 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, सासवड, पाटन और लोनावला ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए।
- मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।
- वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष दो पुरस्कार जीते।
- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए शीर्ष तीन पुरस्कार जीते।
- चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफ़ाईमित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला।

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में:-

- वर्ष 2016 से MoHUA द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता एवं स्वच्छता सर्वेक्षण है।
- यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कस्बों तथा शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।
- यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दायरे में संचालित किया जाता है।

जरूर पढ़ें:स्वच्छ भारत 2.0

SOURCE:PIB

पीएम गतिशक्ति

संदर्भ: हाल ही में, पीएम गतिशक्ति ने अयोध्या बाईपास परियोजना की योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया।

पृष्ठभूमि:-

- अयोध्या बाईपास परियोजना कई जिलों में आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी।

पीएम गतिशक्ति के बारे में:-

- लॉन्च: 13 अक्टूबर, 2021

- इसमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित और शुरू की गई बुनियादी ढांचागत पहलों को एकजुट करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की परिकल्पना की गई है।
- यह बुनियादी ढांचे की अंतिम मील कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि जैसी बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल होंगी।
- महत्व:- आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाता है, समन्वित शासन, कनेक्टिविटी में सुधार करता है।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय रसद नीति

SOURCE:PIB

इ-डेट आयोग (Idate Commission)

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इडेट आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के महत्व पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- एनएचआरसी ने भारत में घुमंतू, अर्ध घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातियों के संरक्षण और भविष्य की योजनाओँ पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया।

इसके बारे में:-

- स्थापना: 2014 और नेतृत्व: भीकू रामजी इदाते।
- उद्देश्य: विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) की एक राज्यव्यापी सूची संकलित करना।
- मई 2018 में, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे तीन साल की अस्थायी अवधि के लिए गठित किया गया।
- इसे राज्यवार इन समुदायों की पहचान करते हुए, उनके विकास की स्थिति का आकलन करते हुए और उनके उत्थान के तरीकों की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें:-

- रिपोर्ट में विमुक्त खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर और सबसे दलित समुदाय कहा गया है जो सामाजिक कलंक, अत्याचार और बहिष्कार के अधीन हैं।
- आयोग ने एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है ताकि अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित एनटी/डीएनटी/एसएनटी को तीसरी श्रेणी के रूप में जोड़ा जा सके।
- एससी/एसटी/ओबीसी सूची में पहचाने नहीं गए व्यक्तियों को ओबीसी श्रेणी में निर्दिष्ट करना।
- डीएनटी, एसएनटी और एनटी के लिए कानूनी स्थिति वाला एक स्थायी आयोग बनाना।
- महत्वपूर्ण आबादी वाले राज्यों में इन समुदायों के कल्याण को संबोधित करने के लिए एक अलग विभाग बनाना।
- एनटी, एसएनटी और डीएनटी समुदायों के लिए प्रमुख समितियाँ/आयोग:-
- आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947
- अनंतशयनम अयंगर समिति, 1949
- काका कालेलकर आयोग (जिसे प्रथम ओबीसी आयोग भी कहा जाता है), 1953
- बी पी मंडल आयोग, 1980

अवश्य पढ़ें: मानवाधिकार आयोगों को और सशक्त बनाना

SOURCE:NHRC

अंतरराष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को 2.5 मिलियन डॉलर का दान दिया है।

पृष्ठभूमि:-

- एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधान मंत्री ने लोगों से हैशटैग #JanManSurvey का उपयोग करके सीधे उनके साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहा।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के बारे में:-

- स्थापना: 1950 और मूल रूप से इसका मुख्यालय बेरूत, लेबनान में था, लेकिन 1978 में इसे वियना, ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया।
- 1948 के युद्ध के बाद, UNRWA की स्थापना 8 दिसंबर 1949 के UNGA संकल्प 302 (IV) द्वारा की गई थी।
- फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या के समाधान के अभाव में, UNGA असेंबली ने UNRWA के जनादेश को बार-बार नवीनीकृत किया है, हाल ही में इसे 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है।
- एजेंसी की सेवाओं में सशस्त्र संघर्ष के समय सहित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाएं, शिविर के बुनियादी ढांचे तथा सुधार, माइक्रोफाइनेंस और आपातकालीन सहायता शामिल हैं।
- यह अपने संचालन के पांच क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, जिसमें येरूशलम का पूर्व भी शामिल है।
- फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को लगभग पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से भी कुछ धन प्राप्त होता है।

अवश्य पढ़ें: भारत, इज़राइल और फ़िलिस्तीन

SOURCE:[THE INDIAN EXPRESS]

परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर द्विपक्षीय समझौता

संदर्भ: भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर द्विपक्षीय समझौते के अनुसार परमाणु प्रतिष्ठानों की एक सूची का आदान-प्रदान किया।

पृष्ठभूमि:-

- यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक साथ किया गया था।

इसके बारे में:-

- समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए और 27 जनवरी, 1991 को लागू हुआ।
- समझौता दोनों देशों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने का आदेश देता है।
- यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 33वां आदान-प्रदान है।
- समझौते की 'परमाणु स्थापना या सुविधा' की परिभाषा व्यापक है, जिसमें सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण, पुनर्प्रसंस्करण सुविधाएं और विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।

महत्व:-

- यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक उपकरण है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु क्षमताओं के क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वास और एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देता है।
- यह दोनों देशों के बीच स्थिरता और विश्वास को मजबूत करता है।

अवश्य पढ़ें: परमाणु अप्रसार संधि की स्थिति

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना चार साल का कार्यकाल शुरू किया।

पृष्ठभूमि:-

- देश ने लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद अप्रैल में वैश्विक सांख्यिकी निकाय का चुनाव जीता था।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1946 में और मुख्यालय: न्यूयॉर्क
- यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और सांख्यिकीय मानकों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
- सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के कार्य की देखरेख करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है।
- इसका 55वां सत्र 27 फरवरी - 1 मार्च 2024 तक न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला है।
- संरचना:-आयोग के अधिकारी, जिन्हें ब्यूरो भी कहा जाता है, अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और प्रतिवेदक हैं।

सदस्य:-

- आयोग में निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं:
  - अफ्रीकी राज्यों से पाँच सदस्य
  - एशिया-प्रशांत राज्यों से चार सदस्य
  - पूर्वी यूरोपीय राज्यों से चार सदस्य
  - लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों से चार सदस्य
  - पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से सात सदस्य
- सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
- भारत आखिरी बार 2004 में सदस्य था और दो दशकों के अंतराल के बाद वापस हो गया।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

SOURCE:THE ECONOMIC TIMES

मालदीव

संदर्भ: हाल ही में, मालदीव के प्रतिनिधिमंडल ने पहली भारत-मालदीव उच्च-स्तरीय कोर समूह की बैठक में 15 मार्च, 2024 तक भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव रखा।

पृष्ठभूमि:-

- दोनों देशों के विदेशी कार्यालयों के आधिकारिक बयानों में समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध के बारे में:-

IMAGE SOURCE: worldatlas.com

- भारत और मालदीव पुरातनता से जुड़े जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं।
- इनके संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं।
- भारत 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- मालदीव में भारत की अग्रणी स्थिति है, जिसके संबंध वस्तुतः अधिकांश क्षेत्रों तक हैं।
- मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका के महत्व को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, भारत सीनासा नेट सुरक्षा प्रदाता है।
- 'इंडिया फर्स्ट' मालदीव सरकार (जीओएम) की घोषित नीति रही है।

हाल के उच्च स्तरीय आदान-प्रदान:-

- प्रधान मंत्री मोदी ने 17 नवंबर 2018 को राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के उद्घाटन समारोह में एकमात्र HoS/HoG के रूप में भाग लिया।
- विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नवंबर 2018 में भारत का आधिकारिक दौरा किया।

व्यापार:-

- भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है।
- मामूली शुरुआत से बढ़ते हुए, वर्ष 2020 में भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 213.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें व्यापार संतुलन काफी हद तक भारत के पक्ष में रहा।

रक्षा सहयोग:-

- भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। (भारत-मालदीव रक्षा संबंध)
- अप्रैल 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए।

पर्यटन:-

- भारत 2022 में मालदीव पर्यटन के लिए शीर्ष बाजार बना रहा और 240,000 आगमन के साथ 14% से अधिक पर हावी रहा।

मालदीव में परिचालन:-

- ऑपरेशन कैक्टस 1988: भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की है।
- ऑपरेशन नीर 2014: पेयजल संकट से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को पेयजल आपूर्ति की।
- ऑपरेशन संजीवनी: भारत ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की।

अवश्य पढ़ें: भारत-मालदीव संबंध

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

ग्लोबल गुड के लिए गठबंधन: लैंगिक समानता और समानता

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने दावोस में 54वीं वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए "ग्लोबल गुड के लिए गठबंधन: लैंगिक समानता और समानता" की स्थापना की।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी मौजूद रहे।

इसके बारे में:-

- मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- इस गठबंधन का विचार जी20 नेताओं की घोषणा और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता से उभरा।
- इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है।
- गठबंधन बड़े वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए G20 नेताओं की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगा, जो कि एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों और G20 ढांचे के तहत पहल, अन्य बातों के साथ-साथ बिजनेस 20, महिला 20 और G20 एम्पावर के अनुसरण में होगा।
- गठबंधन ने मास्टरकार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, बायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएमडी लॉज़ेन और उद्योग के 10,000 से अधिक भागीदारों सहित उद्योग जगत के नेताओं से समर्थन प्राप्त किया है।

महत्व:-

- यह पहल SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), 5 (लैंगिक समानता और सशक्तिकरण), 17 (विकास के लिए वैश्विक भागीदारी) सहित और अधिक कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

अवश्य पढ़ें: फ़ायरएड पहल

SOURCE:TIMES OF INDIA

भारत और फ्रांस

संदर्भ: हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति का स्वागत किया।

पृष्ठभूमि:-

- राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मैक्रॉन का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि दो देशों के नेताओं का एक-दूसरे के राष्ट्रीय दिवस परेड और समारोहों में सम्मानित अतिथि बनना एक ऐतिहासिक क्षण है, और हमारी दोस्ती की गहराई और हमारी साझेदारी की शक्ति का प्रतीक है।

भारत और फ्रांस संबंधों के बारे में:-

- भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं।
- राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित किए गए और 1998 में रणनीतिक स्तर पर उन्नत किए गए।

रक्षा:-

- आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक और तकनीकी आधार के विकास में फ्रांस भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है।
- भारत और फ्रांस तीसरे देशों के लाभ सहित उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- फ्रांसीसी मदद से भारत में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2005 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- 36 राफेल विमानों के लिए सरकार से सरकार के बीच समझौता हो गया है।

आर्थिक:-

- वर्ष 2021-22 में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार।
- फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:-

- पहली बार, दोनों देशों ने 2018 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण पर हस्ताक्षर किए।
- जहां तक परमाणु ऊर्जा का सवाल है, दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के जैतापुर में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु पार्क के संयुक्त निर्माण में प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।
- लगभग एक दशक पहले 9.6 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले छह ईपीआर (यूरोपीय दबावयुक्त रिएक्टर) परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) और अरेवा के बीच बातचीत चल रही है।

पर्यावरण:-

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।
- फ्रांस ने विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं के लिए 2022 तक अतिरिक्त $861.5 मिलियन की पेशकश की।

द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास:-

- अभ्यास शक्ति (सेना)
- अभ्यास वरुणा (नौसेना)
- अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)
- आईएमईएक्स 22

अवश्य पढ़ें: अभ्यास 'वरुण' 2023

SOURCE:PIB

अर्थव्यवस्था

लघु वित्त बैंक (SFB)

संदर्भ: हाल ही में लघु वित्त बैंक (एसएफबी) अभियान शुरू किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को एसएफबी के बिजनेस मॉडल की सफलता को उजागर करना है।

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के बारे में:-

- ये वे वित्तीय संस्थान हैं, जो देश के असेवित और बैंक रहित क्षेत्र को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत न्यूनतम भुगतान पूंजी- 100 करोड़ के साथ एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।
- इनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात - जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 15% होता है।
- विदेशी शेयरधारिता को भुगतान पूंजी के 74% तक सीमित किया गया।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) 24% से अधिक नहीं हो सकता।
- कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 75% की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की आवश्यकता है।

पात्रता मापदंड:-

- बैंकिंग और वित्त में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/पेशेवर आरबीआई की मंजूरी के साथ लघु वित्त बैंक शुरू कर सकते हैं।
- निजी क्षेत्र में मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एमएफआई), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) है।
- भारतीय निवासी और जिनके पास कम से कम पांच वर्षों की अवधि तक अपना व्यवसाय चलाने की उपलब्धि का सफल रिकॉर्ड है, उन्हें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए।
- छोटे वित्त बैंकों की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है।

कार्य:-

- छोटी जमा राशि लेना और ऋण वितरित करना।
- म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और अन्य सरल तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पाद वितरित करना।
- अपने कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना।
- एकल उधारकर्ता के लिए अधिकतम ऋण आकार पूंजीगत निधि का 10%, समूह के लिए 15% होगा।
- न्यूनतम 50% ऋण 25 लाख तक होना चाहिए।

अवश्य पढ़ें: समावेशी विकास

SOURCE: BUISINESS LINE

आयकर रिटर्न

संदर्भ: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- पिछले साल इसी अवधि के दौरान लगभग 7.5 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बारे में:-

- 1961 का आयकर अधिनियम यह आदेश देता है कि संघीय सरकार राज्य के लिए यह कर एकत्र करे।
- आईटीआर ऐसे फॉर्म हैं जिनका उपयोग शुद्ध कर देनदारियों की घोषणा करने, कर कटौती का दावा करने और सकल कर योग्य आय की

रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है।

- जो व्यक्ति एक विशिष्ट राशि कमाते हैं उन्हें आईटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है।
- आयकर रिटर्न फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1963 में , प्रशासित: राजस्व विभाग।
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय और प्रशासित: राजस्व विभाग।
- यह 1963 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- केंद्रीय राजस्व बोर्ड राजस्व विभाग का सर्वोच्च निकाय है।
- इस पर करों का प्रशासन लगाया जाता है।
- यह 1924 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।
- यह भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स इकाई है।

सीबीडीटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रभारी था।
- हालाँकि, जब करों का प्रशासन एक बोर्ड के लिए कठिन हो गया, तो 1964 से बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड।

सीबीडीटी के कार्य:-

- प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत बोर्ड और केंद्र सरकार के वैधानिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नीतियां बनाना।
- इससे संबंधित सामान्य नीति:-
    - आयकर विभाग की स्थापना और संरचना का संगठन।
    - बोर्ड के काम के तरीके और प्रक्रियाएं।
    - आकलन के निपटान, करों के संग्रहण, रोकथाम और कर चोरी तथा कर से बचाव का पता लगाने के उपाय।
- आयकर विभाग के कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों एवं कैरियर की संभावनाओं से संबंधित सभी अन्य मामले।
- करों के आकलन और संग्रहण तथा अन्य संबंधित मामलों के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्राथमिकताएं तय करना।
- प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये से अधिक की कर मांगों को बट्टे खाते में डालना।
- पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में नीति बनाना।
- कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष की मंजूरी से, बोर्ड के संयुक्त विचार के लिए संदर्भित कर सकता है।

MUST READ:One Nation, One ITR Form

SOURCE:AIR

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)

संदर्भ: हाल ही में, सेबी ने 26 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया रिकवरी के लिए अरुण पंचारिया के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि:-

- कुर्की नोटिस में, बाजार निगरानी संस्था ने लंबित बकाया की वसूली के लिए पंचारिया के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

सेबी के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1992 में और मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-**इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

सेबी की संरचना:-

- अध्यक्ष को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- दो सदस्य, यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक से एक सदस्य होता है।
- शेष पांच सदस्यों को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, उनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)

- सेबी के निर्णय से व्यथित महसूस करने वाली संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) का गठन किया गया है।
- यह सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

सेबी की शक्तियां एवं कार्य:-

- सेबी नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, जांच कर सकता है, फैसले पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है।
- यह तीन श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है -
    - जारीकर्ता: एक बाज़ार प्रदान करके जिसमें जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं।
    - निवेशक: निश्चित और सटीक जानकारी की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करके।
    - मध्यस्थ: मध्यस्थों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके।
- प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा, सेबी अब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने और गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्ति संलग्न करने में सक्षम है।
- सेबी के अध्यक्ष के पास "तलाशी/जाँच और ज़ब्ती संबंधी ऑपरेशन" का आदेश देने का अधिकार है।
- बोर्ड अपने द्वारा जांच किए जा रहे किसी भी प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।
- यह उद्यम पूंजी कोष और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण और विनियमन का कार्य करेगा।
- यह स्व-नियामक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भी काम करता है और धोखाधड़ी तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए भी काम करता है।

अवश्य पढ़ें:स्वेट इक्विटी नियम: सेबी

SOURCE:BUISINESS LINE

ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

संदर्भ: हाल ही में, ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने उच्च पेंशन विकल्पों के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी है।

पृष्ठभूमि:-

- इससे पहले, उच्च योगदान पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 थी।

ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1952 में
- मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली

- यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
- भविष्य निधि (पीएफ): यह कर्मचारियों, नियोक्ताओं और (कभी-कभी) राज्य द्वारा योगदान किया गया एक निवेश कोष है, जिसमें से सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक कर्मचारी को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
- कार्य: यह ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- ईपीएफ वर्ष 1951 में ईपीएफ अध्यादेश की घोषणा के साथ अस्तित्व में आया।
- इसे बाद में ईपीएफ अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया।
- उद्देश्य:-
    - व्यापक सामाजिक सुरक्षा की उभरती जरूरतों को पारदर्शी, संपर्क रहित, फेसलेस और पेपरलेस तरीके से पूरा करना।
    - लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना।

1952 की ईपीएफ योजना

- यह ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक अनिवार्य बचत योजना है।
- इसमें प्रत्येक प्रतिष्ठान शामिल है जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और अन्य प्रतिष्ठान भी हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, भले ही उनमें से प्रत्येक में 20 से कम व्यक्ति कार्यरत हों।
- कर्मचारी को भविष्य निधि (पीएफ) के लिए एक निश्चित योगदान देना होता है और नियोक्ता मासिक आधार पर उतनी ही राशि का भुगतान करता है।
- कर्मचारी और नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12% के बराबर अनुपात में मासिक आधार पर ईपीएफ भारत योजना में योगदान करते हैं।
- सेवानिवृत्ति के अंत में या सेवा के दौरान (कुछ परिस्थितियों में), कर्मचारी को पीएफ पर योगदान पर ब्याज सहित एकमुश्त राशि मिलती है।
- ईपीएफ एक कर-बचत साधन है जो निवेश पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर प्रदान करता है।
- आंशिक निकासी: शिक्षा, विवाह, बीमारी और घर निर्माण के लिए अनुमति आदि पर।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

SOURCE:BUISINESS LINE

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल करेगी।

पृष्ठभूमि:-

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह वृद्धि 7.2 प्रतिशत की अनंतिम वृद्धि दर से ऊपर है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 2019 में
- मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर दिया गया था।
    - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में समय-समय पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन था।
    - भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन: भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था।
- एनएसओ की परिकल्पना सबसे पहले रंगराजन आयोग द्वारा सांख्यिकीय मानकों को लागू करने और बनाए रखने तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी

आयोग (एनएससी) द्वारा निर्धारित केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए की गई थी।

कार्य:-

- यह देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह राष्ट्रीय खाते तैयार करने के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी और निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजी स्टॉक के अनुमान और स्थिर पूंजी की खपत के वार्षिक अनुमान भी प्रकाशित करता है।
- यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को संकलित और जारी करता है।
- यह हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भी जारी करता है।
- यह उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) आयोजित करता है।
- यह समय-समय पर अखिल भारतीय आर्थिक जनगणना और अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों का आयोजन और संचालन करता है।

अवश्य पढ़ें: विकास और राजकोषीय समेकन

SOURCE:AIR

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

संदर्भ: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में भ्रामक विज्ञापनों के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है।

पृष्ठभूमि:-

- सीसीपीए ने पाया है कि कुछ कोचिंग संस्थान जानबूझकर सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि और उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई फीस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं।
- प्राधिकरण ने यह भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ कोचिंग संस्थान सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान किए बिना 100 प्रतिशत चयन और नौकरी की गारंटी जैसे दावे भी करते हैं।

इसके बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 2020 में
- मंत्रालय: उपभोक्ता मामले मंत्रालय
- मुख्यालय: दिल्ली
- प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत किया जा रहा है।
- इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया और उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने में इसके दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास किया।

संघटन:-

- इसके प्रमुख के रूप में मुख्य आयुक्त, और सदस्यों के रूप में केवल दो अन्य आयुक्त, जिनमें से एक सामान से संबंधित मामलें जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखता है।
- इसकी जांच विंग का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है।
- जिला कलेक्टरों के पास उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने की शक्ति होगी।

कार्य:-

- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और शिकायतें/अभियोजन शुरू करना।
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का आदेश देना।
- भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना।

अवश्य पढ़ें: CCPA: विज्ञापन नियम और सेवा शुल्क

SOURCE:AIR

जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना (ZED)

संदर्भ: हाल ही में, एमएसएमई के लिए जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना (जेडईडी) ने 1 लाख प्रमाणीकरण मील का पत्थर हासिल किया।

पृष्ठभूमि:-

- योजना के पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय, 1,02,642 एमएसएमई को प्रमाणित किया गया था, जिनमें से 1,01,962 को ब्रॉन्ज़-लेवल का प्रमाणन, 339 इकाइयों को सिल्वर और 341 को गोल्ड प्रमाणन प्राप्त हुआ था।
- योजना के तहत एमएसएमई को दी गई संचयी वित्तीय सहायता 134.57 करोड़ रुपये थी।

इस योजना के बारे में:-

- लॉन्च: अक्टूबर 2016 में
- मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- उद्देश्य: स्वच्छ प्रौद्योगिकी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन का दोहरा लक्ष्य प्राप्त करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- ZED योजना का लक्ष्य सभी एमएसएमई को प्रत्येक उद्योग के लिए सेक्टर-विशिष्ट मापदंडों के साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद वितरित करने के लिए रेट करना और समर्थन देना है।
- शून्य दोष उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करेगा और शून्य प्रभाव पर्यावरण का न्यूनतम प्रदूषण प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, यह योजना केवल एमएसएमई विनिर्माण के लिए लागू है।

इसके लाभ:-

- यह मेक इन इंडिया के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- एमएसएमई की उत्पादकता और दक्षता को भी बढ़ाता है और निवेश आकर्षित करने में सहायता करता है।
- विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक और घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

अवश्य पढ़ें: एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना

SOURCE: THE FINANCIAL EXPRESS

प्रवर्तन निदेशालय

संदर्भ: हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के मामले में एक गिरफ्तार टीएमसी नेता और उसके सहयोगियों से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ईडी की टीमें मध्य कोलकाता में चार परिसरों और शहर के पूर्वी किनारे पर साल्क लेक में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय में तलाशी अभियान की कारवाही की।
- उनके अनुसार, ये सभी स्थान जहां तलाशी ली जा रही थी, टीएमसी नेता और बोंगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या से जुड़े थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बारे में:-

- यह वर्ष 1956 में स्थापित एक बहु-विषयक संगठन है और इसका मुख्यालय: नई दिल्ली में है।
- यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है।
- यह एक कानून प्रवर्तन संगठन है जिसे आर्थिक कानूनों को लागू करने और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग तथा विदेशी मुद्रा अनियमितताओं जैसे आर्थिक अपराध से निपटने का काम सौंपा गया है।
- निदेशालय के कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है:-
    - **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए)**
    - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): एक नागरिक कानून जिसके तहत ईडी विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करता है।

- **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973**
- 1974 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रायोजक संगठन है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): एक कानून जिसके तहत निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो गिरफ्तारी की गारंटी लेकर भारत से भाग गए हैं और उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार को जब्त करने का प्रावधान है।

- **प्रवर्तन निदेशक:-**
  - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके सदस्यों में सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, सचिव डीओपीटी और राजस्व सचिव शामिल होते हैं।
  - कार्यकाल: 5 वर्ष तक

MUST READ:CBI and ED
SOURCE:THE HINDU

नम्मा यात्री

संदर्भ: हाल ही में, नम्मा यात्री ने 10,000 ऑटो चालकों के साथ दिल्ली में शुरुआत की।
पृष्ठभूमि:-

- यह ऐसे समय में आया है जब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन में गतिशीलता एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरी है।

नम्मा यात्री के बारे में:-

- इसे 2020 में कोच्चि में "यात्री (Yatri)" के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह पहला ओपन नेटवर्क मोबिलिटी एप्लिकेशन है जिसे किसी बिचौलिए के जुड़े बिना यात्रियों को मल्टी-मॉडल सेवा प्रदान करने के विचार से बनाया गया है।
  - ओपन मोबिलिटी एक खुला नेटवर्क है जहां परिवहन का कोई भी साधन यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने में योगदान दे सकता है जिससे किसी तीसरे पक्ष के संगठनों पर निर्भरता खत्म हो सकती है।
- ऑटो रिक्शा इस गतिशीलता नेटवर्क में शामिल होने वाले कई सेवा प्रदाताओं में से पहला है।
- नम्मा यात्री परिवार के ऐप्स वर्तमान में ओएनडीसी नेटवर्क के सात शहरों में संचालित हो रहे हैं।
- यह Juspay द्वारा समर्थित है, और यह 1.7 लाख से अधिक ड्राइवरों और 40 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
- ऐप का दावा है कि ड्राइवरों ने अब तक कमीशन-मुक्त 350 करोड़ रुपए कमाए हैं।

अवश्य पढ़ें: शहरी गतिशीलता विस्तार
SOURCE:BUSINESS LINE

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

संदर्भ: हाल के विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सर्वेक्षण में 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की आशंका है।
पृष्ठभूमि:-

- जैसा कि दुनिया भर के शीर्ष नेता अपनी वार्षिक सभा के लिए यहां एकत्रित होते हैं, मुख्य अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भू-आर्थिक विखंडन में तेजी आने का अनुमान लगाया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1971 में और मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- मिशन: WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था और यह स्वतंत्र, निष्पक्ष है।
- यह शासन के उच्चतम मानकों को बनाये रखते हुए वैश्विक जनहित में उद्यमशीलता को प्रदर्शित करता है।
- यह विश्वास स्थापित करने और सहयोग तथा प्रगति के लिए पहल करने के लिए हितधारकों के बीच सार्थक संबंध के लिए एक वैश्विक,

निष्पक्ष और गैर-लाभकारी मंच प्रदान करता है।

- फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है।
- कार्य करना:-
  - फोरम चार प्रमुख वार्षिक बैठकें आयोजित करता है: विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, नए चैंपियंस की वार्षिक बैठक, वैश्विक भविष्य परिषदों की वार्षिक बैठक।
  - उद्योग रणनीति बैठक: उद्योग के एजेंडे को आकार देने के लिए उद्योग रणनीति अधिकारियों को एक साथ लाता है और यह पता करता है कि उद्योग परिवर्तन के प्रबंधन से अग्रणी परिवर्तन की ओर कैसे स्थानांतरित हो सकते हैं।
  - इसके अलावा, क्षेत्रीय बैठकें और राष्ट्रीय रणनीति दिवस क्षेत्रीय और स्थानीय एजेंडे पर हावी मुद्दों पर केंद्रित सहभागिता प्रदान करते हैं।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट:-ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, WEF ने INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट

अवश्य पढ़ें:आईएमएफ और विश्व आर्थिक आउटलुक

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

तेल की कीमतें

संदर्भ: हाल ही में, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच तेल की कीमतों में 0.93% की गिरावट आई।

पृष्ठभूमि:-

- इंट्रा-डे ट्रेड में, अंतिम रिपोर्ट आने तक ब्रेंट क्रूड 0.93 प्रतिशत गिरकर 77 डॉलर और 56 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी तीन प्रतिशत गिरकर 71 डॉलर और 91 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

तेल की कीमत और भारत की स्थिति :-

- भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है।
- भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 70% ओपेक सदस्यों से आयात करता है।
- एक दशक की तुलना में, वर्ष 2021-22 में आयात 87% से घटकर 70% हो गया है। हालाँकि, ओपेक अभी भी भारत के अधिकांश तेल आयात का हिस्सा है।
- ओपेक एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है।
- तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक: -आपूर्ति और खपत, सरकारी विनियमन, भू-राजनीति, वित्तीय बाजार।
- भारत पर तेल की कीमतों में गिरावट का प्रभाव: आयातित मुद्रास्फीति में कमी, उच्च आर्थिक विकास, कम राजकोषीय घाटा, कम बाहरी भेद्यता

अवश्य पढ़ें: तेल बाज़ार में मंदी

SOURCE:AIR

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

संदर्भ: हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने 'सनातन खादी वस्त्र' की नई श्रृंखला लॉन्च की।

पृष्ठभूमि:-

- KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रमुख खादी भवन में खादी कपड़ों से बने सनातन वस्त्र लॉन्च किए।

सनातन खादी वस्त्र के बारे में:-

- द्वारा: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)।
- कपड़ों का डिजाइन निफ्ट स्थित खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार किया गया है।
- लॉन्च का उत्सव मनाने के लिए, केवीआईसी ने 17 से 25 जनवरी, 2024 तक 'सनातन वस्त्र' पर 20% और अन्य खादी और ग्रामोद्योग

उत्पादों पर 10% से 60% की विशेष छूट की पेशकश की।

महत्व:-

- 'सनातन वस्त्र' भारत की समृद्ध विरासत और समकालीन फैशन रुझानों का मिश्रण है और साथ ही यह इन समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
- यह 1956 के खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- केवीआईसी का उद्देश्य: -देश में रोजगार को बढ़ावा देना, खादी वस्तुओं को बढ़ावा देना और बिक्री करना, आत्मनिर्भरता सिद्धांत को पूरा करना और समाज के वंचित तथा ग्रामीण वर्गों को सशक्त बनाना।
- कार्य: केवीआईसी पर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है।

अवश्य पढ़ें: ग्रामोद्योग विकास योजना

SOURCE:AIR

बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवोल्यूशन)

संदर्भ: हाल ही में, सीएसआईआर की गणतंत्र दिवस की झांकी जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर की खेती के माध्यम से बैंगनी क्रांति पर प्रकाश डालती है।

पृष्ठभूमि:-

- विकसित भारत थीम के तहत, झांकी सीएसआईआर की लैब-टू-मार्केट सफलता की कहानी पर प्रकाश डालती है।

लैवेंडर की खेती के बारे में:-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2016 में पर्पल रिवोल्यूशन या लैवेंडर क्रांति की शुरुआत की।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन ने बैंगनी क्रांति का नेतृत्व किया।

उद्देश्य:-

- आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना और भारतीय किसानों तथा सुगंध उद्योग को वैश्विक नेता बनने में सक्षम बनाना।
- किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने, बंजर भूमि का उपयोग करने एवं जंगली और चरने वाले जानवरों से उनकी फसलों की सुरक्षा में लाभ प्रदान करना।
- इसका उद्देश्य किसानों को अन्य विदेशी विकल्पों से स्वदेशी सुगंधित फसल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके लैवेंडर फसलों को बढ़ावा देना है।
- नोडल प्रयोगशाला सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीमैप), लखनऊ है।
- जिन किसानों ने पहली बार लैवेंडर का उत्पादन किया, उन्हें लक्ष्य के हिस्से के रूप में मुफ्त लैवेंडर पौधे प्रदान किए गए।

महत्व:-

- इसने जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में लगभग 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों को रोजगार दिया है।
- यह आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा।
- इससे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योगों के लिए अतिरिक्त 700 टन आवश्यक तेल के उत्पादन में मदद मिलेगी।

अवश्य पढ़ें: हरित क्रांति को तेज़ करना

SOURCE:PIB

के-शेप्ड इकोनामिक रिकवरी

संदर्भ: हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कथन को चुनौती दी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के बाद 'K-आकार' की रिकवरी देखी गई है।

पृष्ठभूमि:-

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि एक कहानी बनाई जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है।

'K-आकार' की रिकवरी के बारे में:-

- यह तब होता है, जब मंदी के बाद, अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से अलग-अलग दरों, समय या परिमाण में ठीक हो जाते हैं।
- यह सभी क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में एक समान, समान पुनर्प्राप्ति के विपरीत है।
- आर्थिक सुधार मंदी के बाद का व्यावसायिक चक्र चरण है, जो व्यावसायिक गतिविधि में सुधार की निरंतर अवधि की विशेषता है।
- आर्थिक सुधार कई रूप ले सकता है, जिसे वर्णमाला संकेतन का उपयोग करके दर्शाया गया है।
    - उदाहरण के लिए, Z-आकार की रिकवरी, V-आकार की रिकवरी, U-आकार की रिकवरी, U-आकार की रिकवरी, W-आकार की रिकवरी, L-आकार की रिकवरी और K-आकार की रिकवरी।
- इससे अर्थव्यवस्था या व्यापक समाज की संरचना में बदलाव आता है क्योंकि मंदी से पहले और बाद में आर्थिक परिणाम और संबंध मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
- इस प्रकार की पुनर्प्राप्ति को K-आकार कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का मार्ग जब एक साथ चार्ट किया जाता है तो रोमन अक्षर "K" की दो भुजाओं के समान भिन्न हो सकता है।

अवश्य पढ़ें: अपेक्षित आर्थिक सुधार

SOURCE:INDIA TODAY

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत 'प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क' का मसौदा जारी किया।

पृष्ठभूमि:-

- आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, मसौदा मानदंडों का ध्यान जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं की व्यापक उपलब्धता के मद्देनजर मुद्रा परिवर्तकों के लिए प्राधिकरण ढांचे को तर्कसंगत बनाने, विदेशी मुद्रा से संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक मॉडल को देखने और एडी-श्रेणी II संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के दायरे में सुधार करने पर है।
- इसमें कहा गया है कि यह एपी के लिए नियामक ढांचे की भी समीक्षा करेगा।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के बारे में:-फेमा, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- उदारीकरण के बाद भारत में बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ, यह 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या FERA के उत्तराधिकारी के रूप में 1999 में आया।
- उद्देश्य: बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना।
- 1 जून 2000 से, विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेनदेन को पूंजी या चालू खाता लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- चालू खाता लेनदेन: किसी निवासी द्वारा किए गए सभी लेनदेन जो भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहित उसकी संपत्ति या देनदारियों में बदलाव नहीं करते हैं, चालू खाता लेनदेन हैं।
- पूंजी खाता लेनदेन: इसमें वे लेनदेन शामिल हैं जो भारत के निवासी द्वारा किए जाते हैं जैसे कि भारत के बाहर उसकी संपत्ति या देनदारियां बदल जाती हैं (या तो बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं)।
- यह पूंजी खाता लेनदेन के क्रमिक उदारीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करता है और पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता के अनुरूप है।
- चूंकि यह विदेशी मुद्रा के अधिग्रहण/धारण पर रिजर्व बैंक/भारत सरकार से कुछ प्राधिकरण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है, इसलिए यह अपने आवेदन में अधिक स्पष्ट है।
- भारत में रहने वाला व्यक्ति जो पहले देश के बाहर रहता था, उसे भारत के बाहर रहने के दौरान प्राप्त किसी भी विदेशी प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति को रखने, और स्थानांतरित करने की पूरी आजादी दी गई है।
- भारत के नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं वे फेमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

- यह अधिनियम न केवल भारत के अंदर भारत के निवासियों पर लागू होता है, बल्कि भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों और सेट-अप पर भी लागू होता है, जिनका स्वामित्व या नियंत्रण भारत में निवासी व्यक्ति के पास होता है।

MUST READ: **Finding Unemployment Benefits**
SOURCE: **AIR**

भूगोल

अदन की खाड़ी

संदर्भ: भारतीय नौसेना ने हाल ही में मध्य/उत्तरी अरब सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री निगरानी प्रयासों को बढ़ाया है।

पृष्ठभूमि:-

- पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य/उत्तरी अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर समुद्री सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

अदन की खाड़ी के बारे में:-

IMAGE SOURCE: worldatlas.com

- स्थान: पश्चिमी अरब सागर
- यह हिंद महासागर का विस्तार है, जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है।
- यह खाड़ी बाब अल मांडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है।
- इस खाड़ी का नाम यमन के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर "अडेन" के नाम पर रखा गया है।
- यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोट्रा द्वीप समूह से, उत्तर में यमन से, पूर्व में अरब सागर से और पश्चिम में जिबूती से घिरी है।
- खाड़ी के भूभाग की प्रमुख राहत विशेषता शेबा रिज है, जो हिंद महासागर रिज प्रणाली का विस्तार है, यह खाड़ी के मध्य तक फैली हुई है।

आर्थिक क्रियाकलाप:-

- मछली पकड़ना तटीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और बंदरगाह व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करती हैं।
- यमन और सोमालिया सहित आसपास के क्षेत्रों में संभावित तेल और गैस भंडार हैं।

अवश्य पढ़ें: हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका

SOURCE: PIB

सोमालिया

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना ने सोमालिया तट से हाइजैक मालवाहक जहाज से चालक दल के 21 सदस्यों को बचाया।

पृष्ठभूमि:-

- मालवाहक जहाज से अपहरण का संकेत मिलने के बाद नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस चेन्नई को रवाना किया और समुद्री अभियान चलाया।

सोमालिया के बारे में:-

IMAGE SOURCE: WORLD ATLAS

- स्थान: अफ़्रीका के सबसे पूर्वी सिरे पर।
- मोगादिशु सोमालिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
- यह केन्या, इथियोपिया और जिबूती तीन देशों की सीमा बनाता है।
- यह अफ्रीका के हॉर्न के किनारे स्थित है, यह क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी और पर्वतीय होने के लिए जाना जाता है।
- सुदूर उत्तर में, एक संकीर्ण अर्धरेगिस्तानी तटीय मैदान, जिसकी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 12 किमी से लेकर पूर्व में केवल 2 किमी तक है, अदन की खाड़ी की सीमा पर है। इसे गुबन कहा जाता है।
- इस मैदान से परे करकर पर्वत की समुद्री पर्वत श्रृंखला है (मानचित्र पर चिह्नित) जो देश में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है।
- इसकी केवल दो देशों के साथ भूमि सीमाएँ हैं; दक्षिण पश्चिम में केन्या और पश्चिम में इथियोपिया।
- अदन की खाड़ी सोमालिया की उत्तरी सीमा बनाती है और सोमाली सागर तथा गार्डाफुई चैनल इसे पूर्व में घेरते हैं।
- सोमालिया गर्म तापमान और सीमित वर्षा के साथ मुख्य रूप से शुष्क से अर्ध-शुष्क जलवायु का अनुभव करता है।

अवश्य पढ़ें: हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका

SOURCE:AIR

कवरत्ती द्वीप

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप समूह में 1150 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

पृष्ठभूमि:-

- आज की विकास परियोजनाएं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को कवर करती हैं।

इस द्वीप समूह के बारे में:-

IMAGE SOURCE: kscl.utl.gov.in

- भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, इसका सबसे विकसित द्वीप है।
- यह लक्षद्वीप द्वीपसमूह के केंद्र में स्थित है।
- यह पश्चिम में अगत्ती द्वीप और पूर्व में एंड्रोट द्वीप के बीच स्थित है।
- क्षेत्रफल: 4.22 वर्ग किमी.
- इस द्वीप में 12 एटोल, पांच जलमग्न तट (five submerged banks) और तीन मूंगा चट्टानें शामिल हैं।
    - एटोल जल के एक तालाब के चारों ओर भूमि का एक घेरा है जिसे लैगून कहा जाता है।
- कवरत्ती अपने उत्तरी सिरे पर एक छोटी अंतर्देशीय झील से आश्चर्यचकित करता है।
- कवरत्ती शहर अपनी मस्जिदों की जटिल नक्काशीदार लकड़ी के खंभों और छतों के साथ-साथ अपने कब्रिस्तानों की शोभा बढ़ाने वाले नक्काशीदार पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है।
- निवासियों के रूप में गैर-द्वीपवासियों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत के साथ, बोली जाने वाली भाषाएँ मलयालम और महल (Mahl) हैं।
- इसके अलावा, कावारत्ती को प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए निर्धारित 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है।

अवश्य पढ़ें: सोलोमन द्वीप समूह

SOURCE:PIB

कोरापुट काला जीरा चावल

संदर्भ: हाल ही में कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है।

कोरापुट काला जीरा चावल के बारे में:-

- ओडिशा में कोरापुट जिला से।
- चावल कोरापुट जिले के तोला, पात्रापुट, पुजारीपुट, बालीगुडा और मोहुली क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- इसे 'प्रिंस ऑफ़ राइस' कहा जाता है।
- यह चावल की एक सुगंधित किस्म है।
- यह अपने काले रंग, अच्छी सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए लोकप्रिय है।
- काले रंग के चावल की किस्म, अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है।
- कोरापुट क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने लगभग 1,000 वर्षों से चावल की किस्म को संरक्षित रखा है।
- चूंकि चावल के दाने जीरे के समान होते हैं, इसलिए इसे काला जीरा भी कहा जाता है।
- विभिन्न प्रकार के चावल का सेवन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में चयापचय में सुधार करता है।

- इस सुगंधित अनाज में ऐंठननाशक, पेटनाशक, वातनाशक, जीवाणुरोधी, कसैला और शामक होता है।

MUST READ:GI tag for Narasinghapettainagaswaram
SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

सिमिलिपाल काई चटनी

संदर्भ: हाल ही में सिमिलिपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है।
सिमिलिपाल काई चटनी के बारे में:-

- लाल बुनकर चींटियों से बनी चटनी ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों का पारंपरिक व्यंजन है।
- चींटियाँ मयूरभंज के जंगलों में पाई जाती हैं, जिनमें सिमिलिपाल के जंगल भी शामिल हैं - यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवमंडल है। यह औषधीय और पोषण मूल्य से भरपूर है।
- चटनी को प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन बी-12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है।
- आदिवासी चींटियों को सिल बट्टा या चक्की पर हाथ से पीसकर काई चटनी तैयार करते हैं। मयूरभंज के आदिवासी लाल चींटियों और चींटियों से बनी चटनी बेचकर भी अपनी आजीविका कमाते हैं।
- उनका मानना है कि इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है।

अवश्य पढ़ें: सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान
SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

लांजिया सौरा पेंटिंग

संदर्भ: हाल ही में लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है।
लांजिया सौरा पेंटिंग के बारे में:-

- सबसे पुराने जनजातीय कला रूपों में से एक, पेंटिंग को इडिटल के नाम से भी जाना जाता है।
- कलाकृतियाँ अपनी सुंदरता, सौंदर्यशास्त्र, कर्मकांडीय संगति और प्रतिमा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं।
- यह कला लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है, जो एक पीवीटीजी और मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहते है। (सहरिया जनजाति)
- ये पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्तिचित्रों के रूप में हैं।
- सफेद पेंटिंग लाल-मैरून पृष्ठभूमि पर चित्रित हैं।
- ऐसा माना जाता है कि लांजिया सौरस अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी दीवारों को आइडिटल कलाकृतियों से रंगते हैं।
- प्रकृति के प्रति आदिम जनजातियों के प्रेम और स्नेह को दर्शाते हुए, उनमें आदिवासी मानव, पेड़, जानवर, पक्षी, सूर्य और चंद्रमा जैसे विषय शामिल हैं।

अवश्य पढ़ें: जलवायु परिवर्तन के कारण प्राचीनतम शैल चित्रों का क्षय
SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

कुनो राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: हाल ही में, नामीबियाई चीता ज्वाला ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चार शावकों को जन्म दिया है, न कि तीन, जैसा कि पहले घोषित किया गया था।
पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 24 जनवरी 2024 को यह जानकारी दी।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-

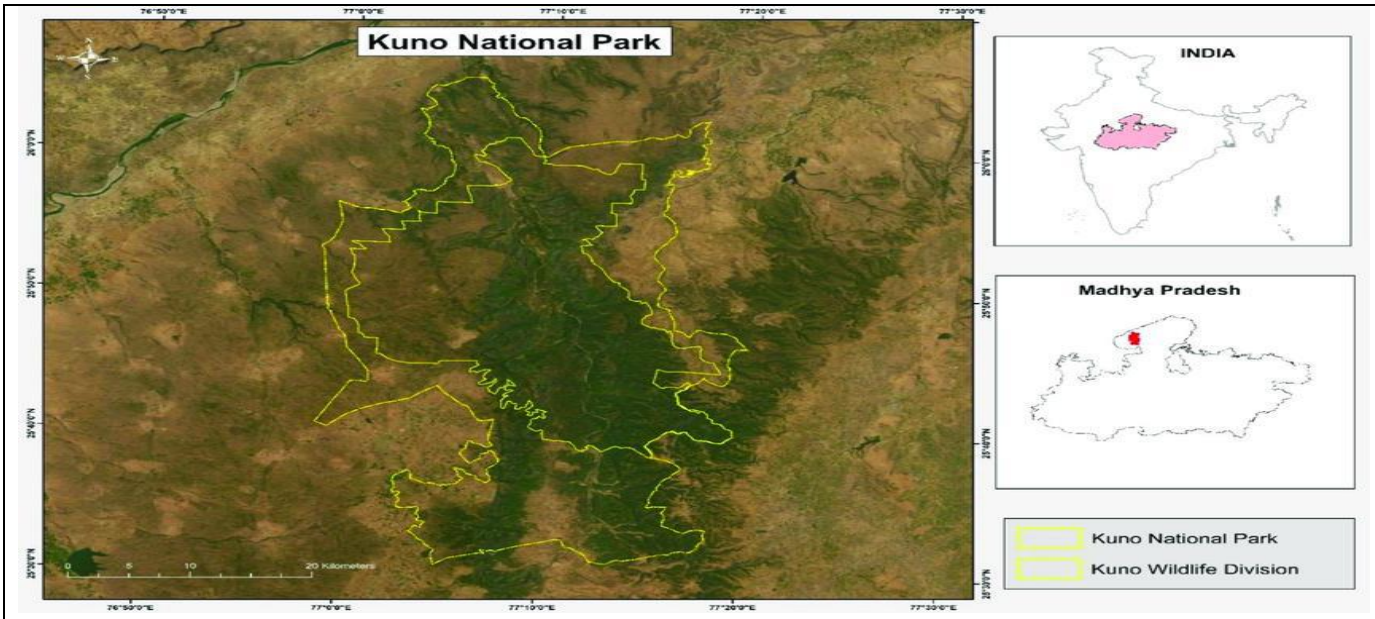

IMAGE SOURCE: researchgate.net

- स्थान: मध्य प्रदेश, भारत, इसकी स्थापना 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी।
- यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है।
- इसका नाम कूनो नदी (चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक) के नाम पर रखा गया है जो इसे विभाजित काटती है।
- शुरुआत में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित, वर्ष 2018 में ही सरकार ने इसकी स्थिति को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान को 'भारत में चीता के परिचय के लिए कार्य योजना' के तहत चुना गया था।
- वनस्पति: शुष्क सवाना वन और घास के मैदान तथा उष्णकटिबंधीय नदी वन।
- जीव-जंतु: भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सुस्त भालू, ढोल, भारतीय भेड़िया, सुनहरा सियार, धारीदार लकड़बग्घा और बंगाल लोमड़ी।

अवश्य पढ़ें: मानस राष्ट्रीय उद्यान

SOURCE:THE HINDU

नयागढ़ कांतिमुंडि बैंगन

संदर्भ: हाल ही में, नयागढ़ कांतिमुंडि बैंगन को जीआई टैग मिला है।

इसके बारे में:-

- नयागढ़ कांतिमुंडि बैंगन का पौधा खूब सारे तने और कांटेदार होने के लिए मशहूर है।
- छोटे हरे और सफेद रंग के बैंगन के फल में अन्य किस्मों की तुलना में ज्यादा बीज होते हैं।
- अपनी अनूठी स्वाद और कम समय में पकने के लिए बैंगन का यह किस्म मशहूर है।
- पौधे प्रमुख कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाए जा सकते हैं।
- नयागढ़ जिले में व्यापक रूप से खेती की जाती है।
- प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल तक उपज, 60 रुपये प्रति किलो बिकते है।
- स्थानीय लोगों ने लगभग 100 साल पहले पहाड़ी इलाकों से बैंगन के बीज एकत्र किए थे।

अवश्य पढ़ें:मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

ढेंकनाल माजी

संदर्भ: हाल ही में ढेंकनाल माजी को जीआई टैग मिला है।

ढेंकनाल माजी के बारे में:-

- स्थान: ओडिशा
- यह भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई है, जो स्वादिष्ट और आकार की दृष्टि से विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होती है।
- इसमें अद्वितीय पोषण मूल्य भी हैं जो इसे अन्य पनीर-आधारित मिठाइयों से अलग करते हैं।

- ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान हजारों लोग पशुपालन, विशेषकर भैंस पालन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे।
- यह क्षेत्र भैंस के दूध उत्पादन का आंतरिक क्षेत्र था और दूध और दही के बाद पनीर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन था।
- गोंदिया ब्लॉक के मंदार-सादंगी क्षेत्र को मीठे पदार्थ की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, जो अब पूरे जिले में फैल गया है।
- पनीर से नमी निकालकर और फिर उसे भूनकर, अंत में मिश्रण से गोले बनाकर मिठाई तैयार की जाती है।

अवश्य पढ़ें: मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग
SOURCE:THE HINDU

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

यूरेशियन ऊदबिलाव

संदर्भ: हाल ही में, यूरेशियन ओटर को केरल में देखा गया था।

पृष्ठभूमि:-

- केरल के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार राज्य में यूरेशियन ओटर की मौजूद होने का दावा किया है।

यूरेशियन ओटर के बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम: लुट्रालुट्रा
- वितरण: यह पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।
- भारत में, यह उत्तरी, उत्तरपूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यह विभिन्न वातावरणों में रह सकता है, जिसमें जलधाराएँ, नदियाँ, झीलें, मीठे पानी और पीट दलदली जंगल, समुद्र तट, चावल के खेत, जंगल, गुफाएँ और जलमार्गों के पास स्थलीय क्षेत्र शामिल हैं।
- भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से ठंडी पहाड़ियों और पहाड़ी नदियों में पाया जाता है।
- यह एक अर्ध-जलीय स्तनपायी (semi-aquatic mammal) है, यह आमतौर पर यूरेशिया का मूल निवासी है।
- इसका आहार मुख्य रूप से मछली है और यह अत्यधिक प्रादेशिक है।

संरक्षण की स्थिति:-

- IUCN स्थिति: संकट निकट
- CITES: परिशिष्ट I
- WPA: अनुसूची II

अवश्य पढ़ें: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

SOURCE: TIMES OF INDIA

लाओखोवा और बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में, गैंडे 40 साल बाद असम के लाओखोवा-बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य में वापस आए।

पृष्ठभूमि:-

- 1983 तक, यह संरक्षित क्षेत्र, जो "बड़े" काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, में 45-50 गैंडे थे लेकिन शिकारियों ने उन्हें नष्ट कर दिया। हालाँकि, पिछले साल नवंबर से इन्हें फिर से देखा गया है।
- लाओखोवा और बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के दो केंद्रीय रूप से स्थित संरक्षित क्षेत्र (पीए) हैं।
- वास्तव में, इन दोनों वन्यजीव अभयारण्यों के दो अलग-अलग नाम हैं, ये पारिस्थितिक और भौगोलिक रूप से एक विलक्षण इकाई हैं।

इस अभयारण्य के बारे में:-

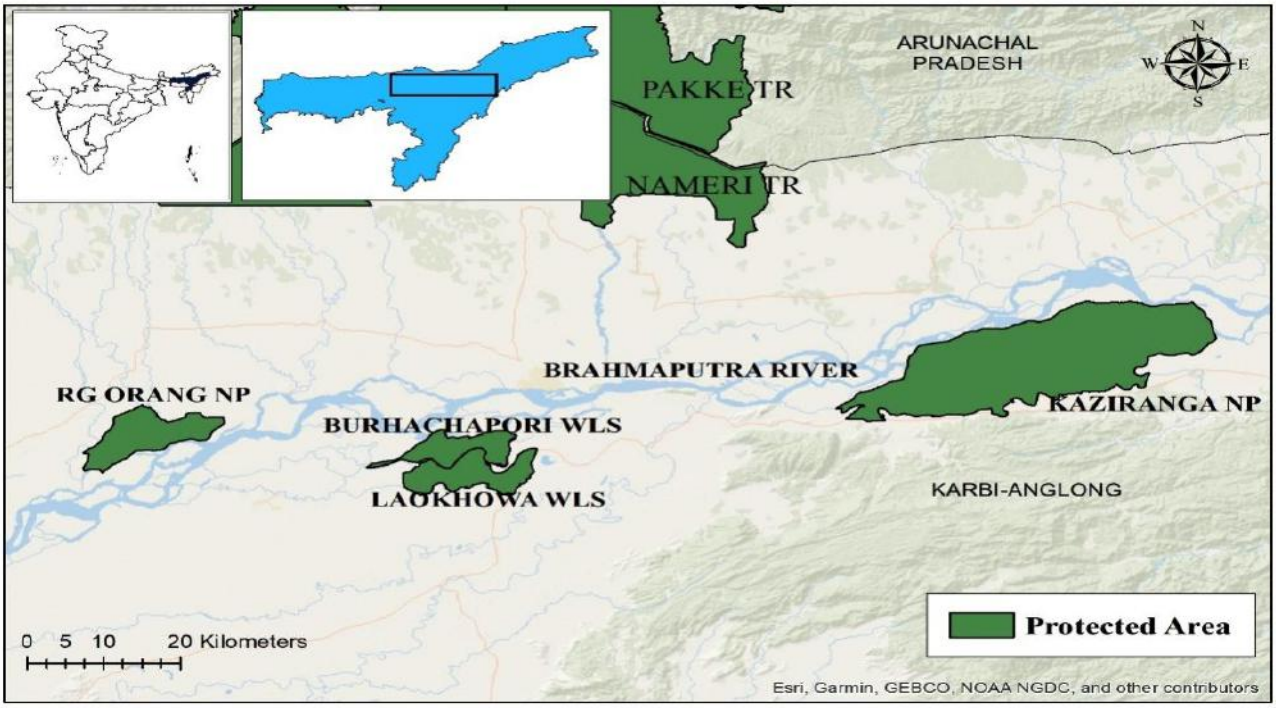

IMAGE SOURCE: pachydermjournal.org

- **स्थान:** भारत के असम का नागांव जिला।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- **क्षेत्रफल:** लगभग 70 वर्ग किलोमीटर
- **वनस्पति:** इस क्षेत्र में मीठे पानी के मैंग्रोव पेड़, सिमुल, कोराई, अजर, हिजाल आदि पाए जाते हैं।
    - अभयारण्य में पेड़ों और औषधीय पौधों की कई प्रजातियाँ हैं।
- **जीव-जंतु:** भारतीय एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, जंगली भैंसा, हाथी आदि।
    - अत्यधिक लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फ़िन अभी भी इन पासों से सटे ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में देखी जाती हैं।

बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य:-

- यह असम के नागांव जिले में स्थित, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के निकट है।
- यह 44 वर्ग किलोमीटर में फैला और 1995 में आधिकारिक तौर पर एक वन्यजीव अभयारण्य बन गया।
- लाओखोवा-बुराचापोरी इको-सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व के लिए बफर के रूप में कार्य करता है।
- इसमें घास के मैदान, आर्द्रभूमि और नदी के आवासों का एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है।
- प्रजातियों में मीठे पानी के मैंग्रोव पेड़, सिमुल, कोराई, अजर, हिजाल और औषधीय पौधे शामिल हैं।
- यह हाथी, जंगली भैंस, हिरण और विभिन्न प्राइमेट्स का निवास है।

अवश्य पढ़ें: वन्यजीव संरक्षण

SOURCE: THE TIMES OF INDIA

बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (बीआरटी) टाइगर रिजर्व

संदर्भ: हाल ही में, कर्नाटक वन विभाग ने बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (बीआरटी) टाइगर रिजर्व के माध्यम से बीआर हिल्स में आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू किया।

पृष्ठभूमि:-

- कर्नाटक वन विभाग ने हाल ही में बीआरटी टाइगर रिजर्व के माध्यम से बीआर हिल्स में प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स, दोपहिया वाहनों से 10 रुपये और चार पहिया वाहनों से 20 रुपये वसूलना शुरू किया है।

बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (बीआरटी) टाइगर रिजर्व के बारे में:-

IMAGE SOURCE: researchgate.net

- स्थान: कर्नाटक
- क्षेत्रफल: 574.82 किमी²
- इसका नाम बिलिगिरि उस सफेद चट्टान से पड़ा है जिसके शीर्ष पर भगवान विष्णु का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग रंगास्वामी के नाम से जानते हैं।
- यह भी माना जाता है कि इस पहाड़ी श्रेणी का नाम सफेद धुंध (white mist) और चांदी के बादलों के कारण पड़ा है जो वर्ष के अधिकांश समय इन ऊंची पहाड़ियों को ढके रहते हैं।
- कन्नड़ में, बिलिगिरी का अर्थ है सफेद पहाड़ियाँ - इसलिए यह नाम पड़ा।
- यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच पुल के मध्य में स्थित है।
- यह अनोखा अभयारण्य झाड़ीदार, शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, सदाबहार, अर्ध सदाबहार और शोला वनों को प्रदर्शित करता है।
- इसे 1974 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में गठित किया गया था।
- बीआरटी वन्यजीव अभयारण्य को 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
- वनस्पति: एनोजीसस लैटिफोलिया, डालबर्गिया पैनिकुलता, ग्रेविया तेलियाफोलिया, टर्मिनलिया अल्टा, टर्मिनलिया बेलिरिका, टर्मिनलिया पैनिकुलता, आदि।
    - यह मूल्यवान औषधीय सहित पौधों की कई स्थानिक प्रजातियों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
- जीव-जंतु: बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, बाइसन, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग डियर, चार सींग वाले मृग, सुस्त भालू, जंगली सूअर, आदि।

MUST READ:Global Conservation Assured|Tiger Standards (CA|TS)
SOURCE:THE TIMES OF INDIA

कॉनजॉइन्ड सिल्वरलाइन

संदर्भ: हाल ही में, कर्नाटक में सिल्वरलाइन से जुड़ी एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई।
पृष्ठभूमि:-
इस प्रजाति को पहली बार 2008 में देखा गया था, इसके बाद 2021 में व्यापक शोध किया गया।
इसके बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम: सिगारिटिस कंजंक्टिवा ,यह तितली मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु जिले की हनी घाटी में घने मध्य-ऊँचाई वाले सदाबहार जंगलों में पाई जाती है।
- यह पश्चिमी घाट में खोजी गई दूसरी स्थानीय प्रजाति है।
- इसकी पहचान कर्नाटक के कोडागु जिले में की गई है, जो 1970 के दशक के बाद से भारत के पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट में पहली

ऐसी खोज है।

- नामकरण: पंखों पर विशिष्ट रंग विविधता के कारण इसे 'संयुक्त सिल्वरलाइन' कहा जाता है।
- दूर से देखने पर पंख एक ही रंग में प्रतीत होता है किंतु करीब से ये बहुत ही आकर्षक दिखते हैं।
- पंखों के सभी रंगीन भाग पंख के नीचे की ओर आपस में जुड़े होते हैं।

MUST READ:White Tufted Royal Butterfly
SOURCE: DOWN TO EARTH

अफ्रीका चीता

संदर्भ: हाल ही में, विशेषज्ञों ने IUCN से हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका चीता की स्थिति को 'लुप्तप्राय' में अपग्रेड करने की अपील की है।

पृष्ठभूमि:-

- विशेषज्ञों के एक समूह ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) से अफ्रीका के हॉर्न में पाए जाने वाले पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस सोमेरिंगी) की स्थिति को 'असुरक्षित' से 'लुप्तप्राय' की श्रेणी में डालने की अपील की है।

अफ्रीका चीता के बारे में:-

- वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस
- निवास स्थान: अफ्रीकी सवाना
- इनका शरीर 1.2 मीटर (4 फीट) लंबा, पतला होता है, संतुलन के लिए एक लंबी पूंछ (65-85 सेमी) होती है, जो आम तौर पर एक सफेद गुच्छे (white tuft) में समाप्त होती है।
- इनका वजन 34 से 54 किलोग्राम (75 से 119 पाउंड) तक होता है, नर मादा से थोड़े बड़े होते हैं। एशियाई चीता की तुलना में ये आकार में बड़े होते हैं।
- इनके पूरे शरीर पर छोटे काले गोल धब्बे होते हैं, काले निशान आंख के अंदर से मुंह के कोने तक होते हैं। इनका नाम ही संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है 'धब्बेदार'। ये छोटे मृगों, स्तनधारियों, पक्षियों का शिकार करते हैं। वे सभी भूमि जानवरों में सबसे तेज़ हैं। (चीता पुनरुत्पादन)

संरक्षण की स्थिति:-

- IUCN स्थिति: असुरक्षित
- CITES: परिशिष्ट I

अवश्य पढ़ें: चीता और अन्य: 7 बड़ी बिल्लियों के बारे में जानकारी होना

SOURCE:DOWN TO EARTH

सेन्ना स्पेक्टाबिलिस

संदर्भ: हाल ही में, तमिलनाडु के वन विभाग ने सेन्ना स्पेक्टेबिलिस की 356.50 हेक्टेयर आक्रामक वृद्धि को साफ़ कर दिया है।

पृष्ठभूमि:-

- यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में जैव विविधता संरक्षण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था।

सेन्ना स्पेक्टेबिलिस के बारे में:-

- इसे आमतौर पर कैसिया एक्सेलसा, कैसिया फास्टिगियाटा, या कैसिया मल्टीजुगा के नाम से जाना जाता है।
- इसे "कैसिया" या "गोल्डन वंडर ट्री" भी कहा जाता है। यह अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है।
- पर्यावास: पूर्वोत्तर ब्राज़ील में शुष्क भूमि वन, आमतौर पर खुली संरचनाओं में, गहरी, अच्छी तरह से सूखी, उपजाऊ मिट्टी इसके लिए लाभदायक हैं। यह एक पर्णपाती वृक्ष है। यह कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और फूल आने के बाद हजारों बीज वितरित करता है।
- फूलों के मौसम के दौरान, पेड़ पीले फूलों के जीवंत गुच्छों का उत्पादन करता है, यह देखने में आकर्षक बनाता है।
- इसे देश में कॉफी और जलाऊ लकड़ी के लिए छायादार पेड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया था और जल्द ही यह देशी वृक्ष प्रजातियों के लिए खतरा बन गया क्योंकि इसके घने पत्ते अन्य देशी पेड़ों और घास प्रजातियों के विकास को रोकते थे।

संरक्षण की स्थिति:-

- IUCN: कम चिंताजनक

अवश्य पढ़ें: आक्रामक पौधों का विस्तार

SOURCE:THE HINDU

अफ़ीम

संदर्भ: हाल की रिपोर्टें अफ़ीम के पौधों के उत्पादन के लिए अनिश्चित भविष्य दिखाती हैं।

पृष्ठभूमि:-

- मध्य प्रदेश और राजस्थान के तीन जिले मिलकर भारत के 80% अफ़ीम उत्पादन में योगदान करते हैं।

अफीम के बारे में:-

IMAGE SOURCE: pinterest.co.uk

- अफ़ीम खसखस से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है और इसके व्युत्पन्न का उपयोग मुख्य रूप से दर्द प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- खसखस, खसखस परिवार (पापावेरेसी) के कई फूलों वाले पौधों में से कोई, विशेष रूप से जीनस पापावेर की प्रजाति है।
- अधिकांश खसखस उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और खसखस की कई प्रजातियों की खेती बगीचे के सजावटी पौधे के रूप में की जाती है।
- अफ़ीम, जिससे मॉर्फ़ीन, हेरोइन, कोडीन और पैपावेरिन प्राप्त होते हैं, अफ़ीम पोस्ता (पापावर सोम्निफ़ेरम) के कच्चे बीज कैप्सूल में दूधिया लेटेक्स से आता है, जो तुर्की का मूल निवासी है।

उपयोग:-

- अफ़ीम पोस्त के अर्क जैसे मॉर्फ़ीन शक्तिशाली दर्द निवारक हैं और मुख्य रूप से कैंसर रोगियों के लिए निर्धारित हैं।
- अफ़ीम उत्पाद कोडीन खांसी को कम करने में सहायक है।
- इसका उपयोग अवैध रूप से धूम्रपान, शराब पीने या यहां तक कि टिकए के रूप में खाने के लिए भी किया जाता है।

भारत में अफ़ीम की खेती:-

- भारत में इसकी खेती 15वीं शताब्दी से होती आ रही है।
- मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफ़ीम की खेती पर एकाधिकार कर लिया।
- स्वतंत्रता के बाद, अफ़ीम की खेती और व्यापार पर भारत सरकार का नियंत्रण था।
- वर्तमान नियमों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और नियम शामिल हैं।
- पारंपरिक अफ़ीम उगाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
- भारत वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित सुविधाओं पर केवल अफ़ीम गोंद से एल्कलॉइड निकालता है।

MUST READ: Drug Addiction

SOURCE:THE HINDU

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

संदर्भ: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और प्रोत्साहन प्रकाशित किए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- मिशन के तहत, घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप हेतु 17,490 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2021 में
- मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

उद्देश्य:-

- भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।
- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (एनएचएम) का हिस्सा होना।
- भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- हरित हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करना।
- उभरते अंतिम-उपयोग क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना।
- हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सक्षम नीति ढांचा विकसित करना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सुविधा प्रदान करना।
- लक्ष्य-उन्मुख, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है।

हरित हाइड्रोजन संक्रमण (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के बारे में:-

- यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक उपघटक है।
- उद्देश्य: घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)।
- प्रारंभिक चरण में, 2029-30 तक 17,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रस्तावित किए गए थे:
    - इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन
    - हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

अवश्य पढ़ें: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा

SOURCE:DOWN TO EARTH

ई – कचरा

संदर्भ: हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 में 500,000 टन से अधिक ई-कचरा एकत्र और संसाधित किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 527,131.57 टन ई-कचरा एकत्र, नष्ट और पुनर्चक्रित किया गया।

ई-कचरे के बारे में:-

- ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक-कचरा का संक्षिप्त रूप है और इस शब्द का उपयोग पुराने, समाप्ति तिथि वाले या बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, हिस्से और स्पेयर शामिल हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसे ई-कचरा भी कहा जाता है, ये बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विभिन्न रूप हैं जो अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं या अब उनके मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं।
- ई-कचरा खतरनाक नहीं होते है यदि इसे वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्चक्रित करके सुरक्षित भंडारण में रखा जाता है या औपचारिक क्षेत्र में भागों या समग्रता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।

भारत में ई-कचरा:-

- भारत में सालाना 18.5 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें मुंबई और दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा योगदान है।
- वर्ष 2018 तक यह आंकड़ा सालाना 30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- अन्य प्रमुख शहरों में बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर शामिल हैं।
- महाराष्ट्र सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पन्न करने वाला राज्य है, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं।
- विकसित देशों से आधे से अधिक ई-कचरा विकासशील देशों को निर्यात किया जाता है।
- विकासशील देशों में पुनर्चक्रण में अक्सर मैन्युअल भागीदारी शामिल होती है, जिससे श्रमिक विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016:

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित।
- ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 को हटा दिया गया।
- इसका उद्देश्य ई-कचरे से उपयोगी सामग्री को पुनर्प्राप्त करना और उसका पुन: उपयोग करना है।
- उत्पादकों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) का परिचय दिया गया।
- निर्माता ई-कचरा संग्रहण और विनिमय के लिए उत्तरदायी होता हैं।
- निर्माता, डीलर, ई-रिटेलर्स और रिफर्बिशर्स भी इसमें शामिल हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय ई-कचरे को एकत्र करने और अधिकृत विखंडनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

MUST READ:Extended Producer Responsibility
SOURCE:DOWN TO EARTH

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन

संदर्भ: हाल ही में इसरो का PSLV-C58 XPoSat मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नए साल में XPoSat और 10 अन्य पेलोड ले जाने वाले PSLV-C58 का सफल प्रक्षेपण किया।

इसरो के PSLV-C58 XPoSatmission के बारे में:-

- लॉन्च तिथि: 01 जनवरी, 2024
- लॉन्च का समय: 09:10 बजे IST
- XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) आकाशीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष-आधारित ध्रुवीकरण माप में शोध करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है।
- सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन को IMS-2 बस प्लेटफ़ॉर्म से संशोधित किया गया है।
- मेनफ्रेम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन IRS उपग्रहों की विरासत के आधार पर तैयार किया गया है।
- यह दो पेलोड अर्थात् POLIX (एक्स-रे में पोलारिमीटर उपकरण) और XSPECT (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग) ले जाता है।
    - POLIX को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा साकार किया गया है
    - XSPECT URSC के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप द्वारा है।
- इस मिशन के उद्देश्य हैं:-
- POLIX पेलोड द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के माध्यम से लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाले ऊर्जा बैंड 8-30keV में एक्स-रे के ध्रुवीकरण को मापने के लिए।
- XSPECT पेलोड द्वारा ऊर्जा बैंड 0.8-15keV में ब्रह्मांडीय एक्स-रे स्रोतों का दीर्घकालिक वर्णक्रमीय और अस्थायी अध्ययन करना।
- सामान्य ऊर्जा बैंड में क्रमशः POLIX और XSPECT पेलोड द्वारा ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का ध्रुवीकरण और स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप करना।

अवश्य पढ़ें: अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (NGLV)

SOURCE: TIMES OF INDIA

R21 वैक्सीन

संदर्भ: हाल ही में, WHO ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को प्रीक्वालिफाइड कर दिया।

पृष्ठभूमि:-

- अक्टूबर 2023 में, WHO ने टीकाकरण पर WHO के रणनीतिक सलाहकार समूह (SAGE) और मलेरिया नीति सलाहकार समूह की सलाह के बाद, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इसके उपयोग की सिफारिश की।

R21 वैक्सीन के बारे में:-

- विकसित: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित।
- RTS, S/AS 01 के बाद यह दुनिया की दूसरी डब्ल्यूएचओ-अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन है।
- नया टीका मॉस्किरिक्स ब्रांड के तहत बेचा जाएगा।
- यह 75% से अधिक प्रभावशीलता प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन है।
- इसे 5-36 महीने की आयु के बच्चों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, यह आयु वर्ग मलेरिया से मृत्यु का सबसे अधिक जोखिम है।
- घाना पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसने वैक्सीन को मंजूरी दी।

लाभ:-

- उच्च प्रभावकारिता, कम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता

MUST READ:iNCOVACC
SOURCE: THE HINDU

आइंस्टीन प्रोब

संदर्भ: हाल ही में, चीन ने ब्रह्मांड में आतिशबाजी की तरह टिमटिमाती रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब नामक एक नया खगोलीय उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा।

पृष्ठभूमि:-

- यह एक्स-रे के विस्फोटों के लिए आकाश को फ़िल्टर करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोब है जो ब्लैक होल और विलय तारों से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने में मदद कर सकता है, इसने हाल ही में उड़ान भरा।

इसके बारे में:-

- लॉन्च किया गया: चीन के सिचुआन प्रांत में ज़िचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर।
- वजन: लगभग 1.45 टन। ईपी अत्याधुनिक एक्स-रे डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करता है।
- कमल से प्रेरित डिज़ाइन में 12 'पंखुड़ियाँ' हाउसिंग वाइड-फील्ड एक्स-रे टेलीस्कोप (डब्ल्यूएक्सटी) और दो 'स्टेमेन्स' शामिल हैं जिनमें फॉलो-अप एक्स-रे टेलीस्कोप (एफएक्सटी) शामिल हैं।
- दो 'स्टेमेन्स' में फॉलो-अप एक्स-रे टेलीस्कोप (एफएक्सटी) शामिल हैं, जो गहन अवलोकन और क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- साथ में, ये घटक एक अंतरिक्ष वेधशाला का निर्माण करते हैं जिसका प्राथमिक उद्देश्य सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान उत्सर्जित प्रारंभिक प्रकाश को कैप्चर और ब्रह्मांड के बाहरी किनारे पर क्षणिक खगोलीय पिंडों की प्रकृति की खोज करना है।
- यह पांच साल के जीवनकाल के साथ डिज़ाइन किया गया, आइंस्टीन प्रोब खगोलीय टाइम -डोमेन अवलोकन विधि को नियोजित करता है, जो सॉफ्ट एक्स-रे बैंड में उच्च-संवेदनशीलता वास्तविक समय गतिशील आकाश सर्वेक्षण का संचालन करता है।

अवश्य पढ़ें: अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी)

स्रोत: CNN

एक्सोप्लैनेट WASP-121

संदर्भ: हाल ही में, खगोलविदों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक अभूतपूर्व खोज की है, जिसमें पृथ्वी से 880 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुदूर एक्सोप्लैनेट WASP-121 b पर बड़े पैमाने पर चक्रवात और गतिशील मौसम गतिविधि का पता चला है।

पृष्ठभूमि:-

- खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए 2016, 2018 और 2019 के हबल डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

WASP-121 b के बारे में:-

- WASP-121 b एक गैस जायंट है, जिसका आकार बृहस्पति के समान है।
- जैसा कि हम जानते हैं, इसका वातावरण जीवन के लिए बहुत प्रतिकूल है।
- यह विदेशी दुनिया पर वायुमंडलीय गतिशीलता को समझने का केंद्र बिंदु बन गया है।
- WASP-121 b अपने तारे से मजबूती से लॉक्ड है, जिसका अर्थ है कि एक गोलार्ध लगातार ऊष्मा का सामना करता है, जो लगभग 3,450 डिग्री फ़ारेनहाइट के झुलसा देने वाले तापमान तक पहुँच जाता है।

हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में:-

- लॉन्च: 24 अप्रैल, 1990, द्वारा लॉन्च: डिस्कवरी।
- हबल स्पेस टेलीस्कोप NASA/ESA की एक बड़ी, अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला है।
- इसे 1990 से तैनात किया गया है।
    - **नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA):** यह अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है।
    - **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए):** एक स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है।

- हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित पहली खगोलीय वेधशाला है, जिसमें पराबैंगनी से निकट-अवरक्त तक फैले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में छवियों को रिकॉर्ड करने की क्षमता है।
- हबल पृथ्वी की सतह से लगभग 340 मील (547 किमी) ऊपर परिक्रमा करता है।

MUST READ:IN-SPACe
SOURCE:INDIA TODAY

नासा की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला

संदर्भ: नासा के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने हाल ही में 30 डोरैडस B में मेगास्टार विस्फोटों को कैप्चर किया।
पृष्ठभूमि:-

- हल्के एक्स-रे के विस्तृत आवरण से संकेत मिलता है कि एक और सुपरनोवा 5,000 साल से भी पहले हुआ था, और संभवतः उससे भी पहले।

नासा की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के बारे में:-

- प्रक्षेपण: 23 जुलाई 1999, अवधि: 23 वर्ष
- चंद्रा एक्स-रे वेधशाला विश्व की सबसे शक्तिशाली एक्स-रे दूरबीन है।
- यह हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिटाइज़र स्पेस टेलीस्कोप और अब डीऑर्बिटेड कॉम्पटन गामा रे वेधशाला के साथ नासा के "महान वेधशालाओं" के बेड़े का हिस्सा है।
- दूरबीन का नाम भारतीय खगोल वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चन्द्रशेखर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था।
- यह ब्रह्मांड की कुछ अजीब वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे की जांच करता है, जिसमें क्वासर, गैस और धूल के विशाल बादल और ब्लैक होल में समाए कण शामिल हैं।

30 डोरैडस B के बारे में:-

- 30 डोरैडस B, एक सुपरनोवा अवशेष है जो अंतरिक्ष के एक जीवंत क्षेत्र का हिस्सा है जहां लाखों वर्षों से तारे बन रहे हैं।
  - सुपरनोवा एक विनाशकारी घटना है जो किसी विशाल तारे के जीवन चक्र के अंत में घटित होती है।
- यह खगोलीय दृश्य, पृथ्वी से लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- यह गैस के काले बादलों, नये तारों, उच्च-ऊर्जा शॉट और अत्यधिक गर्म गैस का एक जटिल परिदृश्य है।
- आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के स्थानीय समूह में तारा निर्माण का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षेत्र 30 डोरैडस (या, अनौपचारिक रूप से, टारेंटयुला नेबुला) कहा जाता है।
- यह बड़े मैगेलैनिक बादल में स्थित है, जो आकाशगंगा की एक छोटी पड़ोसी आकाशगंगा है।
- 30 डोरैडस का लंबे समय से खगोलविदों द्वारा अध्ययन किया गया है जो बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं कि सूर्य जैसे तारे कैसे उत्पन्न और विकसित होते हैं।

MUST READ:The North Star
SOURCE:INDIA TODAY

चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर (SLIM)

संदर्भ: जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून (एसएलआईएम) हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा।
पृष्ठभूमि:-

- SLIM 20 जनवरी 2024 को सुबह 0:20 बजे (JST) चंद्रमा की सतह पर उतरा।
- लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष यान से संचार स्थापित हो गया है।

SLIM (चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर) के बारे में:-

- लॉन्च तिथि: 7 सितंबर, 2023। लॉन्च स्थान: JAXA तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में योशिनोबु लॉन्च कॉम्प्लेक्स। लॉन्च वाहन: H-IIA लॉन्च वाहन संख्या 47।
- एजेंसी: जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)।

- SLIM जापान का पहला चंद्र सतह मिशन है। (चंद्रयान-2)
- SLIM (चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर) परियोजना भविष्य की चंद्र जांच के लिए आवश्यक पिनपॉइंट लैंडिंग तकनीक पर शोध करने और छोटे पैमाने की जांच के साथ चंद्रमा की सतह पर इसे सत्यापित करने के लिए एक मिशन है।
- SLIM हल्का है क्योंकि यह बहुत कम ईंधन वहन करता है। इसने गतिज ऊर्जा बनाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया, अंततः धीमी गति से पहुंचने और कैप्चर करने के लिए चंद्रमा के साथ अपने प्रक्षेप पथ को संरेखित किया।
- यह एक बार जब यह चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा, तो यह पृथ्वी और चंद्रमा की संयुक्त ताकतों द्वारा गहरे अंतरिक्ष में विक्षेपित हो जाएगा।
- सॉफ्ट लैंडिंग पर, एसएलआईएम लूनर एक्सकर्शन व्हीकल (एलईवी) 1 और 2 नामक 2 छोटे रोवर तैनात करेगा।
- ये लैंडिंग पॉइंट के पास चंद्र सतह का अध्ययन करेंगे, तापमान और विकिरण रीडिंग एकत्र करेंगे, और चंद्रमा के आवरण का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

अवश्य पढ़ें: चंद्रयान-3

SOURCE:THE HINDU

सॉवरेन AI

संदर्भ: हाल ही में, भारत अपना खुद का 'सॉवरेन AI' बना रहा है।

पृष्ठभूमि:-

- भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जिसने बड़े पैमाने पर शासन समाधान विकसित करने और वितरित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

सॉवरेन एआई और भारत की भूमिका

- सॉवरेन एआई अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एआई प्रौद्योगिकियों पर एक राष्ट्र के नियंत्रण को संदर्भित करता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, नैतिक AI उपयोग सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण AI बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण बनाए रखना है।
- सरकार को नैतिक मानकों, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई अनुसंधान, विकास और तैनाती के लिए नीतियां, कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है।
- भारत का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन और भाषा अनुवाद में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने स्वयं के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करते हुए, सॉवरेन एआई स्थापित करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने केंद्र सरकार की संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत और अज्ञात डेटासेट को रखने के लिए एक भारतीय डेटासेट प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा है।

MUST READ:ChatGPT and the AI challenge

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

हेल्थ

वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस

संदर्भ: हाल ही में, अर्जेंटीना में वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस का प्रकोप हुआ।

पृष्ठभूमि:-

- वर्तमान प्रकोप अर्जेंटीना और उरुग्वे में घोड़ों में चल रहे प्रकोप के संदर्भ में भी आता है।

वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस के बारे में:-

- यह मच्छर जनित संक्रमण है।
- यह वेस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV) के कारण होता है, जो गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों वाले वायरस के टोगाविरिडे परिवार से संबंधित है, और इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- वायरस में लगभग 11.5 किलोबेस सिंगल-स्टैण्डर्ड RNA जीनोम होता है और यह पूर्वी इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (ईईईवी) और सिंदबिस-जैसे वायरस का पुनः संयोजक है।
- पसेरिन पक्षियों को जलाशय और घोड़े की प्रजातियों को मध्यवर्ती मेजबान माना जाता है।

वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस (WEE) लक्षण और संचरण

- लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मतली, उल्टी, कम भूख, थकान और कमजोरी शामिल हैं।
- प्राथमिक संचरण संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है, क्यूलेक्स टार्सालिस इसका मुख्य वाहक है।
- गैर-विशिष्ट नैदानिक प्रस्तुति के कारण निदान के लिए प्रयोगशाला पुष्टि की आवश्यकता होती है।
- पश्चिमी और मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में सबसे आम है।

अवश्य पढ़ें: मलेरिया

SOURCE:THE HINDU

केटामाइन

संदर्भ: हाल ही में अभिनेता मैथ्यू पेरी की मौत में केटामाइन दवा शामिल होने की जानकारी मिली थी।

पृष्ठभूमि:-

- हाल के वर्षों में, अवसाद और अन्य गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए केटामाइन अपने बढ़ते उपयोग के कारण व्यापक बहस का विषय रहा है।

केटामाइन के बारे में:-

- अमेरिकी औषधि प्रवर्तन प्रशासन द्वारा एक संवेदनाहारी को हेलुसीनोजेन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- फेनसाइक्लिडीन (पीसीपी) से प्राप्त, एक हेलुसीनोजेनिक दवा है।
- मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एनएमडीए रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है।
- न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज को बढ़ाता है।
- चिकित्सा-प्रतिरोधी रोगियों में मानसिक बीमारियों का इलाज करता है।
- आनंद या मन में बदलाव के लिए एक मनोरंजक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
- इनके प्रकारों में शामिल हैं:
  - o उत्तेजक: सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाना। जैसे, कोकीन, मेथमफेटामाइन और कैफीन।
  - o अवसाद: यह शांत प्रभाव उत्पन्न करता हैं। जैसे, शराब, मारिजुआना, और बेंजोडायजेपाइन।
  - o हेलुसीनोजेन्स: यह मतिभ्रम उत्पन्न करता हैं। जैसे, एलएसडी, साइलोसाइबिन और डीएमटी।

अनुप्रयोग:-

- इसे साइकेडेलिक गुणों के साथ एक विघटनकारी संवेदनाहारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- इसका उपयोग एनेस्थीसिया के लिए चिकित्सकीय देखरेख में सख्ती से किया जाता है।
- अवसाद, चिंता, पीटीएसडी, इंड ऑफ़ लाइफ डिस्ट्रेस, दीर्घकालिक दर्द और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्थितियों के उपचार में भी नियोजित किया जाता है।

भारत में नियामक स्थिति:-

- इसे भारत में अनुसूची X दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर द्वारा मामले-विशिष्ट आधार पर कड़े नियंत्रण और निगरानी के अधीन है।
    - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत अनुसूची X दवाओं को "प्रतिबंधात्मक दवाओं" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष)
    - अनुसूची X के अंतर्गत दवाओं का वर्गीकरण उच्च स्तर के नियामक नियंत्रण और निगरानी का प्रतीक है।

अवश्य पढ़ें: बिस्फेनॉल A

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

इतिहास, कला एवं संस्कृति

वारली पेंटिंग

सन्दर्भ: हाल ही में इनहेरिटेड आर्ट्स फोरम द्वारा वारली पेंटिंग की एक प्रदर्शनी लगी।

पृष्ठभूमि:-

- इसमें प्रसिद्ध माशे परिवार की कलात्मक यात्रा और वारली पेंटिंग को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास का पता लगाया गया।

वारली पेंटिंग के बारे में:-

- वारली आर्ट महाराष्ट्र की एक लोक चित्रकला है।
- यह 10वीं शताब्दी ई.पू. की है।
- वारली शब्द सबसे बड़ी जनजाति से प्रेरित है, जो मुंबई, महाराष्ट्र के उत्तरी बाहरी इलाके में पाई जाती है।
- चित्रकला की यह कला मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्रि पर्वतमाला में रहने वाली जनजातियों द्वारा प्रचलित है।
- इस आदिवासी कला की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई, जहां इसने अभी भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।
- यह परंपरागत रूप से वार्ली जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता था जिन्हें सुवासिनिस कहा जाता था, जो लगन चौक या विवाह चौक को सजाती थीं।
- ये पेंटिंग अपनी ज्वलंत विरोधाभासी अभिव्यक्तियों के कारण विशिष्ट हैं।
- इन चित्रों में मुख्य रूप से वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का प्रभुत्व है।
- थीम: वारली ग्रामीण जीवन की दैनिक दिनचर्या, प्रकृति के साथ आदिवासी लोगों के रिश्ते, उनके देवताओं, मिथकों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और उत्सवों का प्रतिनिधित्व करता है।

MUST READ:Mural Art
SOURCE:THE HINDU

दिव्य कला शक्ति

संदर्भ: हाल ही में, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने अहमदाबाद में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, "दिव्य कला शक्ति" प्रस्तुत किया।

पृष्ठभूमि:-

- इस कार्यक्रम में पूरे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें कुल 100 दिव्यांग व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के साथ मंच संभाला।

दिव्य कला शक्ति के बारे में:-

- प्रारंभ: वर्ष 2019 में
- आयोजक: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- दिव्य कला शक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक और अनूठा मंच प्रदान करता है।

महत्व:-

- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों में आत्मविश्वास विकसित करना है।

अवश्य पढ़ें: विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा
SOURCE:PIB

श्रीमुखलिंगम मंदिर

संदर्भ: हाल ही में, एएसआई ने आंध्र प्रदेश के श्रीमुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर संरचनाओं की सूची में शामिल करने पर यूनेस्को को एक नोट भेजने का आश्वासन दिया।

पृष्ठभूमि:-

- श्रीमुखलिंगम मंदिर के मुख्य पुजारी नायडूगारी राजशेखर का कहना है कि मंदिर की वास्तुकला ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर के समान है।

श्रीमुखलिंगम मंदिर के बारे में:-

- इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ई. में किया गया था।
- इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजाओं ने करवाया था।
- पूर्वी गंगा राजवंश, जिसे चोडागांगस के नाम से भी जाना जाता है, ने 11वीं-15वीं शताब्दी तक कलिंग (वर्तमान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश) पर शासन किया था।
- यह वंशधारा नदी पर स्थित है।
- यह भगवान श्रीमुखलिंगेश्वर (शिव का एक रूप) को समर्पित है।
- यहां के शिवलिंग में भगवान शिव का मुख या चेहरे का प्रतिनिधित्व है।
- इसमें उस काल की उत्कृष्ट मूर्तियां शामिल हैं।
- यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर के समान कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है।
- उत्तरी भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली को मिलाकर कलिंग वास्तुकला का निर्माण किया गया।

अवश्य पढ़ें: खजुराहो के मंदिर

MUST READ:Khajuraho temples

SOURCE:THE HINDU

बोब्बिली वीणा

संदर्भ: हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि बोब्बिली वीणा कारीगर आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि:-

- तमिलनाडु के तंजावुर की तरह, विजयनगरम जिले का बोब्बिली शहर उच्च गुणवत्ता वाली वीणा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

बोब्बिली वीणा अवलोकन

- विशाखापत्तनम से लगभग 120 किमी दूर बोब्बिली, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- इसे 'सरस्वती वीणा' के नाम से भी जाना जाता है।
- कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला बड़ा तार वाला वाद्य यंत्र है।
- यह 17वीं शताब्दी में बोब्बिली संस्थानम के राजा पेद्दा रायडू द्वारा बनाया गया।
- कटहल, सागौन, या महोगनी सहित विश्वनीय लकड़ी से तैयार किया गया।
- इसमें जटिल नक्काशी के साथ एक गुंजयमान यंत्र, नेक और तार होता हैं।
- मध्य भाग में पतले सिरे पर शेर का सिर बना होता है।
- यह सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बोब्बिली और विजयनगरम जिले की कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्ष 2011 में भारत सरकार से भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ।

अवश्य पढ़ें: संगीत नाटक अकादमी

SOURCE:THE HINDU

कपडगंडा शॉल

संदर्भ: हाल ही में, ओडिशा के कपडागंदा शॉल को जीआई टैग मिला।

पृष्ठभूमि:-

- ओडिशा के सात उत्पादों, जिनमें लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमिलिपाल काई चटनी से लेकर कढ़ाईदार कपडागंडा शॉल तक शामिल हैं, ने राज्य के लिए उनकी विशिष्टता की मान्यता में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल किया है।

कपडगंडा शॉल अवलोकन

- ओडिशा से उत्पन्न, डोंगरिया कोंध जनजाति की महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई किया गया।
- डोंगरिया कोंध की समृद्ध आदिवासी विरासत का प्रतीक है।
- मटमैले सफेद मोटे कपड़े पर लाल, पीले और हरे धागों से की गई कढ़ाई है।

- हरा रंग पर्वत और पहाड़ियों का प्रतीक है।
- पीला रंग शांति और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है।
- लाल रक्त का प्रतीक है।
- मोटिफ्स ज्यादातर रेखाएं और त्रिकोण हैं जो पर्वतीय महत्व को दर्शाते हैं।
- यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहनने योग्य होते है।
- डोंगरिया इसे प्यार की निशानी के रूप में उपहार में देते हैं।

अवश्य पढ़ें: (पश्मीना शॉल)

SOURCE:THE INDIAN EXPRESS

जगन्नाथ मंदिर

संदर्भ: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना 17 जनवरी 2024 को जनता के लिए खुली रहेगी।

पृष्ठभूमि:-

- मंदिर विरासत गलियारा भक्तों और मंदिर के बीच दृश्य संबंध को बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

जगन्नाथ मंदिर के बारे में:-

- इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के अनातवर्मन चोड गंग ने करवाया था।
- इसका पुनर्निर्माण सदियों बाद गजपति जैसे बाद के शासकों द्वारा किया गया था।
- ऐसा माना जाता है कि यह राजा इंद्रद्युम्ना से जुड़े एक पुराने मंदिर का स्थान है।
- चार धाम के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है।
- यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को समर्पित है।
- भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं।
- इस मंदिर को "व्हाइट पैगोडा" कहा जाता था और यह चार धाम तीर्थयात्राओं (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
- यह चार धाम सर्किट का एक हिस्सा है, जिसे "यमानिका तीर्थ" कहा जाता है।
- अद्वितीय लकड़ी के देवताओं को समय-समय पर बदला जाता है।
- मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के तीन मुख्य देवताओं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर एक भव्य जुलूस में निकाला जाता है।
- यह मंदिर अपने अनूठे भोजन प्रसाद, महाप्रसाद के लिए भी जाना जाता है।

वास्तुकला:-

- मंदिर एक ऊंचे मंच पर आंतरिक आंगन के केंद्र में स्थित है।
- इसके चार घटक हैं:-
  - o विमान या देउला (गर्भगृह)
  - o जगमोहन
  - o नटमंडप
  - o भोगमंडप
- जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली दो प्रकारों-रेखा और पिधा का संयोजन है।
- इसमें चार जटिल नक्काशीदार द्वार हैं।
- नीला चक्र, अरुणा स्तम्भ जैसी इसकी अन्य विशेषताएं है।
  - o नीला चक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थित है और चक्र पर प्रतिदिन एक अलग ध्वज फहराया जाता है, जिसे पतित पावना नाम दिया गया है।

अवश्य पढ़ें: सोमनाथ मंदिर

SOURCE:AIR

महायोगी वेमना

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेमना जयंती के अवसर पर महायोगी वेमना को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री ने X पर पोस्ट किया: "आज, वेमना जयंती पर, हम महायोगी वेमना के कालातीत ज्ञान (timeless wisdom) को याद करते हैं।

उनके छंद और गहन शिक्षाएँ हमें सच्चाई, सादगी और आंतरिक शांति के जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हुए प्रबुद्ध और प्रेरित करती रहती हैं। उनके व्यावहारिक कार्य दुनिया भर में गूंजते हैं और उनकी शिक्षाएँ एक बेहतर ग्रह की तलाश में हमारे मार्ग को रोशन करती हैं।

महायोगी वेमना के बारे में:-

- वे आंध्र प्रदेश में एक संत थे।
- वेमना का जन्म आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गांडीकोटा में हुआ था।
- वह एक भारतीय दार्शनिक और तेलुगु भाषा के कवि थे।
- वे अचलयोगी, कवि, समाज सुधारक थे।
- उनकी कविताएँ सरल भाषा और देशी मुहावरों के प्रयोग के लिए जानी जाती हैं।
- वे योग, ज्ञान और नैतिकता के विषयों पर चर्चा करते हैं।
- उनकी कविताएँ विभिन्न विषयों का अनुसरण करती हैं: सामाजिक, नैतिक, व्यंग्यात्मक और रहस्यमय।
- उनमें से अधिकांश अटावेलडी (नृत्य करने वाली महिला) मीटर में हैं।
- उल्लेखनीय कार्य:-
  o वेमनसातकम्

अवश्य पढ़ें: संत रविदास

SOURCE:PIB

अमृत उद्यान

संदर्भ: अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा।

पृष्ठभूमि:-

- लोग सोमवार को छोड़कर, जो रखरखाव के दिन हैं, सप्ताह में छह दिन उद्यान में जा सकते हैं।

अमृत उद्यान के बारे में:-

- आजादी का अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया गया।
- लगभग 15 उद्यानों के समूह को सामूहिक रूप से अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- वर्ष 1911 में, अंग्रेजों ने भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
- वायसराय हाउस के निर्माण के लिए लगभग 4,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और सर एडविन लुटियंस को रायसीना हिल पर इमारत को डिजाइन करने का काम सौंपा गया था।
- जबकि प्रारंभिक योजनाओं में पारंपरिक ब्रिटिश संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक उद्यान बनाना शामिल था, तत्कालीन वायसराय की पत्नी लेडी हार्डिंग ने योजनाकारों से मुगल शैली का उद्यान बनाने का आग्रह किया।

विशेषणिक विशेषताएं:-

- मुगल गार्डन (अब पूर्ववर्ती) जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन, ताज महल के आसपास के उद्यान और भारत तथा फारस के लघु चित्रों से प्रेरणा लेते हैं।
- ये अपनी 'चारबाग शैली' के लिए जाने जाते हैं। बाबर नामा में, बाबर ने दावा किया कि यह उसका पसंदीदा प्रकार का बगीचा है।
- इन उद्यानों को उनके आयताकार लेआउट द्वारा परिभाषित किया गया है, इन्हें चार समान खंडों में विभाजित किया गया है, और इन्हें पहले मुगलों द्वारा शासित भूमि पर पाया जा सकता है।
- दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के आसपास के बगीचों से लेकर श्रीनगर में निशात बाग तक, सभी इसी शैली में बने हैं।
- इन उद्यानों की एक परिभाषित विशेषता जलमार्गों का उपयोग है, जो अक्सर बगीचे के विभिन्न चतुर्थांशों का सीमांकन करने के लिए किया जाता है।

MUST READ:Akbar

SOURCE:PIB

कौशल भवन

संदर्भ: हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न पहलों जैसे पीएम विश्वकर्मा, पीएम जनमन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के लाभार्थियों द्वारा स्थापित प्रदर्शनी स्टालों का दौरा किया और उनके साथ बातचीत की।

कौशल भवन के बारे में:-

- स्थान: नई दिल्ली में
- कौशल भवन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई इमारत है।
- इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी।
- यह मंत्रालय के साथ-साथ इसके सहयोगी संगठनों - प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगा।
- यह अत्याधुनिक कार्यालय भवन, आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है।
- इसे नई कार्य संस्कृति की शुरुआत करने और कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और कुशल कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

अवश्य पढ़ें: होयसल मंदिर

SOURCE:PIB

हज़रत निज़ामुद्दीन औलियादरगाह

संदर्भ: हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह का दौरा किया।

पृष्ठभूमि:-

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज के दौरान, मैक्रॉन ने अपने प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक मित्रता की पुष्टि की।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के बारे में:-

- हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है।
- यह प्रसिद्ध सूफी संत, निज़ामुद्दीन औलिया (1238-1325 ई.) का मकबरा है।
    - सैयद मुहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे।
    - हज़रत निज़ामुद्दीन और महबूब-ए-इलाही (भगवान के प्रिय) के रूप में भी जाने जाते हैं, वह एक सुन्नी मुस्लिम विद्वान और चिश्ती आर्डर के सूफी संत थे।
- इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था।
- इसमें एक वर्गाकार कक्ष है जो बरामदों से घिरा हुआ है, जो धनुषाकार छिद्रों से छिद्रित हैं।
- गुंबद को काले संगमरमर की खड़ी धारियों से अलंकृत किया गया है और इसके शीर्ष पर कमल-शिखा (lotus-cresting) है।
- दरगाह के उत्तर की ओर एक बावड़ी है।

अवश्य पढ़ें: अजमेर शरीफ दरगाह

SOURCE:TIMES OF INDIA

डिफेन्स एंड सिक्योरिटी

CV-22B ऑस्प्रे विमान

संदर्भ: हाल ही में, गोताखोरों ने दक्षिण-पश्चिमी जापान के पास दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी वायु सेना CV-22B ऑस्प्रे विमान के मलबे और चालक दल के सदस्यों के अवशेषों की खोज की।

पृष्ठभूमि:-

- जापान के याकुशिमा द्वीप के तट पर अमेरिकी विशेष अभियान विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है।

CV-22B ऑस्प्रे विमान के बारे में:-

- इसे दुनिया भर में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, अमेरिकी वायु सेना और अमेरिकी नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था।
- इसका निर्माण अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किया है।
- यह एक बहु-इंजन, दोहरे पायलट वाला, स्व-तैनाती, मध्यम-लिफ्ट विमान है।
- इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की घुसपैठ, घुसपैठ, मध्यम दूरी के हमले, विशेष अभियान, वीआईपी परिवहन, पुनः आपूर्ति, आपदा राहत, खोज-और-बचाव, चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशन सहित कई प्रकार के मिशनों के लिए किया जाता है।
- यह एक हेलीकॉप्टर के ऊर्ध्वाधर टेकऑफ़, होवर और ऊर्ध्वाधर लैंडिंग गुणों को एक टर्बोप्रॉप विमान की लंबी दूरी, ईंधन दक्षता और गति विशेषताओं के साथ जोड़ता है।
- यह डुअल रोल्स-रॉयस लिबर्टी AE1107C इंजन से लैस है। विमान के अंदर 24 लोग बैठ सकते हैं।

अवश्य पढ़ें: उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए)

SOURCE: TIMES OF INDIA

डेजर्ट साइक्लोन 2024

संदर्भ: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन 2024' हाल ही में शुरू हुआ।

पृष्ठभूमि:-

- विदेश मंत्रालय ने कहा, रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्र रक्षा उपकरणों का उत्पादन और विकास हैं; सशस्त्र बलों के संयुक्त अभ्यास, विशेषकर नौसैनिक अभ्यास; रणनीति और सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना; इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर आदि के संबंध में तकनीकी सहयोग।

डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में:-

- दिनांक 2 से 15 जनवरी 2024 तक
- स्थान: महाजन, राजस्थान
- उद्देश्य: साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करना और दो मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना।
- यह अभ्यास शहरी प्रशासन पर विशेष ध्यान देने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया।
- दो सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम को शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करने की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और यूएई सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- यूएई दल का प्रतिनिधित्व जायद फर्स्ट ब्रिगेड के सैनिकों द्वारा किया गया।
- 45 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया गया।
- यह अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती और विश्वास के बंधन को और मजबूत करने का प्रतीक है।

अवश्य पढ़ें: भारत-यूएई संबंध

SOURCE: AIR

INS चेन्नई

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री गश्ती विमान (एमपीए) P8I और आईएनएस चेन्नई सहित अपने मिशन-तैनात प्लेटफार्मों को शामिल करके जहाज एमवी लीला नॉरफ़ॉक पर अपहरण के प्रयास का जवाब दिया।

पृष्ठभूमि:-

- उत्तरी अरब सागर में अपहरण के प्रयास को विफल करते हुए, भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो (MARCOS) लाइबेरिया-ध्वजांकित जहाज पर चढ़ गए और "स्वच्छता" अभियान चलाने के बाद 15 भारतीयों सहित 21 चालक दल को बचाया।

आईएनएस चेन्नई के बारे में:-

- निर्मित: मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)
- भारतीय नौसेना में कमीशन: 21 नवंबर, 2016।
- विस्थापन: 7,500 टन से अधिक। अधिकतम गति: 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी/घंटा)
- आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। यह कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (परियोजना 15 ए) का तीसरा और आखिरी जहाज है।
- इसकी लंबाई 163 मीटर है और इसका बीम 17.4 मीटर है।
- यह चार प्रतिवर्ती गैस टरबाइन इंजनों द्वारा संचालित है। यह 350 से 400 लोगों को ले जा सकता है।
- जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है।
- इसमें आधुनिक निगरानी रडार लगा हुआ है।

जरूर पढ़ें: प्रोजेक्ट-15बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक

SOURCE:[THE INDIAN EXPRESS]

सेना दिवस

संदर्भ: हाल ही में सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी है।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री ने x पर पोस्ट किया:
  " सेना दिवस पर, हम अपने सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा और हमारी संप्रभुता को बनाए रखने में उनका पूर्ण समर्पण ही उनकी वीरता का प्रमाण है। वे शक्ति और सौम्यता के स्तंभ हैं।"

भारतीय सेना दिवस के बारे में:-

- भारत हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाता है।
- उद्देश्य: भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ - जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) केएम करिअप्पा और रक्षा बलों की उपलब्धियों का उत्सव मनाना ।
- सेना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया जाता है। भारत 15 जनवरी 2024 को अपना 76वां सेना दिवस मनाएगा।
- भारतीय सेना दिवस 2024 की थीम: राष्ट्र की सेवा में। (रक्षा अधिग्रहण परिषद)
- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य: सेवा परमो धर्म और इसका अर्थ है 'स्वयं से पहले सेवा'।
  - यह दर्शाता है कि सेना के अधिकारी हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
- यह उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उन लोगों के अटूट समर्पण को पहचानने और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदान की सराहना करने का दिन है।
- 1949 से 2022 तक, सेना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में किया गया था। 2023 में दक्षिणी कमान बेंगलुरु में परेड की प्रभारी थी।
- 2024 सेना परेड: इस वर्ष, उत्सव लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगा।

अवश्य पढ़े : सेना को सौंपी गई नई रक्षा प्रणालियाँ

SOURCE:PIB

अभ्यास डेजर्ट नाइट

संदर्भ: हाल ही में, अभ्यास डेजर्ट नाइट शुरू की गई।

पृष्ठभूमि:-

- 23 जनवरी 24 को, भारतीय वायु सेना (IAF) ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (FASF) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) वायु सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया।

अभ्यास डेजर्ट नाइट के बारे में:-

- यह भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और फ्रांसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है।
- फ्रांसीसी भागीदारी में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल थे, यूएई वायु सेना ने एफ -16 को मैदान में उतारा।
- ये विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे से संचालित होते थे।
- IAF दल में Su-30 MKI, MiG-29, जगुआर, AWACS, C-130-J और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान शामिल थे।
- भारतीय FIR में अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान भारत के भीतर के ठिकानों से संचालित हो रहे थे।
- अभ्यास के दौरान हुई बातचीत से प्रतिभागियों के बीच परिचालन संबंधी ज्ञान, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान में मदद मिली।
- इस तरह के अभ्यास भारतीय वायुसेना की शक्ति को प्रदर्शित करने के अलावा, क्षेत्र में बढ़ती राजनयिक और सैन्य बातचीत का संकेत देते हैं।

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अभ्यास:-

- वरुण - नौसेना अभ्यास
- गरुड़ - वायु अभ्यास
- शक्ति - सेना अभ्यास

INS सुमित्रा

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना की आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक मछुआरों को बचाया।

पृष्ठभूमि:-

- सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज (एफवी) इमान का अपहरण कर लिया था।

आईएनएस सुमित्रा के बारे में:-

- डिज़ाइन और निर्माण: गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
- आईएनएस सुमित्रा एक नई पीढ़ी का नौसैनिक अपतटीय गश्ती जहाज है जो चेन्नई में पूर्वी नौसेना कमान में शामिल हुआ है।
- यह भारतीय नौसेना का चौथा और अंतिम सरयू श्रेणी का गश्ती जहाज है।
- यह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। इस जहाज की मारक क्षमता 6,500 समुद्री मील है।
- यह दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। यह एक ध्रुव/चेतक हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में सक्षम है।
- इसे 2014 में कमीशन किया गया था और यह पूर्वी नौसेना कमान के तहत चेन्नई में स्थित है।
- जहाज की प्राथमिक भूमिका देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की निगरानी के अलावा अन्य परिचालन कार्यों जैसे कि समुद्री डकैती विरोधी गश्त, बेड़े समर्थन संचालन, अपतटीय संपत्तियों की समुद्री सुरक्षा और अनुरक्षण संचालन करना है।

अवश्य पढ़ें:NAVDEX 23 और IDEX 23

SOURCE:HINDUSTAN TIMES

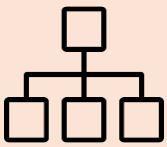

सरकारी पहल, योजनाएँ और नीतियाँ, संगठन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

संदर्भ: हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि नए साल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) श्रमिकों के लिए आधार-लिंक्ड वेतन अनिवार्य कर दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:-

- नए साल से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मजदूरी का भुगतान केवल आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए श्रमिकों के आधार विवरण को उनके जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक है।

इसके बारे में:-

- शुरू किया गया: वर्ष 2005 में
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी)
- उद्देश्य: ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) में सुधार करना, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं:-

- भारतीय कानून 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित हुआ।
- वैधानिक न्यूनतम वेतन पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सालाना 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) द्वारा निगरानी की जाती है।
- इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, छोटे या सीमांत किसानों, भूमि सुधार लाभार्थियों या लाभार्थियों द्वारा लाभार्थी-उन्मुख कार्य किए जा सकते हैं।
- आवेदन जमा करने या मांग के 15 दिनों के भीतर वेतन रोजगार प्रदान किया जाता है।
- 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।

लाभ:-

- मनरेगा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
- मनरेगा कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता प्रदान करता है।
- मनरेगा जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को दूर करने के लिए कार्य करता है।

अवश्य पढ़ें:मनरेगा से जुड़े मुद्दे

SOURCE: THE HINDU

नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम

संदर्भ: हाल ही में मंत्री भूपेन्द्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि:-

- यह पूरे भारत में वन वस्तुओं के परिवहन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है।

परिचय:-

- लॉन्च: 29 दिसंबर 2023
- मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- उद्देश्य: देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन को सुविधाजनक बनाना।

मुख्य विशेषताएं:-

- देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) बनाया गया है।
- वर्तमान में, राज्य-विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं।
- एनटीपीएस की कल्पना "वन नेशन-वन पास" व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी।
- यह पहल देश भर में कृषि वानिकी में शामिल पेड़ उत्पादकों और किसानों के लिए एक एकीकृत, ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारगमन परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

ट्रांजिट परमिट आवेदन की मुख्य विशेषताएं:

- भूमिका-आधारित और वर्कफ़्लो-आधारित एप्लिकेशन डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में उपलब्ध है।
- ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रांजिट परमिट (टीपी) या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) आवेदन जमा करना।
- निजी भूमि पर उगाई गई प्रजातियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को पारगमन पास व्यवस्था से छूट दी गई है।
- प्रजातियों की श्रेणी के आधार पर ट्रांजिट परमिट या एनओसी का ऑनलाइन सृजन।
- ई-भुगतान प्रणाली: टी.पी. डाउनलोड करने से पहले भुगतान मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

लाभ:

- लघु वन उपज के लिए पारगमन परमिट तेजी से जारी करना।
- मैनुअल पेपर-आधारित पारगमन प्रणाली का प्रतिस्थापन।
- भारत में लकड़ी, बांस और लघु वन उपज के पारगमन के लिए एक परमिट।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य की सीमाओं पर सुचारू आवाजाही।
- कृषि वानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- परिवहन लागत और समय की बचत।

अवश्य पढ़ें: बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

सागर परिक्रमा

संदर्भ: हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां चरण चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ।

पृष्ठभूमि:-

- सागर परिक्रमा का दसवां चरण हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने संयुक्त रूप से इस मिशन का उद्घाटन किया जो नेल्लोर, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम से होकर गुजरेगा।

सागर परिक्रमा के बारे में:-

- मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- पहला चरण शुरू: 5 मार्च 2022।
- प्रथम चरण का स्थान: मांडवी, गुजरात।
- आयोजित: मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ-साथ-
  - o मत्स्य पालन विभाग, गुजरात सरकार,
  - o भारतीय तट रक्षक,
  - o भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण,
  - o गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और
  - o मछुआरों के प्रतिनिधि।
- उद्देश्य: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों तथा हितधारकों की आर्थिक संभावनाओं को ऊपर उठाते हुए उनके सामने आने वाली चुनौतियों का

समाधान करना।

- सागर परिक्रमा सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है।
- इसकी कल्पना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सलाम करते हुए 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में की गई है।
- परिक्रमा में राज्य के मत्स्य अधिकारी, मछुआरे प्रतिनिधि, फिश फार्मर उद्यमी, हितधारक, पेशेवर, अधिकारी और देश भर के वैज्ञानिक शामिल होंगे।
- इसे गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह से पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से मनाया जाना है।

महत्व:-

- सागर परिक्रमा कार्यक्रम 75वें "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है।
- यह तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने की एक पहल है।
- यह सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा

अवश्य पढ़ें: समुद्री स्थानिक योजना रूपरेखा

SOURCE:AIR

स्मार्ट 2.0

संदर्भ: हाल ही में, स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- प्रोफेसर (वीडी) रबीनारायण आचार्य, महानिदेशक, सीसीआरएएस के अनुसार, अध्ययन का उद्देश्य बाल कासा, कुपोषण, अपर्याप्त स्तनपान, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, रजोनिवृत्त महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और मधुमेह मेलिटस (डीएम) II के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में सुरक्षा, सहनशीलता और आयुर्वेद फॉर्मूलेशन का पालन करना है।

स्मार्ट 2.0 के बारे में:-

- 'स्मार्ट 2.0' का मतलब शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्यधारा में लाने की गुंजाइश है।
- लॉन्च किया गया: 3 जनवरी, 2024
- लॉन्च किया गया: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM)।
- मंत्रालय: आयुष मंत्रालय
- उद्देश्य: आपसी सहयोग के माध्यम से देश भर में आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों/अस्पतालों के साथ आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं:-

- 'स्मार्ट 2.0' का उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुवाद करने के लिए एक मजबूत सबूत उत्पन्न करना है।
- 'स्मार्ट 1.0' के तहत, 38 कॉलेजों के शिक्षण पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी से लगभग 10 बीमारियों को कवर किया गया।
- इसके तहत, CCRAS और NCISM प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों को लक्षित करने वाले आयुर्वेद फॉर्मूलेशन की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने वाले मजबूत अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से आयुर्वेद कॉलेजों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हैं।
- फोकस के क्षेत्र: प्रारंभिक अनुसंधान में बाल चिकित्सा, महिलाओं का स्वास्थ्य, कुपोषण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ शामिल हैं:-
  - o चाइल्डहुड पोषण: बर्बादी, स्तनपान संबंधी समस्याएं
  - o मासिक धर्म संबंधी समस्याएं: असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव
  - o पोषण: कुपोषण, कैल्शियम की कमी

o जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ: मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस

- सीसीआरएएस बहु-केंद्र परीक्षणों के दौरान वैज्ञानिक इनपुट और परियोजना निगरानी प्रदान करेगा।

अवश्य पढ़ें: डब्ल्यूएचओ और पारंपरिक चिकित्सा

SOURCE:PIB

"पृथ्वीविज्ञान"

संदर्भ: हाल ही में, कैबिनेट ने व्यापक योजना "पृथ्वीविज्ञान (पृथ्वी)" को मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वीविज्ञान (पृथ्वी)" को मंजूरी दे दी है।

पृथ्वीविज्ञान (पृथ्वी) योजना के बारे में:-

- कार्यान्वयन अवधि: 2021-2026 तक
- मंत्रालय:पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

उद्देश्य:-

- पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकनों का विस्तार।
- मौसम, महासागर और जलवायु खतरों की भविष्यवाणी करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास।
- नई घटनाओं और संसाधनों की खोज की दिशा में ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज।
- सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों के दोहन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास।

मुख्य विशेषताएं:-

- इस योजना में पांच चल रही उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात् "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस)", "महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)", "ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पेसर)", "भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (एसएजीई)" और "अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट)"।
- यह अंतर-विषयक परियोजनाओं को शुरू करने और यहां तक कि अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के लिए आवंटित धन का एक साथ उपयोग करने में मदद करेगा। इस प्रकार, इससे अनुसंधान करने में भी आसानी होगी।
- यह मौसम और जलवायु, महासागर, क्रायोस्फीयर, भूकंपीय विज्ञान और सेवाओं की बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और उनके स्थायी दोहन के लिए जीवित और गैर-जीवित संसाधनों का पता लगाएगा।
- महत्व:- यह पृथ्वी प्रणाली के सभी पांच घटकों से संबंधित है: वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, और जीवमंडल, और उनकी जटिल इंटरेक्शन।

अवश्य पढ़ें: गहरे महासागर मिशन

SOURCE: PIB

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना

संदर्भ: हाल ही में, ओडिशा के डेब्रीगढ़, खिंडा को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- इस योजना के तहत डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और खिंडा गांव को पर्यटक और गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के बारे में:-

- मंत्रालय:पर्यटन मंत्रालय
- उद्देश्य: एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की पूर्ण क्षमता का एहसास करना और अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में "स्थानीय के लिए मुखर" को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं:-

- इसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार गंतव्य विकसित करना है और SD2.0 योजना के लिए दिशानिर्देश साझा किए हैं।
- यह योजना 100% केंद्र पोषित है।
- परियोजनाओं को धन की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी किए गए धन के उपयोग आदि के अधीन मंजूरी दी जाती है।
- स्वदेश दर्शन 2.0 स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को बनाने के लिए स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन में बदलने के लिए एक पीढ़ीगत बदलाव है।
- पर्यटकों और गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह टिकाऊ और जिम्मेदार स्थलों के निर्माण में सहायता करेगा।
- यह पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सामान्य और थीम-विशिष्ट बेंचमार्क और मानकों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और राज्य उन बेंचमार्क और मानकों का पालन करेंगे।
- पहचाने गए कुछ प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में झाँसी और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट और खजुराहो और महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा हैं।
    - योजना ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पर्यटन विषयों की पहचान की है: संस्कृति और विरासत का पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको-पर्यटन, कल्याण पर्यटन, एमआईसीई पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन, अंतर्देशीय और महासागर परिभ्रमण।
- महत्व: योजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना है।

अवश्य पढ़ें: स्वदेश दर्शन और प्रसाद के तहत बौद्ध स्थलों का प्रचार

SOURCE:THE NEW INDIAN EXPRESS

अनुभव पुरस्कार योजना 2024

संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने अनुभव पुरस्कार योजना 2024 को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि:-

- अनुभव पोर्टल पर सबमिशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 होगी, सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अनुभव पोर्टल पर सबमिशन करने के लिए पेंशनभोगियों तक पहुंचेंगे।

अनुभव पुरस्कार योजना, 2024 के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2015 में
- मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
- उद्देश्य: अधिक से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने लेख प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा सरकार में काम करते हुए राष्ट्र निर्माण और लिखित आख्यानों के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने में किए गए योगदान को मान्यता देता है।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश पर, DOPPW ने सरकार के साथ काम करते हुए सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए मार्च 2015 में 'अनुभव पोर्टल' नामक एक ऑनलाइन मंच लॉन्च किया।
- योजना में भाग लेने के लिए, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद तक अपना अनुभव राइट-अप जमा करना आवश्यक है।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन के बाद लेख प्रकाशित किए जाएंगे।
- प्रकाशित लेखों को अनुभव पुरस्कार और जूरी प्रमाणपत्र के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

जरूर पढ़ें: पद्म पुरस्कार विजेता शांति देवी

SOURCE:PIB

अटल बिहारी बाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया

संदर्भ: हाल ही में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री ने पोस्ट किया: "अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे नागरिकों के लिए 'जीवन की सुगमता' को बढ़ाने की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पुल यात्रा के समय को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का वादा करता है, जिससे दैनिक आवागमन आसान हो जाता है।"

अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु के बारे में:-

- पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में किया था।
- विजन: शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की 'आवाजाही में आसानी' में सुधार करना।
- यह लगभग 21.8 किमी लंबा 6-लेन पुल भारत का सबसे लंबा पुल होगा और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी होगा।
- यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को कम करेगा।
- इसमें मानसून के दौरान उच्च-वेग वाली हवाओं का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रकाश खंभे हैं और बिजली से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिजली संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है।

अवश्य पढ़ें: चार धाम राजमार्ग

SOURCE:THE ECONOMIC TIMES

अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS)

संदर्भ: हाल ही में, उडुपी स्टेशन को पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) में शामिल किया गया है।

पृष्ठभूमि:-

- रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) नेटवर्क के अंतर्गत है और इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत थी।

अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के बारे में:-

- लॉन्च: अगस्त, 2023
- मंत्रालय: रेल मंत्रालय

उद्देश्य:-

- न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाओं को बढ़ाने और लंबी अवधि में स्टेशन परिसर में रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन करना ।
- फंडिंग की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करना।
- यह योजना मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन के साथ-साथ नई सुविधाओं की शुरूआत को भी पूरा करेगी।

मुख्य विशेषताएं:-

- अमृत भारत स्टेशन योजना में मध्य रेलवे के 76 रेलवे स्टेशनों को उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए लेने की परिकल्पना की गई है और उनमें से 38 स्टेशनों पर आधारशिला रखी जाएगी।
- इसमें प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, लैंडस्केपिंग इत्यादि जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है।
- इस योजना में भवन के सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाजा', चरणबद्धता और व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।
- यह उन स्टेशनों को कवर करेगा जो विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन से गुजर चुके हैं। हालाँकि, इन स्टेशनों में रूफ प्लाजा का निर्माण निकट अवधि में नहीं किया जाएगा क्योंकि संरचनाओं और उपयोगिताओं के पुन: आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।
- यह योजना रेलवे स्टेशनों की जरूरतों और संरक्षण के आधार पर लागू की जाएगी।
- इस योजना के तहत 1,000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

लाभ :-

- आधुनिक यात्री सुविधाएं।
- बेहतर यातायात परिचालन।

- अंतर-मोडल एकीकरण।
- स्थिरता और पर्यावरण-मित्रता।

अवश्य पढ़ें: रेलवे का पुनर्गठन

SOURCE:THE HINDU

प्रसादम

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, 'प्रसादम' का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन, महाकाल लोक में किया गया।

प्रसादम के बारे में:-

- लॉन्च: जनवरी, 2024
- मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- प्रसादम देश के हर कोने में आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा।
- यह प्रयास आम लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित और स्वस्थ खान-पान की आदतों से जोड़ेगा।
- यह देश की पहली "स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट" है।
- यह 19 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।
- प्रसादम प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 1-1.5 लाख भक्तों के लिए सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है।
- फूड स्ट्रीट को बच्चों के खेल क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अवश्य पढ़ें: खजुराहो के मंदिर

SOURCE:PIB

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

संदर्भ: हाल ही में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आठ करोड़ ग्राहकों की उपलब्धि का जश्न मनाया।

पृष्ठभूमि:-

- अपनी स्थापना के बाद से, IPPB देश के हर कोने में सुलभ और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित रहा है।
- आठ करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की यह उल्लेखनीय उपलब्धि भारत के लोगों द्वारा आईपीपीबी पर जताए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाती है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के बारे में:-

- लॉन्च किया गया: वर्ष 2018 में और शासित: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।
- इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था।
- यह भारतीय डाक विभाग का एक भुगतान बैंक है।
- उद्देश्य: भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाना।
- फोकस समूह: आईपीपीबी मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थियों, प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आईपीपीबी के कार्य:-

- यह जमा स्वीकार करता है और प्रेषण सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग और तृतीय-पक्ष फंड हस्तांतरण प्रदान करता है।
- यह 3 प्रकार के बचत खाते प्रदान करता है: नियमित खाता - सफल, मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) - सुगम और बीएसबीडीए

लघु - सरल

- चालू और बचत खातों के लिए जमा की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है।
- बैंक बचत खातों पर 4% ब्याज दर प्रदान करता है।
- ये डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, इससे पैसे उधार नहीं दिए जा सकते।
- यह मनरेगा मजदूरी, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे सामाजिक सुरक्षा भुगतान प्रदान करता है और थर्ड पार्टी की सेवाओं, बीमा और म्यूचुअल फंड तक पहुंच प्रदान करता है।
- आईपीपीबी खाताधारकों को एक अद्वितीय क्यूआर कोड के साथ क्यूआर कोड-आधारित बायोमेट्रिक कार्ड जारी किया जाएगा।

अवश्य पढ़ें:भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

SOURCE:PIB

पीएम-ईबस सेवा योजना

संदर्भ: हाल ही में, पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत ई-बसों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि मंत्रालय ने पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी की हैं और बोली प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

पीएम-ई बस सेवा के बारे में:-

- शुरू : वर्ष 2023 में
- उद्देश्य: सार्वजनिक परिवहन में धीमी गति से चल रही ई-बसों को बढ़ावा देना।
- इसके तहत देश के शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
- इसमें 'केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों' की सभी राजधानियाँ शामिल होंगी।

योजना के खंड:-

- इसके दो खंड हैं - सिटी बस सेवाओं और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल।
- सिटी बस सेवाओं और संबद्ध बुनियादी ढांचे को बढ़ाना: इस खंड के तहत, यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल, बस डिपो और मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे पर 10,000 इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) का विस्तार करके शहर के इलेक्ट्रिक बस संचालन को बढ़ाएगी।
- हरित शहरी गतिशीलता पहल (GUMI): इस खंड के तहत, योजना बस सेवाओं के पूरक और शहरी क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी का प्रदर्शन करने के लिए जीयूएमआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी।

ऑपरेशन मॉडल:-

- सिटी बस परिचालन को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- बस सेवाओं को 10 वर्षों तक समर्थन दिया गया, संचालन और ऑपरेटरों को भुगतान के लिए राज्य/शहर जिम्मेदार थे।

पीएम ई-बस सेवा योजना के लाभ:-

- यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी।
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहरों को समर्थन दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।

अवश्य पढ़ें: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV)

SOURCE:THE HINDU

स्टार्टअप रैंकिंग 2022

संदर्भ: हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में तमिलनाडु को शीर्ष श्रेणी 'बेस्ट परफ़ॉर्मर' के रूप में मान्यता दी गई थी।

पृष्ठभूमि:-

- यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग का चौथा संस्करण था।

स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के बारे में:-

- द्वारा जारी: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)।
- उद्देश्य: स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) का मूल्यांकन करना।
- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी।
- इसका उद्देश्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश नीति हस्तक्षेप की नजर से भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य का मूल्यांकन करना और उन प्रथाओं की पहचान करना है जो पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि और विकास को गति देते हैं।
- राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को समर्पित स्टार्टअप नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है और अपनी वार्षिक रैंकिंग के माध्यम से, यह इन नीतियों के विकास और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रयासों को ट्रैक करने में सक्षम है।

स्टार्टअप रैंकिंग 2022:-

- रैंकिंग ढांचे में 7 सुधार क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कुल 25 कार्य बिंदु हैं, जिसमें 85 अंक और फीडबैक अभ्यास सहित कुल 100 अंक हैं।
- इस संस्करण में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संस्करणों में अधिकतम भागीदारी देखी गई।
- रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी-ए (1 करोड़ से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी-बी (1 करोड़ से कम जनसंख्या) में विभाजित किया गया था।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस - 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण के परिणाम है।

श्रेणी A राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक)

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता: गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना।
- लीडर: आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
- महत्वाकांक्षी लीडर: बिहार, हरियाणा।
- उभरते पारिस्थितिकी तंत्र: छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर।

श्रेणी B राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से कम)

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता: हिमाचल प्रदेश।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।
- लीडर: गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा।
- महत्वाकांक्षी लीडर: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड।
- उभरते पारिस्थितिकी तंत्र: चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम।

जरूर पढ़ें: स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग

SOURCE:BUISINESSLINE

आयुष दीक्षा

संदर्भ: हाल ही में, 'आयुष दीक्षा' के निर्माण का शिलान्यास समारोह 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया।

पृष्ठभूमि:-

- यह समारोह केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (CARI), भरतपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया।

आयुष दीक्षा के बारे में:-

- मंत्रालय:आयुष मंत्रालय
- यह भारत सरकार का केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का मानव संसाधन विकास केंद्र है।

- संस्थान सामान्य रूप से आयुष और विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।
- यह क्षमता विकास, आयुर्वेद में मानव संसाधनों को मजबूत करने, अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने, उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अलावा राजस्व उत्पन्न करने के लिए अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने में भी मदद करेगा।

अवश्य पढ़ें: आयुष मार्क प्रमाणीकरण योजना

SOURCE:PIB

आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब - भीष्म

संदर्भ: हाल ही में, दो आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब-भीष्म को अयोध्या में तैनात किया गया है।

पृष्ठभूमि:-

- आगामी 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के दौरान चिकित्सा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस क्रांतिकारी मोबाइल अस्पतालों को अयोध्या में तैनात किया गया।
- यह "प्रोजेक्ट भीष्म" नाम की व्यापक पहल का हिस्सा है - सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, तेजी से प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर देते हुए 200 हताहतों के इलाज के लिए तैयार की गई है।

आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब के बारे में:-

- यह दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है और इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है।
- मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 वियोज्य मिनी-क्यूब्स (detachable mini-cubes) से बनी है, प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है।
- इसमें एक मिनी-आईसीयू, एक ऑपरेशन थिएटर, एककुकिंग स्टेशन, भोजन, पानी, एक बिजली जनरेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, एक एक्स-रे मशीन और बहुत कुछ जैसे चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति शामिल है।
- यह प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।
- बड़े पैमाने पर हताहत होने की घटनाओं (एमसीआई) के सामने, जहां आवश्यकताएं बुनियादी सहायता से लेकर उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल तक होती हैं, एड क्यूब आश्चर्यजनक 12 मिनट के भीतर तैनात होने की अपनी क्षमता के साथ खड़ा है।
- एयरड्रॉप से लेकर जमीनी परिवहन तक, क्यूब को तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
- उन्नत चिकित्सा उपकरण, कुशल रीपैकेजिंग और पुनः तैनाती के लिए आरएफआईडी-टैग, क्यूब की एक प्रमुख विशेषता है।
- प्रदान किए गए टैबलेट में एकीकृत अत्याधुनिक भीष्म सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेटरों को वस्तुओं का तुरंत पता लगाने, उनके उपयोग और समाप्ति की निगरानी करने तथा बाद की तैनाती के लिए तैयारी सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।

महत्व:-

- यह प्राथमिक देखभाल से निश्चित देखभाल तक महत्वपूर्ण समय अंतराल को प्रभावी ढंग से भरता है, जिससे आपात स्थिति के सही समय में संभावित रूप से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।

MUST READ: Ayushman Bharat PMJAY

SOURCE:PIB

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

संदर्भ: हाल ही में, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के शुभारंभ की घोषणा की।

पृष्ठभूमि:-

- वर्तमान में, भारत में छत पर सौर स्थापना वाले घरों की संख्या का कोई केंद्रीय रूप से संकलित अनुमान नहीं है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में:-

- शुरू: जनवरी, 2024
- उद्देश्य:-सस्ती सौर ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं:-

- यह आवासीय उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर को अपनाने को किफायती बनाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- यह योजना भारत द्वारा मौजूदा रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत 2022 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता के अपने प्रारंभिक लक्ष्य से चूक जाने के बाद आई है।
- नई योजना 2026 की विस्तारित समय सीमा तक 40GW क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए सिरे से प्रोत्साहन का संकेत देती है।
- इस योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्र में भारत की छत पर सौर स्थापित क्षमता का विस्तार करना है।
- उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा निविदा परियोजनाओं के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है।
- डिस्कॉम की भूमिका तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन जारी करने, नेट मीटर की स्थापना और सिस्टम का निरीक्षण करने तक सीमित है।
    - नेट मीटरिंग एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है।
- उत्पादित अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।

लाभ:-

- सौर छत स्थापित करने से घरों के मासिक बिजली बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
- यह 2030 तक 500GW नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का भी समर्थन करेगा।
- यह ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाएगा।

अवश्य पढ़ें: सोलर रूफ टॉप योजना

SOURCE:THE HINDU

'वैभव' फेलोशिप

संदर्भ: हाल ही में, विज्ञान मंत्रालय ने 'वैभव' फ़ेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की।

पृष्ठभूमि:-

- विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह योजना "ओपन-एंडेड" थी और इसका उद्देश्य सार्थक सहयोग की सुविधा प्रदान करना और संभावित रूप से प्रवासी वैज्ञानिकों को भारत में काम करने के लिए आकर्षित करना था।

वैभव फ़ेलोशिप के बारे में:-

- यह NRI शोधकर्ताओं को भारत में किसी शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के साथ साल में न्यूनतम एक महीने से लेकर अधिकतम दो महीने तक काम करने का अवसर प्रदान करता है।
- इसकी अवधि तीन वर्ष है और पूरी अवधि के लिए शोधकर्ताओं को 37 लाख रुपये तक की पेशकश की जाती है।
- **उद्देश्य:** वैभव फेलोशिप का उद्देश्य विदेशी संस्थानों से भारत में संकाय/शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत के उच्च शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।

पात्रता: (वैज्ञानिकों के लिए)

- आवेदक एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) और भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना चाहिए, जो वर्तमान में विदेश में रह रहा हो।
- आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Ph.D./M.D/M.S की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
- आवेदक को शीर्ष 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले अनुसंधान और विकास के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक विदेशी शैक्षणिक / अनुसंधान / औद्योगिक संगठन में कार्यरत शोधकर्ता होना चाहिए।
- भारत में किसी अनुसंधान संस्थान/शैक्षणिक संस्थान में प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने से अधिकतम 2 महीने तक अनुसंधान कार्य करने की योजना बनाएं, जो 3 वर्षों तक विस्तारित रहा हो।

पात्रता: (संस्थानों के लिए)

- उच्च शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय NIRF समग्र रैंकिंग में शीर्ष 200 में स्थान पर हैं और उनके पास NAAC 'ए' ग्रेड (3.0 और ऊपर) और वैज्ञानिक संस्थान हैं।

समर्थन की प्रकृति एवं अवधि:

- यह फेलोशिप केवल भारत में मान्य है और किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में लागू की जाती है।
- मेजबान संस्थान को आवश्यक प्रशासनिक और ढांचागत सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- फ़ेलोशिप 3 साल की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 1-2 महीने के लिए है।

अध्येता नीचे दिए गए अनुसार अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे:

- 5000 अमेरिकी डॉलर की फ़ेलोशिप (समकक्ष भारतीय मुद्रा में)
- अपने संस्थान के स्थान से भारत में कार्यस्थल तक बिजनेस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा
- आकस्मिकता 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष
- शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक वर्ष में दो स्टेशनों तक घरेलू यात्रा

MUST READ:SpaceTech Innovation Network (SpIN)
SOURCE:THE HINDU

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-2022

संदर्भ: हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2021-2022 जारी किया।

पृष्ठभूमि:-

- पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों की कुल संख्या 1,168, कॉलेजों की 45,473 और स्टैंडअलोन संस्थानों की 12,002 है।

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-2022 के बारे में:-

- संचालन: शिक्षा मंत्रालय
- इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी और यह एक वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण है।
- डेटा संग्रह के विभिन्न मापदंडों में शामिल हैं - शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और बुनियादी ढांचा।
- संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक, प्रति छात्र व्यय जैसे संकेतकों की गणना भी एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से की जाएगी।
- महत्व:-शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत निर्णय और अनुसंधान करने में उपयोगी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:-

- उच्च शिक्षा में नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ और 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया (91 लाख छात्रों की वृद्धि, यानी 2014-15 से 26.5%)।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया (50 लाख छात्रों की वृद्धि, 32% की वृद्धि)।
- जीईआर 2014-15 में 23.7 से बढ़कर 2021-22 में 28.4 हो गया; महिला जीईआर 2014-15 में 22.9 से बढ़कर 2021-22 में 28.5 हो गई।
- 2017-18 से लगातार पांचवें वर्ष महिला जीईआर पुरुष जीईआर से अधिक बनी हुई है।
- 2014-15 से अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 44% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। (2014-15 में 46.07 लाख से 2021-22 में 66.23 लाख)
- 2014-15 (16.41 लाख) की तुलना में 2021-22 (27.1 लाख) में एसटी छात्रों के नामांकन में 65.2% की पर्याप्त वृद्धि हुई।
- 2014-15 (1.13 करोड़) से 2021-22 में ओबीसी छात्र नामांकन में 45% की वृद्धि (1.63 करोड़)

- 2014-15 (52.36 लाख) के बाद से 2021-22 में महिला ओबीसी छात्रों में 49.3% की उल्लेखनीय वृद्धि (78.19 लाख)
- कुल पीएचडी नामांकन 2014-15 (1.17 लाख) से 2021-22 (2.13 लाख) में 81.2% बढ़ गया है।

अवश्य पढ़ें: शिक्षा में लैंगिक अंतर

SOURCE:PIB

पीएम यशस्वी योजना

संदर्भ: हाल ही में, पीएम यशस्वी योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 32.44 करोड़ रुपए और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 387.27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य छात्रों को प्री-मैट्रिक से लेकर पोस्ट-सेकेंडरी चरणों तक की पढ़ाई में सहायता करना है।

पीएम यशस्वी - वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के बारे में:-

- मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- उद्देश्य: पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-माध्यमिक चरण में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- टेस्टिंग एजेंसी: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को यशस्वी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- MSJ & E, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन है जो प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में आवेदकों के प्रवेश के लिए कुशल और पारदर्शी मानकीकृत परीक्षण आयोजित करती है।

मुख्य विशेषताएं:-

- यह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है।
- कंपोनेंट्स: -प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, टॉप क्लास स्कूल शिक्षा, टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा, ओबीसी के लिए छात्रावासों का निर्माण।

पात्रता:-

- आवेदक छात्र भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- उम्मीदवार छात्र ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी एसएआर, एनटी या एसएनटी समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे।
- इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
- सभी लिंग के छात्र पीएम यशस्वी योजना 2023 के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे।

चयन:-

- उम्मीदवार छात्रों को कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

लाभ :-

- नौवीं कक्षा के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति वर्ष 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 11वीं कक्षा के छात्रों को प्रति वर्ष 125,000 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

अवश्य पढ़ें: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

SOURCE:HINDUSTAN TIMES

स्पोर्ट्स

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023

संदर्भ: प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चेन्नई, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- श्री मोदी ने प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी लगभग 250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में:-

- इसमें भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट भाग लेंगे।
- लोगो में संत तिरुवल्लुवर की छवि है और शुभंकर वीरा मंगई है।
- यह पहली बार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए जा रहे हैं।
- खेल तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर में खेले जाएंगे।

अवश्य पढ़ें: ग्रैंड स्लैम

SOURCE: THE INDIAN EXPRESS

विविध

विश्व ब्रेल दिवस

संदर्भ: हाल ही में दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया।

पृष्ठभूमि:-

- इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्र देश में कई कार्यक्रम आयोजित किये गए।

विश्व ब्रेल दिवस के बारे में:-

- यह दिन ब्रेल लिपि के दूरदर्शी आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है।
- यह दिन इस बात को मान्यता देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को मानवाधिकारों तक अन्य सभी लोगों की तरह ही पहुंच मिलनी चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 के अंत में विश्व ब्रेल दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया।
- ब्रेल, एक भाषा के बजाय एक सार्वभौमिक कोड है, जो संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं सहित विभिन्न भाषाओं में लिखने और पढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।
    - यह दृष्टिहीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्पर्श द्वारा पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है।
    - इसमें बिंदुओं की व्यवस्था होती है जो वर्णमाला के अक्षर, संख्याएं और विराम चिह्न बनाते हैं।

अवश्य पढ़ें: विकलांगों को सक्षम बनाना

SOURCE:AIR

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

संदर्भ: हाल ही में, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

पृष्ठभूमि:-

- प्रधान मंत्री ने पोस्ट किया "राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं, एक अवसर जो हमारे जीवंत लोकतंत्र का उत्सव मनाता है और लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन भी है, यदि उन्होंने पहले से ही पंजीकरण नहीं कराया है।
  सुबह 11 बजे, मैं नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करूंगा, जो पूरे भारत से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को एक साथ लाएगा।"

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में:-

- हर साल 25 जनवरी को भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है।
- उद्देश्य: देश के प्रत्येक मतदाता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह देश में पहली बार 2011 में मनाया गया था।
- इसके पीछे मुख्य कारण अधिक से अधिक युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था।
- वर्ष 2023 का विषय था "चुनावों को समावेशी, सुलभ और भागीदारीपूर्ण बनाना।"

महत्व:-

- मतदान प्रणाली के पीछे मुख्य महत्व लोगों को यह तय करने की अनुमति देना है कि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कौन शासन करेगा।
- इसका मतलब यह भी है कि लोगों के पास यह चुनने की शक्ति है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी, विचारधारा या नीतियां देश के भविष्य को आकार देंगी।

अवश्य पढ़ें:राष्ट्रीय मतदाता दिवस - वोट की शक्ति

SOURCE:PIB

IAS BABA

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2024

Most Comprehensive Prelims classroom Program

- 1:1 Personal Mentorship
- 400+ Hours of Prelims Focused Classes
- Prelims Exclusive Handouts
- Solve 5000 + MCQ's for PRELIMS 2024
- 125+ Daily Tests & Full Length Tests
- PYQ Classes & CSAT Classes by Prelims Experts
- Current Affairs - Classes, Handouts & Tests

ONLINE & OFFLINE

LIVE

ADMISSIONS OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

MAINS

PAPER 1

महिला नेतृत्व में विकास

GS I – महिलाओं की भूमिका

संदर्भ: हाल ही में भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान समावेशी विकास, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति, पर्यावरण के अनुकूल विकास, तकनीकी नवाचार और बहुपक्षीय संस्थानों के पुनर्गठन के साथ-साथ "महिला नेतृत्व में विकास" को छह केंद्रीय बिंदुओं के रूप में नामित किया।

"महिला नेतृत्व में विकास" से आपका क्या तात्पर्य है?

- महिला-नेतृत्व में विकास के तहत महिलाएँ केवल विकास की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे नेतृत्वकर्त्ता के रूप में विकास का एजेंडा तय करने और विकास योजना के निर्माण तथा निर्णयन में भागीदारी करती हैं।

भारत लैंगिक अंतर को कम करने के लिए प्रयास क्यों कर रहा है?

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 में भारत को 146 देशों में से 127वाँ स्थान दिया गया था और कार्यबल से "महिलाओं के अनुपस्थित होने की" (Missing Women) सार्वकालिक समस्या का सामना करता है, जो एक बड़ी समस्या है।
  जब महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच होती है, तो वे पुरुषों की तुलना में परिवार और समुदायों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अधिक निवेश करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ उन्हें कार्यान्वित किया है। इसमें जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पहल शामिल हैं।
- मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18% तक का इज़ाफा कर सकता है, बशर्ते कि वह देश में महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार कर लैंगिक समानता के अंतर को खत्म करे।

महिला नेतृत्व में विकास को लेकर प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर दुनिया में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले सामने आए, जिनमें से 32,033 मामले बलात्कार के थे।
- कृषि जनगणना से पता चलता है कि 2015-16 में महिला भूमि मालिकों की संख्या केवल 13.9% थी।
- स्थानीय स्तर सहित राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं की अधिक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना एक चुनौती है। भारत की संसद में केवल 82 महिला- लोकसभा में (15.2%) और राज्यसभा में (13%) सदस्य हैं।

महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें

- महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी।
- मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017, जो 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम का संशोधन था, मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर क्रेच सुविधा प्रदान करता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में शिकायत निवारण और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के संबंध में प्रावधान हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करती है।

सशस्त्र बलों में महिलाएं

GS I – महिलाएं

संदर्भ: हाल ही में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के समान मातृत्व, शिशु देखभाल और शिशु गोद लेने की छुट्टियों के नियमों में विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का इतिहास:

- ब्रिटिश भारतीय सेना में महिलाओं को पहली बार 1927 में सैन्य नर्सिंग अधिकारियों के रूप में और 1943 में चिकित्सा अधिकारियों के रूप

में तैनाती के दौरान सैनिकों, परिवारों और जनता की देखभाल के लिए शामिल किया गया था, जिसमें आबादी का महिला वर्ग भी शामिल था।

- वर्ष 1992 में ही सेना, वायु सेना और नौसेना में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू हुआ। यह पहली बार था जब महिलाओं को मेडिकल स्ट्रीम के बाहर सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और अब तक, सेना में 9500 से अधिक महिलाएं हैं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

- मौजूदा समय में महिलाओं को दस में भारतीय सेना में कमीशन दिया जा रहा है।
- भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं को शामिल करना वर्ष 1991 में शुरू हुआ। तब से, भारतीय नौसेना ने धीरे-धीरे महिला अधिकारियों के लिए सभी शाखाएं खोल दी हैं, जिनमें एनडीए के माध्यम से शामिल करना भी शामिल है।
- पहली बार 2022 से अग्निपथ योजना के तहत नाविकों की प्रविष्टियों के लिए महिलाओं की भी भर्ती की जा रही है और 20% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की भर्ती लिंग-तटस्थ है। भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं और धाराओं में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं पर वर्तमान आँकड़े:

- वर्तमान में 9,118 महिलाएं सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवारत हैं।
- भारतीय सेना में केवल 3.8%, वायु सेना में 13% और नौसेना में 6% महिलाएं शामिल हैं।

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के उदाहरण:

- गुंजन सक्सेना एक पूर्व भारतीय वायु सेना अधिकारी हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनीं।
- तानिया शेरगिल 2020 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए भारतीय सेना की सभी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला परेड एडजुटेंट बनीं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने का महत्व:

- सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली महिलाएं लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 में दिए गए समानता के अधिकार को बनाए रखता है।
- मिक्स्ड-जेंडर बल की अनुमति देने से सेना मजबूत रहती है।
- विविध प्रतिभा पूल: सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने से भर्ती पूल बढ़ता है, जिससे अधिक विविध और प्रतिनिधि सेना की अनुमति मिलती है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- पुरुष और महिला दोनों कैदियों को यातना और बलात्कार का खतरा होता है। शत्रु द्वारा महिला युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार को समाजों में कम स्वीकार्यता है।
- सीधी लड़ाई में महिलाओं की सेवा इकाई के मनोबल और एकजुटता को नुकसान पहुंचाकर मिशन की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है क्योंकि जमीन पर एक औसत सैनिक की मानसिकता एक महिला नेता के प्रति विमुख रहती है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के संबंध में वैश्विक रुझान:

- अमेरिकी सशस्त्र बलों में लगभग 200,000 अमेरिकी महिलाएं सक्रिय ड्यूटी पर हैं। वे इसकी शक्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- इज़राइल सशस्त्र बलों में महिलाओं के उच्च प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। वर्ष 2021 तक, इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) में लगभग 33% महिलाएं शामिल हैं, जिनमें वायु सेना, नौसेना और पैदल सेना में लड़ाकू भूमिकाएँ शामिल हैं।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली

GS I – भारतीय संस्कृति: वास्तुकला

संदर्भ: अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है।

वास्तुकला की नागर शैली से आप क्या समझते हैं?

- यह उत्तर भारत में प्रचलित एक मंदिर-शैली की वास्तुकला है जो पांचवीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुई थी।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषताएं:

- ये निर्माण की पंचायतन शैली का पालन करते हैं, जिसमें मुख्य मंदिर के लिए एक क्रूस पर चढ़ाए गए भूमि योजना में सहायक मंदिर शामिल होते हैं।
- गर्भगृह के बाहर, नदी देवी, गंगा और यमुना की छवियां रखी होती है।
- मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के विपरीत, मंदिर परिसर में कोई पानी की टंकी या जलाशय मौजूद नहीं होते हैं।
- मंदिर आमतौर पर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते है।
- शिखर सामान्यतः तीन प्रकार के होते है:
    - लैटिना या रेखा-प्रसाद: ये आधार पर चौकोर होते है और दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु तक अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है।
    - फमसाना (Phamsana): इनका आधार व्यापक होता है और लैटिना लोगों की तुलना में ऊंचाई में छोटे होते है। ये एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर झुके होते हैं।
    - वलभी: इनका आधार आयताकार होता है और छत गुंबददार कक्षों की तरह उठा होता है। इन्हें वैगन-वॉल्टेड छतें भी कहा जाता है।
- शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क में समाप्त होता है, जिसे अमलक के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर एक गोलाकार आकृति रखी होती है जिसे कलश के नाम से जाना जाता है।
- मंदिर के अंदर, दीवार को तीन ऊर्ध्वाधर प्लेन में विभाजित किया जाता है जिन्हें रथ कहा जाता है। इन्हें त्रिरथ मन्दिरों के नाम से जाना जाता है। बाद में, पंचरथ, सप्तरथ और यहां तक कि नवरथ मंदिर भी अस्तित्व में आए।
- द्रविड़ शैली के विपरीत, मंदिर परिसर में विस्तृत सीमा दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते थे।
- वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण: खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा में सूर्य मंदिर, बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और असम में कामाख्या मंदिर।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उप-विद्यालय:

- **ओडिशा स्कूल:** इसकी सबसे प्रमुख विशिष्ट विशेषता शिकारा (देउल) है जो शीर्ष पर अंदर की ओर मुड़ने से पहले लंबवत रूप से ऊपर उठती है। इन मंदिरों के बाहरी हिस्से में जटिल नक्काशी होती है और आमतौर पर आंतरिक भाग खाली होता है। उत्तर के नागर मंदिरों के विपरीत, अधिकांश ओडिशा मंदिरों में चारदीवारी होती है।
- **चंदेल स्कूल:** ओडिशा शैली के विपरीत, इन मंदिरों की कल्पना एक इकाई के रूप में की गई है और इनमें शिकारे हैं जो नीचे से ऊपर तक घुमावदार हैं। मध्य वाले टावर और टावरों से शिकारे के कई लघु चित्र हैं जो धीरे-धीरे पोर्टिको और हॉल दोनों मुख्य टावर कैप तक बढ़ते हैं।
- **सोलंकी स्कूल:** ये चंदेल स्कूल के समान हैं, सिवाय इसके कि उनकी छतें नक्काशीदार हैं जो एक असली गुंबद की तरह दिखाई देती हैं। इन मंदिरों की विशिष्ट विशेषता सूक्ष्म और जटिल सजावटी रूपांकन हैं।

शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन (एबीसीपी)

GS I - भारतीय संस्कृति: बौद्ध धर्म

संदर्भ: हाल ही में, एशिया में बौद्धों के एक स्वैच्छिक जन आंदोलन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस (एबीसीपी) ने नई दिल्ली में अपनी 12वीं महासभा बुलाई।

शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन (एबीसीपी) से आप क्या समझते हैं?

- इसकी स्थापना 1970 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के एक स्वैच्छिक आंदोलन के रूप में मंगोलिया के उलानबटार में गैंडानथेगचेनलिंग मठ में मुख्यालय के साथ की गई थी।
- एबीसीपी तब भारत, मंगोलिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, तत्कालीन यूएसएसआर, वियतनाम, श्रीलंका और दक्षिण और उत्तर कोरिया के बौद्ध गणमान्य व्यक्तियों के एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में उभरा।

एबीसीपी का उद्देश्य:

- एशिया के लोगों के बीच सार्वभौमिक शांति, सद्भाव और सहयोग को मजबूत करने के समर्थन में बौद्धों के प्रयासों को एक साथ लाना और बौद्ध संस्कृति तथा परंपराओं का प्रसार करना।

एबीसीपी की 12वीं महासभा की प्रमुख झलकियाँ:

- विषय था "एबीसीपी - द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ"। यह भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि इसकी G20 अध्यक्षता और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

- बौद्ध सर्किट को विकसित करने और भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र की स्थापना में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

सुशासन के क्षेत्र में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता:

- बुद्ध का सही दृष्टिकोण पर जोर, विकृति और भ्रम से बचना, पारदर्शिता, निष्पक्षता और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के सुशासन सिद्धांतों के साथ संरेखित है।
- बुद्ध के पांच उपदेश - अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार न करना और नशा न करना - की व्याख्या सार्वजनिक अधिकारियों के लिए नैतिक दिशानिर्देशों के रूप में की जा सकती है।
- बुद्ध की करुणा की मूल शिक्षा नेताओं को केवल कुछ समूहों की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की जरूरतों और पीड़ाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सही स्पीच और सही कार्रवाई पर बुद्ध का जोर सम्मानजनक संचार और संघर्ष के अहिंसक समाधान को बढ़ावा देता है जिसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, अंतरधार्मिक संवाद और यहां तक कि आंतरिक राजनीतिक बहस में भी लागू किया जा सकता है।

PAPER 2

शैक्षिक केन्द्रों में आत्महत्या के मामले

GS II – सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

संदर्भ: हाल ही में लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) ने एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें कोटा में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं के चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में छात्र आत्महत्याओं की स्थिति:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI) रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में वर्ष 2021 में प्रतिदिन 35 से अधिक की दर से 13,000 से अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, वर्ष 2020 में 12,526 मृत्यु के साथ 4.5% की वृद्धि हुई, 10,732 आत्महत्याओं में से 864 मामलों में परीक्षा में विफलता ज़िम्मेदार है।

एजुकेशनल हब में छात्र आत्महत्या के मामले बढ़ने के कारण:

States with Higher Percentage Share of Suicides during 2019 to 2021

Sl. No.	Year					
	2019		2020		2021	
1	Maharashtra	(13.6%)	Maharashtra	(13.0%)	Maharashtra	(13.5%)
2	Tamil Nadu	(9.7%)	Tamil Nadu	(11.0%)	Tamil Nadu	(11.5%)
3	West Bengal	(9.1%)	Madhya Pradesh	(9.5%)	Madhya Pradesh	(9.1%)
4	Madhya Pradesh	(9.0%)	West Bengal	(8.6%)	West Bengal	(8.2%)
5	Karnataka	(8.1%)	Karnataka	(8.0%)	Karnataka	(8.0%)

Image Source: PIB

- माता-पिता, शिक्षकों और समाज की उच्च अपेक्षाओं के अनुरूप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिये अत्यधिक तनाव और दबाव इसका कारण बन सकता है। असफल होने का यह दबाव कुछ छात्रों पर भारी पड़ सकता है, जिससे असफलता और निराशा की भावना पैदा होती है।
- अवसाद, चिंता और बाईपोलर विकार जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ छात्रों द्वारा आत्महत्या करने का कारण हो सकती हैं। ये स्थितियाँ तनाव, अकेलापन और समर्थन की कमी से और भी बदतर हो सकती हैं।
- शैक्षिक केंद्रों में कई छात्र दूर-दूर से आते हैं और अपने परिवार तथा दोस्तों से दूर रहते हैं। यह अलगाव और अकेलेपन की भावना को जन्म दे सकता है, जो एक अपरिचित और प्रतिस्पर्द्धी माहौल में विशेष रूप से कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है।

आत्महत्याओं को कम करने हेतु भारतीय पहल:

- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (MHA), 2017: MHA 2017 का उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- किरण (KIRAN): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परेशान लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन "किरण" शुरू की है।
- मनोदर्पण पहल: मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को कोविड-19 के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- वर्ष 2023 में घोषित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग है।

राजद्रोह (SEDITION)

GS II – विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2024 में राजद्रोह से संबंधित धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई किया। विधि आयोग ने अपनी 22वीं रिपोर्ट में आग्रह किया है कि राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की जरूरत है लेकिन इसके उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता

के लिए कुछ संशोधन किए जाने चाहिए।

राजद्रोह क्या है?

- IPC की धारा 124A : यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
- इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
- धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किये गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब इसने अपराध से निपटने के लिये एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की।
- वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
- आईपीसी की धारा 124ए से जुड़े स्वतंत्रता-पूर्व के कई मामले स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ हैं, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी शामिल हैं।

धारा 124ए के तहत सज़ा:

- राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। उसे बिना पासपोर्ट के रहना पद सकता है।
- राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।

राजद्रोह कानून अभी भी क्यों बरकरार है?

- 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट में राजद्रोह पर कानून बनाए रखने के लिए माओवादी उग्रवाद, उग्रवाद आदि सहित भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला दिया गया था। इसने राजद्रोह को अपराध घोषित करने को उचित ठहराया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे प्रतिस्पर्धी न्यायक्षेत्रों की अदालतों का अपना इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, विविधता, कानून आदि हैं। ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं।
- विधि आयोग का कहना है कि आईपीसी की धारा 124ए जैसे प्रावधान के अभाव में, सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर हमेशा विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

राजद्रोह कानून की आलोचनाएँ:

- यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा है।
- सरकार के प्रति असंतोष, दृश्य प्रतिनिधित्व आदि जैसे शब्द अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग के लिए पर्याप्त संभावना प्रदान करते हैं।
- आलोचकों को चुप कराने और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है।

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट:

- केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) ने आईपीसी धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि, अदालत ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का प्रयास किया। अदालत ने माना कि जब तक उकसावे या हिंसा का आह्वान न हो, सरकार की आलोचना को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल नारे लगाना, इस मामले में खालिस्तान जिंदाबाद, देशद्रोह नहीं है।

राजद्रोह कानून पर 22वें विधि आयोग की सिफारिश:

- इसमें केदार नाथ फैसले के अनुपात को राजद्रोह कानून प्रावधान में शामिल करने की सिफारिश की गई। प्रावधान में "हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले" शब्द जोड़े जाने चाहिए।
- यह "हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति" को केवल हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करने का सुझाव देता है। यह परिभाषा इस बात पर बल देती है कि वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे का प्रमाण आवश्यक नहीं है।
- इसमें जेल की अवधि को सात साल या आजीवन कारावास तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):

- यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1860 में लागू किया गया प्राथमिक आपराधिक कोड है, व्यापक कानून जो विभिन्न अपराध, उनकी सजा और अपराध के अभियोजन के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।

भारत में लेखापरीक्षा की भूमिका

GS II – विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ

संदर्भ: वर्ष 2023 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार केंद्र सरकार के खातों पर केवल 18 ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश की गईं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से आप क्या समझते हैं?

- यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) का प्रमुख है। इन दोनों संस्थाओं को सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (SAI) के रूप में जाना जाता है।
- इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- ये छह वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते है।

CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शक्तियां, संघ और राज्य के खातों का स्वरूप और लेखापरीक्षा रिपोर्ट), अनुच्छेद 279 (कुल आय की गणना, आदि), और तीसरी अनुसूची (शपथ या प्रतिज्ञान), और छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन)।

प्रावधान जो CAG के कामकाज के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं:

- वेतन और व्यय भारत की संचित निधि से वसूला जाता है।
- इसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और यह राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त तक पद पर नहीं रहता है, भले ही उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।
- कार्यालय छोड़ने पर, CAG को कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के भीतर किसी भी बाद के पद को धारण करने से रोक दिया जाता है।

भारत में ऑडिट की भूमिका/महत्व:

- ऑडिट जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- ऑडिट त्रुटियों, विसंगतियों, या संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।
- ऑडिट प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करता है, सुधार और लागत-बचत उपायों की अनुमति देता है।
- ऑडिट सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं, बेहतर परिणामों के लिए भविष्य के नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।

एक राष्ट्र-एक चुनाव (ओएनओई)

GS II – शासन के महत्वपूर्ण पहलू

संदर्भ: केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति' की स्थापना की।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से आप क्या समझते हैं?

- यह लोकसभा (भारतीय संसद का निचला सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा विचाराधीन एक प्रस्ताव है।
- इसका इरादा इन चुनावों को एक साथ, एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर कराने का है।

ONOE के लाभ:

- यह सामूहिक निर्णय लेने पर जोर देकर और विभाजनकारी क्षेत्रीय राजनीति को कम करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिकों के बीच साझा राष्ट्रीय पहचान और सामान्य लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है।
- चुनाव प्रक्रिया की आर्थिक दक्षता:विधि आयोग की एक साथ चुनाव संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, ओएनओई जनता का पैसा बचाकर आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देगा। उदाहरण के लिए, 2014 के लोकसभा चुनाव (चार विधानसभा चुनावों के साथ) नौ चरणों में हुए थे और बड़ी संख्या

में सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया था।

- यह सरकार के सेवा वितरण तंत्र में व्यवधानों को कम कर सकता है क्योंकि चुनाव की योजना बनाने और इसकी रणनीति बनाने में काफी समय लगता है। इसके अलावा, चुनावी मौसम के दौरान एमसीसी को बार-बार लागू करने से शासन में बाधा आती है।
- बार-बार होने वाले चुनावों में छिपी हुई और मापने में कठिन सामाजिक और आर्थिक लागत आती है, जिससे प्रशासनिक ढांचे पर दबाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षकों को चुनाव कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्कूल और कॉलेज छोड़ना पड़ता है।
- बार-बार चुनाव से मतदाता थक कर भागीदारी कम कर सकते है। एक समकालिक चुनाव प्रणाली मतदाताओं को फिर से आकर्षित कर सकती है और उच्च मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है।

भारत में ONOE चुनौतियाँ

- संवैधानिक प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को पांच साल तक सीमित करते हैं, यदि केंद्र या राज्य सरकार मध्य कार्यकाल में गिर जाती है तो व्यवहार्यता के मुद्दे उठते हैं।
- ONOE 'संघवाद' की अवधारणा का खंडन करता है, क्योंकि यह भारत के 'राज्यों के संघ' के साथ संरेखित नहीं है।
- प्रमुख पार्टी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज़ से समझौता करती है, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
- बार-बार होने वाले चुनाव लोकतंत्र में फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि वे मतदाताओं को अपनी आवाज़ अधिक बार सुनने की अनुमति देते हैं।
- एक साथ चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की खरीद के लिए अतिरिक्त लागत के साथ पर्याप्त बजट की आवश्यकता होती है।
- ONOE मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ राज्य और लोकसभा दोनों चुनाव जीत सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय पार्टियाँ हाशिए पर चली जाएंगी।

ONOE का वैश्विक स्तर पर अभ्यास:

- दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ पांच साल के लिए होते हैं और नगरपालिका चुनाव दो साल बाद होते हैं।
- ब्रिटेन में, ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता और पूर्वानुमान (predictability) की भावना प्रदान करने के लिए 2011 का निश्चित अवधि संसद अधिनियम पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई, 2015 को होगा और उसके बाद हर पांचवें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा।
- जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67 अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है (पदस्थ को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव करना)।
- स्वीडन में, राष्ट्रीय विधायिका (रिक्सडैग) प्रांतीय विधायिका/काउंटी परिषद (लैंडस्टिंग), और स्थानीय निकायों/नगरपालिका विधानसभाओं (कोमुनफुलमकटीज) के चुनाव हर चौथे वर्ष सितंबर में एक निश्चित तिथि यानी दूसरे रविवार को होते हैं।

भारत-केन्या संबंध

GS II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: केन्या के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ: भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की है।

केन्या कहाँ स्थित है?

- केन्या अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। इसकी जमीनी सीमाएं दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा, उत्तर पश्चिम में दक्षिण सूडान, उत्तर में इथियोपिया और पूर्व में सोमालिया से लगती हैं।

भारत-केन्या संबंधों के विभिन्न पहलू:

ऐतिहासिक संबंध:

- पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों की उपस्थिति 60 ईस्वी में लिखे गए एक प्राचीन यूनानी लेखक द्वारा 'पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी' या लाल सागर की गाइडबुक में दर्ज की गई है।
- भारत ने 1948 में नैरोबी में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका निवासियों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया।
- दिसंबर 1963 में केन्या की स्वतंत्रता के बाद, केन्या की राजधानी नैरोबी में एक उच्चायोग की स्थापना की गई।
- दक्षिण-पूर्वी केन्या के तटीय शहर मोम्बासा में भारत का एक सहायक उच्चायोग है।

भारत-केन्या व्यापार और विकास सहयोग

- भारत-केन्या व्यापार समझौता (1981) और दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) (1989) पर वर्ष 2016 और 2017 में संशोधित

डीटीएए के साथ हस्ताक्षर किए गए।

- भारत केन्या को ऋण और क्रेडिट के माध्यम से विकास सहायता प्रदान करता है, जिसमें 1982 में 50 मिलियन रुपये का ऋण और एक्जिम बैंक द्वारा औद्योगिक विकास बैंक कैपिटल लिमिटेड को क्रेडिट लाइन शामिल है।
- वर्ष 2021 में, भारत ने केन्या को $2.55B का निर्यात किया, जिसमें मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोलियम, पैकेज्ड दवाएं और सेमी-फिनिश्ड आयरन शामिल था।
- केन्या ने 2021 में भारत को 107 मिलियन डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें मुख्य रूप से सूखे फलियां, कार्बोनेट और चाय शामिल हैं।
- भारत केन्या आने वाले पर्यटकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- केन्या और भारत संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, जी-77, जी-15 और क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के सदस्य हैं।
- लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है।
- तुर्काना झील, दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील, ओमो-तुर्काना बेसिन का हिस्सा है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

GS II – भारत और उसके पड़ोस- संबंध

भारत-बांग्लादेश संबंध अवलोकन

- भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हुए इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक संबंधों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से सीमा पार परिवहन और व्यापार में सुधार हुआ है।
- बांग्लादेश भारत से लगभग 2,000 मेगावाट बिजली आयात करता है। 2018 में, रूस, बांग्लादेश और भारत ने बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- वित्तीय सहायता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन किया है और बांग्लादेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
- लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के सफल समाधान से द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) ने सामुदायिक गुणवत्ता में सुधार किया है और संबंधों को बढ़ावा दिया है।
- भारत और बांग्लादेश बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में संलग्न हैं।
- मजबूत सैन्य सहयोग अंतरसंचालनीयता को बढ़ाता है और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में मुद्दे/चुनौतियाँ:

- सीमावर्ती क्षेत्र आतंकवादी घुसपैठ की चपेट में है, विभिन्न चरमपंथी समूह अपना प्रभाव बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) जैसे समूहों की उपस्थिति खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है।
- भारत और बांग्लादेश 54 साझा नदियाँ साझा करते हैं, लेकिन अभी तक केवल दो संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं - गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि। अन्य प्रमुख नदियाँ, जैसे तीस्ता और फेनी, अभी भी बातचीत के दौर में हैं।
- अवैध प्रवासन में शरणार्थी और आर्थिक प्रवासी दोनों शामिल होते हैं, जिससे सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं।
- सीमाओं के पार नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध शिकार और मानव तस्करी के मामले सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को कमजोर करते हैं।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से बांग्लादेश में चीन की भागीदारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता उत्पन्न कर रही है। बांग्लादेश द्वारा चीन के सैन्य उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने का दबाव चुनौतियां उत्पन्न करता है।

बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई):

- यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों में फैले कई देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग पर केंद्रित है।

आगे की राह:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने वाले स्मार्ट सीमा प्रबंधन समाधानों को लागू करना सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करते हुए सीमा पार आंदोलनों को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- अवैध आप्रवासी मुद्दे को हल करने के लिए उन्नत सीमा प्रबंधन और व्यापक आप्रवासन नीतियों की आवश्यकता है।

- भारत और बांग्लादेश को चीन की बढ़ती उपस्थिति और संबंधित चिंताओं को दूर करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रचनात्मक बातचीत करने की आवश्यकता है।

- सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य बल स्थापित करने की आवश्यकता है।

भारत-रूस संबंध

GS II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: रूस के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ: हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक के लिए रूस का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा और दवाओं, फार्मास्युटिकल पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

भारत-रूस संबंध का अवलोकन

ऐतिहासिक संबंध:

- अक्टूबर 2000 में "भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा" के बाद राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति में सहयोग बढ़ाया गया।

राजनीतिक संबंध:

- भारत के प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक बैठक रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
- दो अंतर-सरकारी आयोग - पहला व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर और दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर हर साल मिलते हैं।

परमाणु ऊर्जा:

- शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग में रूस भारत का एक प्रमुख भागीदार है।
- रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है।

सांस्कृतिक संबंध:

- रूसी संस्थानों में भारतीय भाषाएँ, नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद पढ़ाया जाता है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

- उपग्रह प्रक्षेपण और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली सहित बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग।

व्यापारिक संबंध:

- रूस के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020-21 में 8.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

रक्षा संबंध:

- संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल कार्यक्रम, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम, सुखोई Su-30MKI कार्यक्रम, इल्यूशिन/एचएएल सामरिक परिवहन विमान और केए-226टी जुड़वां इंजन उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

आतंकवाद:

- नवंबर 2017 में आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आधारभूत संरचना:

- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परिवहन समय और लागत को कम करना है।

भारत-रूस संबंध के पाँच स्तंभ:

- समान राजनीतिक और रणनीतिक धारणाएँ: भारत और रूस वैश्विक मामलों पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं।
- गहन सैन्य-तकनीकी सहयोग: दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत रहा है।
- मजबूत आर्थिक संबंध: भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरे संबंध: भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया है।
- लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंध: भारत और रूस के लोगों के बीच संबंधों की विशेषता सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ है।

- नमस्ते रूस भारत और रूस के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से

सुविधा प्रदान की जाती है।

- इंद्र भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में भारत और रूस दोनों आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त रूप से हाइड्रोकार्बन का पता लगाने पर सहमत हुए। रूस की "एशिया की धुरी" रणनीति और भारत की मसौदा आर्कटिक नीति दोनों देशों के बीच अभिसरण को प्रदर्शित करती है।
- ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सिस्टम (ग्लोनास) रूस की रेडियो-आधारित वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यह वैश्विक कवरेज और तुलनीय परिशुद्धता के साथ उपयोग में आने वाली दूसरी वैकल्पिक नेविगेशनल प्रणाली है। यह यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और यूरोपीय गैलीलियो सिस्टम के लिए रूस का जवाब है।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा 7,200 किलोमीटर की मल्टी-मोड पारगमन प्रणाली है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ले जाने के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ती है।

PAPER 3

टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली

GS III – अर्थव्यवस्था

संदर्भ: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 में संशोधन की घोषणा की, और परिवर्तनों में टाइम ऑफ डे टैरिफ (टीओडी) प्रावधानों की शुरूआत शामिल थी।

- **इस टैरिफ प्रणाली का अवलोकन**
  - यह पूरे दिन बिजली की कीमतें निर्धारित करने वाले नियमों का सेट है।
  - इसका उद्देश्य अधिकतम मांग वाले घंटों के दौरान उच्च ऊर्जा खपत को हतोत्साहित करना है।
  - यह निर्धारित करता है कि अलग-अलग समय अवधि के आधार पर बिजली कब सस्ती या अधिक महंगी होगी।
  - सौर घंटों के दौरान टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10-20% कम है।
  - 1 अप्रैल 2024 से 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
  - टीओडी टैरिफ सिस्टम के लिए स्मार्ट मीटर एक शर्त है।

भारत में शीर्ष बिजली उत्पादक राज्य:

टीओडी टैरिफ प्रणाली के लाभ

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बेहतर ग्रिड एकीकरण सुनिश्चित करता है।
- नवीकरणीय उत्पादन में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में सुधार।
- उपभोक्ताओं को टैरिफ के अनुसार उनके लोड का प्रबंधन करने के लिए मूल्य संकेत भेजना।
- बिजली ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर एकीकरण की उम्मीद है।

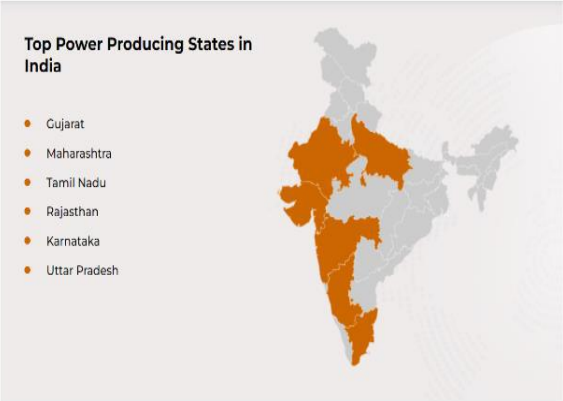

टाइम ऑफ डे (टीओडी) प्रणाली की सीमाएँ:

- इससे बिलिंग में जटिलता बढ़ जाती है क्योंकि उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग समय में उपयोग की निगरानी करनी होती है।
- इसमें व्यवहारिक बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि उपभोक्ताओं को वाहन चार्जिंग या उपकरण के उपयोग में बदलाव जैसी दिनचर्या को अपनाना होगा।
- कुछ उपयोगकर्ता अपनी उपभोग की आदतों को समायोजित नहीं कर सकते हैं जिससे प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
- उच्च मांग वाले घंटों के दौरान अनम्य उपयोगकर्ताओं (Inflexible users) को बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ता है।
- इसकी सफलता पर्याप्त स्मार्ट मीटर तैनाती पर निर्भर करती है; भारत का लक्ष्य 2026 तक 250M का है।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020:

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नियमों को प्रख्यापित किया है।
- यह बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा क्योंकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली पाने का अधिकार है।

कैंसर का पता लगाने और उपचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका

GS III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में इनके अनुप्रयोग और प्रभाव

संदर्भ: मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच), जो भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए बायो-इमेजिंग बैंक की स्थापना करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की ओर रुख कर रहा है।

कैंसर के उपचार में एआई का भविष्य

- एआई से विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रोगी प्रोफाइल के आधार पर उपचार को अनुकूलित करने की उम्मीद है।
- एआई सामान्य चिकित्सकों को एक साधारण क्लिक से जटिल कैंसर का निदान करने में सक्षम कर सकता है, जिससे कैंसर समाधान में सटीकता बढ़ जाएगी।
- एआई समय पर कैंसर का निदान, बेहतर रोगी परिणाम और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए समर्थन का वादा करता है।
- स्वास्थ्य देखभाल में एआई उपकरण मानव रेडियोलॉजिस्ट के संभावित प्रतिस्थापन के बारे में बहस बढ़ाते हैं और नियामक जांच और प्रतिरोध का सामना करते हैं।

कैंसर अवलोकन

- कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है।
- भारत में कुल बीमारी का 40% से अधिक हिस्सा सात कैंसरों का है।
- कैंसर का पता लगाने और उपचार में एआई
- एआई विभिन्न कैंसर से जुड़ी अनूठी विशेषताओं को पहचानने के लिए रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल छवियों का विश्लेषण करता है।
- व्यापक इमेजिंग व्यवहार, उपचार प्रतिक्रिया, रोग पुनरावृत्ति और समग्र अस्तित्व को समझने के लिए अनुदैर्ध्य रोगी डेटा उत्पन्न करती है।
- ट्यूमर छवि बैंक का निर्माण विभिन्न ट्यूमर के लिए एल्गोरिदम के विकास की अनुमति देता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई):

- यह कंप्यूटर या रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आम तौर पर मानव बौद्धिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं।
- बायो-इमेजिंग बैंक अवलोकन
- रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी छवियों का भंडार।
- कैंसर-विशिष्ट प्रारंभिक पहचान एल्गोरिदम के लिए गहन शिक्षण का उपयोग करता है।
- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है।
- यह आईआईटी-बॉम्बे, RGCIRC-नई दिल्ली, एम्स-नई दिल्ली और PGIMER-चंडीगढ़ के साथ सहयोग करता है।
- कार्यों में लिम्फ नोड मेटास्टेसिस स्क्रीनिंग, न्यूक्लियस विभाजन और वर्गीकरण, बायोमार्कर भविष्यवाणी, और थेरेपी प्रतिक्रिया भविष्यवाणी शामिल है।

राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी):

- इसका लक्ष्य भारत भर में कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी समूहों और धर्मार्थ संस्थानों का एक नेटवर्क बनाना है ताकि रोगी देखभाल के समान मानक विकसित किए जा सकें -
  - कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार;
  - ऑन्कोलॉजी में विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना
  - कैंसर में सहयोगात्मक बुनियादी, अनुवादात्मक और नैदानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।
- इसकी स्थापना वर्ष 2012 में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और इसकी अनुदान सहायता संस्था, टाटा मेमोरियल सेंटर के माध्यम से भारत

सरकार की पहल के रूप में की गई थी।

प्रोजेक्ट टाइगर

GS III – वन्यजीवों का संरक्षण

प्रोजेक्ट टाइगर क्या है?

- यह पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, और जलवायु परिवर्तन की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो टाइगर राज्यों को निर्दिष्ट टाइगर रिज़र्व में टाइगर संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
- इसे पहली बार 1 अप्रैल, 1973 में शुरू किया गया था।
- इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा प्रशासित किया गया था।

प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य:

इसका उद्देश्य है:

- अपने प्राकृतिक आवासों में बंगाल टाइगर ('लुप्तप्राय') की एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना,
- इसे विलुप्त होने से बचाना,
- एक प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना जो देश में बाघ की सीमा में पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रोजेक्ट टाइगर: योगदान और चुनौतियां

- देश भर में कई बाघ रिज़र्व स्थापित किए, वर्ष 1973 में नौ से लेकर 2021 में 50 से अधिक।
- ये रिज़र्व बाघों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन और भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देते हैं।
- टाइगर की आबादी काफी हो गई है, अब लगभग 3,682 बाघों के लिए घर, वैश्विक बाघ आबादी के 75% के लिए लेखांकन।
- टाइगर रिज़र्व की लोकप्रियता ने इको-टूरिज्म, स्थानीय रोजगार और संरक्षण जागरूकता में वृद्धि की है।
- कार्बन अनुक्रम और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए टाइगर आवास महत्वपूर्ण हैं।
- चुनौतियों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, बढ़ते समुद्र के स्तर, अपर्याप्त धन और सामुदायिक पुनर्वास के कारण अवैध शिकार, खंडित आवास शामिल हैं।

परियोजना टाइगर की प्रभावशीलता को बढ़ाने के तरीके:

- अलग-अलग बाघों के आवासों को जोड़ने के लिए वन्यजीव गलियारों की स्थापना करके, आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करने और मानव-बाघ संघर्षों को कम करने के लिए निवास स्थान कनेक्टिविटी।
- संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को उलझाने, वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने और वन्यजीवों के कारण नुकसान की भरपाई करके सामुदायिक भागीदारी।
- नियमित टाइगर सेंसर, स्वास्थ्य जांच, और निवास स्थान की गुणवत्ता के आकलन के माध्यम से अनुसंधान और निगरानी फाइन-ट्यून संरक्षण रणनीतियों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

बाघ की सुरक्षा स्थिति:

- अनुसूची I: भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- लुप्तप्राय: प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) लाल सूची
- परिशिष्ट I: जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

भारत के बाघ परिदृश्य:

- शिवलिक हिल्स और गंगा मैदान, मध्य भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट
- उत्तर-पूर्वी हिल्स और ब्रह्मपुत्र मैदान, सुंदरबान।

टाइगर की रक्षा के लिए भारतीय पहल:

- सरकार देश में बाघ की आबादी का अनुमान लगाने के लिए हर चार साल में एक राष्ट्रीय बाघ की जनगणना करती है।
- टाइगर संरक्षण योजना प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए वन्यजीवों (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 वी के तहत अनिवार्य दस्तावेज है, जो उक्त बाघ रिजर्व के लिए प्रबंधन हस्तक्षेप को निर्धारित करता है।

  संरक्षण का आश्वासन | टाइगर मानक (CA | TS) एक व्यापक प्रणाली है जो एकीकृत परिदृश्य योजना के भीतर टाइगर संरक्षण के मौजूदा प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इन प्रयासों से लाभ अनुकूलित हो।
- सरकार ने निर्दिष्ट टाइगर रिज़र्व के बाहर महत्वपूर्ण बाघों के आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व भी स्थापित किए हैं।
- लिडार-आधारित सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग मानव-पशु संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए किया जा रहा है जो जानवरों की मृत्यु का

कारण बन रहा था।

- एम-स्ट्रिप्स (टाइगर्स के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम-गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति) GPS का उपयोग GEOTAG फोटो-अर्थ और टाइगर्स की सर्वेक्षण जानकारी के लिए करता है।
- प्रजातियों के लिए कैमरा ट्रैप तस्वीरों के स्वचालित अलगाव के लिए CaTRAT (कैमरा ट्रैप डेटा रिपॉजिटरी और विश्लेषण उपकरण)।

टाइगर की रक्षा के लिए वैश्विक पहल:

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) की स्थापना 1994 में हुई थी और यह टाइगर संरक्षण के लिए एकमात्र अंतर-सरकारी निकाय है। इसकी सदस्यता में सात टाइगर रेंज देश शामिल हैं: जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल और वियतनाम शामिल है।
- ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (जीटीआई) को 2008 में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के वैश्विक गठबंधन के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि जंगली बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मिलकर काम किया जा सके।
- टाइगर संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 में 13 टाइगर रेंज देशों (टीआरसी) के नेताओं द्वारा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय टाइगर फोरम में इकट्ठे हुए। 13 टाइगर रेंज के देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है।

उद्योग-अकादमिक सहयोग

GS III – औद्योगिक नीति में परिवर्तन

संदर्भ: हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत और जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग (यूआई) लिंकेज सिस्टम' पर मसौदा दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

उद्योग-अकादमिक सहयोग का महत्व और चुनौतियाँ

महत्त्व:

- विश्वविद्यालयों को अनुसंधान का व्यावसायीकरण करने के अवसर प्रदान करता है।
- नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- एक प्रतिभा पाइपलाइन स्थापित करता है, जो भविष्य के पेशेवरों को उद्योग की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।
- संगठनों को व्यावहारिक विशेषज्ञता और शैक्षणिक कठोरता का मिश्रण प्रदान करता है।

चुनौतियाँ:

- उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) सेवा उद्देश्य वाले होते हैं, उद्योग लाभ-संचालित हैं।
- बौद्धिक संपदा गोपनीयता को लेकर एचईआई और उद्योग के बीच विश्वास की कमी है।
- उद्योग उत्पाद विकास को एक टीम प्रयास के रूप में मान्यता देता है, शिक्षा जगत व्यक्तिगत प्रयास को मान्यता देता है।
- HEI सैद्धांतिक ज्ञान और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उद्योग व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चुनौतियों से निपटने के कदम:

- उद्योगों और HEIs के बीच खुला संवाद।
- पारस्परिक रूप से सहमत आईपी व्यवस्था और गैर-प्रकटीकरण समझौतों के लिए संचार चैनल स्थापित करना।
- एचईआई शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को व्यावहारिक अनुशंसाओं में परिष्कृत करना।
- उद्योगों के साथ दीर्घकालिक अनुसंधान सहयोग पर ध्यान देना।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ:
- शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (SPARC) एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।
- उच्चतर आविष्कार योजना (UAY) का उद्देश्य उच्च क्रम के नवाचार को बढ़ावा देना है जो सीधे उद्योग की जरूरतों को प्रभावित करता है और जिससे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार होता है। यह एक व्यवहार्य उद्योग-शैक्षणिक सहयोग पर केंद्रित है जहां उद्योग अनुसंधान की लागत का एक हिस्सा साझा करता है।
- 'भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत और जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज प्रणाली' पर यूजीसी के हालिया मसौदा दिशानिर्देशों में सहयोग के लिए विश्वविद्यालयों में एक उद्योग संबंध सेल (आईआरसी) तथा कंपनियों में एक विश्वविद्यालय संबंध सेल (यूआरसी) के निर्माण का सुझाव दिया गया है।
- इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम (आईआईजीपी) का उद्देश्य भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने के लिए विचार, नवाचार और त्वरण के चरणों के माध्यम से नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को सक्षम करके भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है।

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

GS III – औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव

संदर्भ: भारत ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) में सुधार दिखाया है, जो वर्ष 2014 में अपनी 54वीं रैंकिंग से बढ़कर 2023 में 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंच गया है।

लॉजिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं?

- लॉजिस्टिक्स शब्द में उत्पादन बिंदुओं से लेकर उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, इन्वेंट्री, उपकरण इत्यादि की योजना बनाना, समन्वय करना, भंडारण करना और स्थानांतरित करना शामिल है।
- इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाना और ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता और पहुंच का मूल्यांकन करना शामिल है।

लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) क्या है?

- यह विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है।
- यह विश्वसनीय आपूर्ति चैन कनेक्शन स्थापित करने में आसानी और इसे संभव बनाने वाले संरचनात्मक कारकों को मापता है।
- यह देशों को व्यापार रसद के प्रदर्शन में उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है और वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।
- यह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 6 मापदंडों पर विचार करता है - सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शिपमेंट की व्यवस्था करने में आसानी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, और शिपमेंट की समयबद्धता।

एलपीआई में भारत की स्थिति:

- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023 में भारत छह पायदान ऊपर पहुंच गया है, अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। यह 2018 में 44वें और 2014 में 54वें की पिछली रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण सुधार है।

भारत के रसद प्रदर्शन में सुधार

- पीएम गति शक्ति पहल और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों से लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
- व्यापार-संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश ने भारत के बुनियादी ढांचे के स्कोर को 2018 में 52वें से सुधारकर 2023 में 47वें स्थान पर पहुंचा दिया है।
- प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता मंच, ने देरी को कम कर दिया है।
- भारत का कम प्रवास समय (2.6 दिन) बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को दर्शाता है।

भारत की रसद प्रणाली के मुद्दे

- भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14-18% है, जो वैश्विक बेंचमार्क 8% से अधिक है।
- लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान लगाने में पद्धतिगत चुनौतियाँ मौजूद हैं, यह विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है।
- माल ढुलाई का झुकाव सड़क परिवहन की ओर बहुत अधिक है, जिससे भीड़भाड़, प्रदूषण और रसद लागत में वृद्धि होती है।
- रेलवे, लागत प्रभावी होने के बावजूद, सड़क परिवहन की सुविधा के कारण अधिक लचीले तरीकों के कारण माल ढुलाई हिस्सेदारी खत्म रही है।
- बुनियादी ढांचे की चुनौतियों में आवश्यक टर्मिनल बुनियादी ढांचे की कमी, अनिश्चित वैगन आपूर्ति और सभी मौसम वाली रोड्स की अनुपस्थिति शामिल है।

चंद्रयान-3

GS III – अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता

संदर्भ: वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 मिशन के प्रोपल्शन मॉड्यूल (पीएम) को पृथ्वी की कक्षा में वापस ला दिया है।

चंद्रयान-3 मिशन क्या है?

- चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में इसरो की एंड-टू-एंड क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2 (2019) का अनुवर्ती मिशन है।
- इसमें अंतर-ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल (विक्रम कहा जाता है), और एक रोवर (प्रज्ञान कहा जाता है) शामिल है।

चंद्रयान-3 के उद्देश्य:

- चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना
- चंद्रमा पर रोवर के रोटेटिंग का प्रदर्शन करना
- यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना

चंद्रयान-3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है?

- यह सौर पैनलों द्वारा संचालित चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का एक बॉक्स के आकार का घटक है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लैंडर मॉड्यूल को अंतिम चंद्र ध्रुवीय गोलाकार कक्षा में ले जाना और लैंडर को अलग करना था।

चंद्रयान-3 का महत्व:

- इसने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नेतृत्व प्रदान किया क्योंकि भारत चंद्र सॉफ्ट-लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन करके रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया।
- चंद्रयान-3 द्वारा प्रदर्शित सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता अंतरग्रहीय विज्ञान मिशनों को सक्षम करने वाली मानक ईंधन भरने तथा डॉकिंग तकनीक तक विस्तारित अनुप्रयोगों के साथ भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है।
- मिशन से प्राप्त पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन तकनीक भविष्य के लॉन्च के लिए लागत में कमी लाने में सहायता करती है।
- चंद्रयान-3 में उपयोग की गई प्रौद्योगिकियां रणनीतिक उपकरणों और वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाती हैं जिनका आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की निगरानी में अनुप्रयोग होता है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- भारत का अंतरिक्ष बजट उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.05% है जो अन्य प्रमुख अंतरिक्ष-संबंधी देशों की तुलना में कम है। इसके विपरीत, अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.25% अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए आवंटित करता है।
- भारत प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और घटकों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को रूस से तकनीकी मदद मिलती है।
- वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में नियमित नवाचार, लागत-प्रभावशीलता और समय पर निष्पादन की आवश्यकता होती है।
- भारत को मलबे के उत्पादन को कम करने और अंतरिक्ष मलबे के शमन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता है।
- भारत की अंतरिक्ष विनिर्माण, मानव अंतरिक्ष परिवहन, अंतरिक्ष पर्यटन और उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों में सीमित उपस्थिति है क्योंकि विश्व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 2.6% है।

होहमान ट्रांसफर ऑर्बिट:

- यह एक विशिष्ट कक्षीय पैंतरेबाज़ी है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा दो गोलाकार कक्षाओं के बीच कुशल अंतरग्रहीय यात्रा के लिए किया जाता है, आमतौर पर एक ही केंद्रीय पिंड, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी और मंगल के आसपास।

शिओली क्रेटर:

- यह चंद्रमा की सतह पर लगभग 13.3° S और 25.2° E निर्देशांक पर स्थित एक प्रमुख चंद्र विशेषता है।

Practice Questions

Q1) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए :

पेंटिंग	राज्य
अजंता पेंटिंग	महाराष्ट्र
किशनगढ़ पेंटिंग	राजस्थान
वार्ली पेंटिंग	केरल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q2) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

गौचर रोग का कोई इलाज नहीं है।

कथन-II:

यह एक वंशानुगत लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (एलएसडी) है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q3) वार्ली पेंटिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस आदिवासी कला की उत्पत्ति कर्नाटक में हुई।

2 यह परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता था।

3 इन चित्रों में मुख्य रूप से वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का प्रभुत्व है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

Q4) सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने 1854 में काव्य फुले और 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन किया।

2. 1852 में, सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की।

3. उन्होंने 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 3

Q5) रानी वेलु नचियार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह तमिलनाडु की 18वीं सदी की रानी थी।

2. उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली भारतीय रानी के रूप में इतिहास रचा।

3. तमिल लोगों के बीच, उन्हें प्यार से वीरमंगई के नाम से याद किया जाता है, जिसका अर्थ है "बहादुर महिला।"

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 1

Q6) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

सोमालिया मुख्यतः शुष्क से अर्ध-शुष्क जलवायु का अनुभव करता है।

कथन-II:

अदन की खाड़ी सोमालिया की उत्तरी सीमा बनाती है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q7) यूरेशियन ओटर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केवल नदियों में ही मिलता है।

2. यह केवल यूरोप में पाया जाता है।

3. यह CITES के परिशिष्ट II के अंतर्गत है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) कोई नहीं

Q8) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

मिसाइल	प्रकार
एस्ट्रा	सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल
बराक 8	हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
अग्नि-III	एंटी टैंक मिसाइल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q9) श्रीमुखलिंगम मंदिर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1 इसका निर्माण 19वीं शताब्दी ई. में हुआ था।
2 यह वंशधारा नदी पर स्थित है।
3 यह भगवान विष्णु को समर्पित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2

Q10) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

जनजाति	राज्य
चकमा	असम
अगरिया	छत्तीसगढ़
गद्दीस	केरल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q11) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
कावारत्ती शहर जटिल नक्काशीदार लकड़ी के खंभों के लिए प्रसिद्ध है।
कथन-II:
कावारत्ती में बोली जाने वाली भाषाएँ केवल अंग्रेजी, तमिल और मलयालम हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q12) हाटी समुदाय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हट्टी पुरुष पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों पर एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।
2. वे एक कमजोर जाति व्यवस्था का पालन करते हैं।
3. भट्ट और खश निम्न जातियाँ हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2

Q13) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

योजनाएँ	मंत्रालय
सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्टार्स परियोजना	शिक्षा मंत्रालय
विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q14) बोब्बिली वीणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2001 में इसे भारत सरकार से भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ।
2. इसे 'सरस्वती वीणा' के नाम से भी जाना जाता है।
3. यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा तार वाला वाद्य यंत्र है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल
(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 3

Q15) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

जीआई टैग उत्पाद	राज्य
लांजिया सौरा पेंटिंग	ओडिशा
वांचो लकड़ी शिल्प	त्रिपुरा
अनारदाना	गुजरात

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q16) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान	हिमाचल प्रदेश
केइबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान	असम
साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान	गोवा

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q17) स्वामी विवेकानन्द के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महात्मा गांधी ने विवेकानन्द को "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था।
2. 1893 में, सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर उन्होंने 'विवेकानंद' नाम अपना लिया।
3. उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1

Q18) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए :

योजनाएँ	मंत्रालय
कला उत्सव	संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र	जल शक्ति मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q19) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
कोरापुट काला जीरा चावल कोरापुट जिले के तोल्ला, पात्रापुट, पुजारीपुट, बालीगुडा और मोहुली क्षेत्रों में उगाया जाता है।
कथन-II:
यह चावल की एक गैर-सुगंधित किस्म है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q20) आइंस्टीन प्रोब (Einstein Probe) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे कंबोडिया के ज़िचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था।
2. इसका वजन लगभग 1.45 टन है।
3. ईपी अत्याधुनिक यूवी किरण पहचान तकनीक का उपयोग करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1

Q21) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

जीआई टैग	राज्य
अनारदाना	असम
वांचो लकड़ी शिल्प	मिजोरम
कच्ची खरेक	गुजरात

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q22) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
पिग्मी हॉग	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
कोंडाना रैट	असुरक्षित
एशियाई शेर	कम चिंता जनक

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q23) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार, श्रेणी ए राज्यों में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

कथन-II:

श्रेणी ए राज्यों में बिहार और हरियाणा आकांक्षी लीडर हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q24) जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था।
2. इसका पुनर्निर्माण सदियों बाद गजपति जैसे बाद के शासकों द्वारा किया गया था।
3. यह चार धाम के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

Q25) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

रिपोर्ट	संगठन
तकनीकी सहयोग रिपोर्ट	ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)
विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक	IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी)
वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट (GCR)	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q26) भारतीय सेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय सेना दिवस 2024 का विषय 'राष्ट्र की सेवा में' है।
2. भारतीय सेना का आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' है।
3. 2023 में, यह उत्सव लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 2

Q27) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
जावन गैंडा	कमजोर
वन उल्लू (Forest Owlet)	कम से कम चिंताजनक
टेरापिन नदी	गंभीर रूप से लुप्तप्राय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q28) लांजिया सौरा पेंटिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नवीनतम जनजातीय कला रूपों में से एक है, इसे इडीटल के नाम से भी जाना जाता है।
2. यह कला लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है, जो एक पीवीटीजी है यह मुख्य रूप से रायगड़ा जिले में रहता है।
3. इसमें लाल-मैरून पृष्ठभूमि पर सफेद पेंटिंग की आकृति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 1

Q29) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य
साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क	मणिपुर
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान	अंडमान और निकोबार द्वीप
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान	मेघालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q30)निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
कथन-II:
इसे 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q31) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भारत के प्रधान मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
कथन-II:
यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किए जाते हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q32) श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रमुख मूर्तिकार अरुण योगीराज (मैसूर), गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे हैं।
2. चंद्रकांत सोमपुरा, और उनके दो बेटे - निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा मुख्य वास्तुकार हैं।
3. राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) केवल 3

Q33) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

सरकारी योजना	मंत्रालय
स्टार्स परियोजना	शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	वित्त मंत्रालय
पीएम स्वनिधि	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q34) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य
माउंट हैरियेट	गोवा
नामेरी	असम
वाल्मिकी	बिहार

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q35) पार्किंसंस रोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्सों को प्रभावित करता है।
2. इसके लक्षण तेजी से शुरू होते हैं।
3. उम्र के साथ इसके विकसित होने का जोखिम कम होता जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 3

Q36) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए:

योजना	मंत्रालय
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	रक्षा मंत्रालय
पीएम स्वनिधि	जल शक्ति मंत्रालय
सरल जीवन बीमा	वित्त मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q37) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कथन-I:
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है।
कथन-II:
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को 1994 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q38) पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है।
2. स्व-नामांकन नहीं किया जा सकता।
3. एक वर्ष में दिये जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2

Q39) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
निकोबार व्हाइट-टेल्ड श्रू	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
वन उल्लू	कम से कम चिंताजनक
गंगा शार्क	असुरक्षित

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q40) भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है।
2. डॉ. एस. राधाकृष्णन, सी. राजगोपालाचारी और सी.वी. 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना की गई तो रमन इसके पहले प्राप्तकर्ता थे।
3. भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 3
(D) केवल 1 और 3

Q41) निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए :

बीमारी	के कारण
एंथ्रेक्स	बैसिलस एन्थ्रेसीस
चिकनपॉक्स	नेगलेरिया फाउलेरी
मेनिंगोएन्सेफलाइटिस	वैरीसेला ज़ोस्टर वायरस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q42) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I:
पीएम यशस्वी शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं।
कथन-II:
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को यशस्वी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q43) वेस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक मच्छर जनित संक्रमण है।
2. वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV) टोगाविरिडे परिवार से संबंधित है।
3. यह केवल पश्चिमी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) केवल 1

Q44) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए:

प्रजाति	आईयूसीएन स्थिति
कोंडाना रैट	असुरक्षित
हॉग हिरण	कम से कम चिंता जनक

खरई ऊँट	लुप्तप्राय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q45) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के बाद की गई थी जिसे 15 अप्रैल, 1994 को अनुमोदित किया गया था।

कथन-II:

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते को मराकेश समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q46) हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण 12वीं शताब्दी ई.पू. में हुआ था।
2. इसमें बरामदे से घिरा एक वर्गाकार कक्ष है।
3. यह प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल

Q47) ढेंकनाल मगजी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पनीर से नमी निकालकर और फिर उसे भूनकर, अंत में मिश्रण से गोले बनाकर मिठाई तैयार की जाती है।
2. इसमें अद्वितीय पोषण मूल्य भी होता हैं जो इसे अन्य पनीर आधारित मिठाइयों से अलग करता हैं।
3. यह भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

IAS BABA

P20

Prelims Test Series 2024

20 Tests

- 7 Subject wise Tests
- 3 Current Affairs Tests
- 5 Full Length (GS) Tests
- 5 Full Length (CSAT) Tests

₹1999/-*
+GST

As per latest UPSC pattern

ENGLISH & हिंदी

ADMISSION OPEN

Bengaluru | Delhi | Lucknow | Bhopal

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 9169191888/9019276822